रांची, गुरुवार
20.08.2026
वर्ष : 11, अंक : 258, पृष्ठ : 12
मूल्य : दो रूपए

बिहान भारत

रांची से प्रकाशित हिन्दी दैनिक
खबरें हमारी, विश्वास आपका

website : www.bihanbharat.org | bihanbharat@gmail.com | @bihan_bharat | Bihan Bharat | @bihanbharat | RNI NO - JHAHIN/2015/73988

संक्षिप्त खबरें

वित्त मंत्री सीतारमण मंत्रियों संग सिंगापुर रवाना

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा के लिए प्रस्थान किया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि श्रीमती सीतारमण सिंगापुर में 19-20 अगस्त को होने वाली चौथी भारत-सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंडटेबल (आई एस एम आर) में हिस्सा लेंगी। वित्त मंत्री के साथ इस यात्रा पर गए मंत्रियों के दल में विदेश मंत्री एस. जयशंकर , वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। आईएसएमआर 2022 में शुरू किया गया। यह दोनों देशों के बीच के बीच एक आर्थिक क्षेत्र पर उच्च स्तरीय संवाद का मंच है। यह छह क्षेत्रों–एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, हेल्थकेयर और मेडिसिन, स्किल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी–में हुई प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इस फोरम की इस चौथी बैठक में सहयोग के उपरोक्त क्षेत्रों में हुई प्रगति को आगे बढ़ाने और भारत-सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के नए अवसरों पर विचार किया जाएगा।

जयपुर में दूसरी ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित

जयपुर। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने बुधवार को राजस्थान के जयपुर में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत दूसरी ब्रिक्स 2026 पर्यटन कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी) की बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव भुवनेश कुमार ने की। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भारत की अध्यक्षता के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं पर्यटन, स्थिरता एवं जिम्मेदार पर्यटन, पर्यटन कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण तथा पर्यटन आदान-प्रदान एवं निर्बाध यात्रा सुविधा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक का व्यापक विषय ह्लमजबूती, नवाचार, सहयोग एवं स्थिरता के लिए निर्माणह्व रहा। कार्य समूह ने तकनीकी बदलाव, यात्रियों की बदलती अपेक्षाओं और स्थिरता की आवश्यकताओं के बीच पर्यटन को आर्थिक विकास, रोजगार, सतत विकास और लोगों के बीच आपसी मेल-जोल का महत्वपूर्ण माध्यम माना।

भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, पूल डी में दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल की दौड़ में बरकरार

एजेंसी

अम्स्टेलवीन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 के पूल डी के अपने आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर सेमीफाइनल की दौड़ में खुद को बरकरार रखा। इस जीत के साथ भारत ने छह अंक हासिल किए और पूल डी में दूसरे स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इंग्लैंड तीनों मुकाबले जीतकर पूल में शीर्ष पर रहा, जबकि पाकिस्तान और वेल्स को वर्गीकरण चरण में खेलना होगा।

भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए, जबकि अभिषेक ने भी दो गोल दागे। हार्दिक सिंह ने एक गोल किया। पाकिस्तान के लिए हन्नान शाहिद ने दो और सुफियान खान ने एक गोल किया।

भारत ने शुरूआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए और बाएं छोर से लगातार हमले किए। पांचवें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। हरमनप्रीत का पहला ड्रैग-फ्लिक रशर के पैर से टकराया, जिसके बाद दोबारा पेनल्टी कॉर्नर मिला। कप्तान ने इस बार कोई गलती नहीं की और गेंद को गोलकीपर अली रजा की बाईं ओर भेजकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी।

भारत ने 11वें मिनट में अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। हरमनप्रीत के एरियल पास को अभिषेक ने हासिल किया और उनका प्रयास पाकिस्तान के रक्षकों से डिफ्लेक्ट होकर गोल में चला गया।

दूसरे क्वार्टर में भारत ने 21वें मिनट में तीसरा गोल किया। पेनल्टी कॉर्नर पर हरमनप्रीत ने रणनीति में बदलाव करते हुए राजिंदर को गेंद दी। उनके शॉट को गोलकीपर ने रोका, लेकिन रिबाउंड पर हरमनप्रीत ने गेंद को अपने कब्जे में लेकर शानदार गोल दाग दिया।

पाकिस्तान ने अगले ही मिनट में वापसी की। मिडफील्ड में विवेक सागर प्रसाद से गेंद छीनने के बाद पाकिस्तान ने हमला बोला। भारतीय गोलकीपर ने मोइन शकील के प्रयास को रोक लिया, लेकिन रिबाउंड पर हन्नान शाहिद ने गोल कर स्कोर 1-3 कर दिया।

भारत ने ज्यादा देर नहीं लगाई और 24वें मिनट में अभिषेक ने शानदार गोल करते हुए बढ़त 4-1 कर दी। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर मिला और सुफियान खान ने गोल करके अंतर 4-2 कर दिया। दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने दो-दो गोल किए।

तीसरे क्वार्टर में भारत ने 35वें मिनट में फिर तीन गोल की बढ़त हासिल कर ली। आदित्य को सर्कल के अंदर धक्का दिए जाने पर भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे हार्दिक सिंह ने आसानी से गोल में बदलकर स्कोर 5-2 कर दिया।

पाकिस्तान ने हार नहीं मानी और 46वें मिनट में हन्नान शाहिद ने भारत की मिडफील्ड में हुई गलती का फायदा उठाते हुए अपना दूसरा गोल कर स्कोर 5-3 कर दिया।

आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान ने लगातार दबाव बनाने की कोशिश की और 58वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किया, लेकिन उसकी रणनीति सफल नहीं हुई। भारत ने अंतिम मिनटों में संयम बनाए रखा और 5-3 की शानदार जीत सुनिश्चित की।

इस जीत के साथ भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल कर सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदें कायम रखीं। इंग्लैंड पूल विजेता के रूप में आगे बढ़ा, जबकि पाकिस्तान और वेल्स अब वर्गीकरण चरण में खेलेंगे।

सुरक्षाबलों ने नक्सली डंप से विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा बरामद किया

एजेंसी

सुकमा। सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र अंतर्गत इत्तलंका के जंगल में बुधवार को सुरक्षाबलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया विस्फोटक सामग्री का बड़ा डंप बरामद किया। बरामद सामग्री में जिलेटिन स्टिक, बीजीएल हेड, डेटोनेटर केस, मीटर कॉर्डेक्स वायर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, बीजीएल प्लंजर और अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल है। सुकमा पुलिस अधीक्षक (एसपी) मयंक गुर्जर ने बरामदगी की पुष्टि की है।

पुलिस के अनुसार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार एरिया डोमिनेशन और सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में 18 अगस्त को इत्तलंका के जंगल में नक्सलियों द्वारा सामग्री छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सुकमा एसपी मयंक गुर्जर, 150वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कमांडिंग ऑफिसर राकेश चंद्र शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स) रोहित शाह के समन्वय में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया।

अभियान के लिए एफ/150 बटालियन सीआरपीएफ, क्यूएटी 150 बटालियन सीआरपीएफ और चिंतलनार थाना पुलिस की संयुक्त टीम को रवाना किया गया। टीम ने इत्तलंका गांव से करीब 300 मीटर दूर जंगल में संदिग्ध स्थान की घेराबंदी कर सघन तलाशी ली।

पुलिस के मुताबिक, संभावित आईईडी खतरे को देखते हुए बम डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीएस) की मदद से सुरक्षा मानकों के तहत तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान कपड़े में लिपटा एक संदिग्ध बैग बरामद हुआ। जांच करने पर उसमें नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री और अन्य सामान मिला। बरामद सामग्री में 25 जिलेटिन स्टिक, 16 बीजीएल हेड, 25 डेटोनेटर केस, 12 मीटर कॉर्डेक्स वायर, दो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, छह बीजीएल प्लंजर, पांच मीटर फ्लेक्सिबल वायर, एक चार्जिंग केबल, एक बैटरी कनेक्टर, एक बीजीएल रॉ मटेरियल, एक बेल्ट, तीन रोल वेल्क्रो और एक प्लास्टिक ड्रम शामिल हैं।

अभियान के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद संयुक्त टीम के सभी जवान सुरक्षित रूप से अपने कैंप लौट आए। सुरक्षाबलों ने इलाके में तलाशी और निगरानी अभियान जारी रखा है।

अगले 25 साल तक न बदले लोकसभा की मौजूदा सीटें, 543 सीटों में ही मिले महिलाओं को आरक्षण : कांग्रेस

एजेंसी

नई दिल्ली: कांग्रेस ने परिसीमन को लेकर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या अगले 25 वर्षों तक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए और इन्हीं सीटों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश तथा विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि करीब चार घंटे चली कार्यसमिति की बैठक में 88 सदस्य शामिल हुए और 35 से अधिक सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि युवाओं, पेपर लीक, राम मंदिर के चढ़ावे, जाति जनगणना, देश की सीमाओं की स्थिति, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ 'शुद्धिकरण' वाले व्यवहार और परिसीमन समेत कई विषयों पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ तथा विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए।

वंदे मातरम के मुद्दे पर पूछे गये एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर अपने पुराने रुख पर ही कायम है। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति में पारित प्रस्ताव ही इस विषय पर पार्टी का आधार है। उन्होंने कहा कि उस समय महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, गोविंद बल्लभ पंत सहित कांग्रेस के कई प्रमुख नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि संविधान सभा के अंतिम दौर में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत और जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया था तथा कांग्रेस इस व्यवस्था को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है।

कोलकाता होटल अग्निकांड में मारे गए नौ लोगों में पांच बांग्लादेशी नागरिक

एजेंसी

कोलकाता। कोलकाता के धर्मतला इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल में मंगलवार रात लगी आग में मारे गए नौ लोगों में पांच बांग्लादेशी नागरिकों के होने की जानकारी सामने आई है। कोलकाता स्थित बांग्लादेश उप उच्चायोग के उप उच्चायुक्त मोहम्मद खालिद ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि, कोलकाता पुलिस की ओर से इस संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, मृत पांच बांग्लादेशी नागरिकों में चार कुष्टिया और एक ढाका के सावर इलाके का रहने वाला था। मृतकों की पहचान कुष्टिया निवासी देवाशीष दत्त, शर्णशिष दत्त, अफसाना शिम्मिन, मोहम्मद अकरम अली और ढाका के सावर निवासी अहमद बाबू के रूप में हुई है। इनमें शर्णशिष की उम्र महज तीन वर्ष थी।

जानकारी के अनुसार, देवाशीष दत्त अपनी पत्नी अफसाना शिम्मिन और तीन वर्षीय बेटे शर्णशिष के साथ बेंगलुरु गए थे। बच्चे के इलाज के बाद तीनों मंगलवार को ही कोलकाता पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने धर्मतला के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित शिखा इन होटल में कमरा लिया था। उसी रात होटल में भीषण आग लग गई, जिसमें तीनों की मौत हो गई।

बांग्लादेश उप उच्चायोग के एक अधिकारी ने स्थानीय थाने और मुर्दाघर पहुंचकर मृतकों की पहचान की। स्थानीय पुलिस की सहायता से पांचों की बांग्लादेशी नागरिक के रूप में पहचान की गई। उप उच्चायुक्त मोहम्मद खालिद भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

उल्लेखनीय है कि धर्मतला के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित शिखा इन होटल में मंगलवार रात भीषण आग लग गई थी। आग और धुएं के कारण होटल में फंसे नौ लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। घटना के बाद होटल की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और अन्य अनुमतियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह, इंस्टाग्राम पर बढ़ाएं सक्रियता, युवाओं से सीधे संवाद पर जोर

एजेंसी

नई दिल्ली,। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में केंद्रीय मंत्रियों को सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने की सलाह दी है। खासतौर पर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अधिक मौजूदगी दर्ज कराने और युवाओं से सीधे संवाद स्थापित करने पर जोर दिया।

बैठक में मंत्रियों को केवल ह्यएक्सह्ण तक सीमित न रहते हुए इंस्टाग्राम पर पहुंच बढ़ाने और सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों तथा जनहित से जुड़े कार्यों को रील्स और अन्य रचनात्मक माध्यमों के जरिए युवाओं तक पहुंचाने की सलाह दी गई।

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों की सोशल मीडिया सक्रियता को लेकर विस्तृत आकलन पेश किया गया। मंत्रियों को सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों के आधार पर रैंकिंग दी गई। खास बात यह रही कि मंत्रियों का आकलन केवल एक-दूसरे के मुकाबले नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के शीर्ष नेताओं की सोशल मीडिया पहुंच और प्रभाव के मुकाबले भी किया गया।

यह मूल्यांकन 1 मई से 15 अगस्त 2026 के बीच इंस्टा, एक्स और फेसबुक पर नेताओं की गतिविधियों के आधार पर किया गया। इसमें पोस्ट की संख्या, कुल और औसत एंगेजमेंट, लाइक्स तथा फॉलोअर्स जैसे मानकों को शामिल किया गया। आकलन में प्रधानमंत्री मोदी पहले स्थान पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से संवाद करते रहे हैं। सरकार की कोशिश अब मंत्रियों की डिजिटल मौजूदगी को और प्रभावी बनाकर खासकर युवा वर्ग तक सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी पहुंचाने की है।

वन, वन्यजीव और समुदायों की रक्षा को सफलता का पैमाना बनाएं : उपराष्ट्रपति

एजेंसी

देहरादून। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने वन, वन्यजीव और स्थानीय समुदायों की रक्षा को सफलता का पैमाना बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक वैज्ञानिक वानिकी और भारत के सभ्यतागत ज्ञान का समन्वय सतत भविष्य के निर्माण की कुंजी है।

उपराष्ट्रपति देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए) में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के परिवीक्षार्थियों और प्रशिक्षण ले रहे रॉयल भूटान वन सेवा के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दशकों में इन अधिकारियों पर देश के वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत@2047 की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारतीय वन सेवा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश की पारिस्थितिक सुरक्षा मजबूत करने और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में वन सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

राधाकृष्णन ने अधिकारियों से संरक्षण और विकास, पारिस्थितिक सुरक्षा और आजीविका और वर्तमान आवश्यकताओं और भावी पीढ़ियों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता से अधिक महत्वपूर्ण टीम की उत्कृष्टता है और निरंतर सामूहिक प्रयासों से ही मजबूत संस्थानों और राष्ट्र का निर्माण होता है।

उन्होंने वनों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों के साथ पीढ़ियों से सामंजस्य बनाकर रहने वाले समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाना आवश्यक है।

उपराष्ट्रपति ने लोक सेवा में सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च महत्व देते हुए कहा कि सत्यनिष्ठा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कठिन निर्णय लेते समय संविधान, कानून, विज्ञान और व्यापक जनहित को मार्गदर्शक बनाया जाना चाहिए।

वानिकी क्षेत्र में तकनीक की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने नई पीढ़ी के वन अधिकारियों से रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा आधारित प्रणालियों का उपयोग क्षेत्रीय अनुभव, विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता और जनसंवेदनशीलता के साथ करने का आह्वान किया।

उन्होंने वन सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को उत्साहजनक बदलाव बताते हुए कहा कि वर्तमान बैच में लगभग 17 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसे उन्होंने नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी का प्रमाण बताया।

उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने करियर की सफलता का आकलन केवल पदों के आधार पर न करें। उनके कार्य का वास्तविक मूल्यांकन पुनर्स्थापित किए गए वनों, संरक्षित वन्यजीवों, अर्जित जनविश्वास और भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई विरासत से होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान करते हुए कहा, 'राष्ट्र प्रथम।'

कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आईजीएनएफए के निदेशक डॉ. राजेंद्र प्रसाद, कोर्स निदेशक अजीता लोंगजाम सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

तमिलनाडु के सभी विधायकों को मिलेगा सरकारी वाहन और 75 हजार रुपये मासिक वाहन भत्ता

एजेंसी

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा में बुधवार को अनुदान मांगों पर चर्चा के तीसरे दिन मुख्यमंत्री विजय ने विधायकों और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की। उन्होंने सभी विधायकों को निर्वाचन क्षेत्रों के दौरे और जनसेवा के लिए सरकार की ओर से वाहन उपलब्ध कराने का ऐलान किया। इसके अलावा दूध खरीद मूल्य बढ़ाने, चेन्नई के पेरम्बूर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने, मुख्यमंत्री चिकित्सा बीमा की सीमा बढ़ाने और राज्य में सात नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की।

विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में विधायक अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पहली बार निर्वाचित होने वाले पहली पीढ़ी के विधायकों की संख्या बढ़ी है। आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के बावजूद जनसेवा कर रहे ऐसे विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र में कामकाज सुचारू रूप से संचालित करने में सुविधा देने के लिए सभी विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपनी सहायता के लिए एक सहायक नियुक्त कर सकेंगे। सहायक की नियुक्ति के लिए 25 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन के लिए चालक नियुक्त किया जाएगा। वाहन के ईंधन और रखरखाव के लिए 75 हजार रुपये मासिक वाहन भत्ता दिया जाएगा।

झारखंड में तैयार होगा स्टेट एक्शन फ्रेमवर्क फॉर ड्राउनिंग प्रिवेंशन, डूबने की घटनाओं की होगी निगरानी

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड में नदियों, तालाबों, झरनों, खानों के गड्ढों और पर्यटन स्थलों में डूबने से होने वाली अप्राकृतिक मौतों को लेकर एक गंभीर और स्थायी समाधान की दिशा में पहला राज्यस्तरीय कदम उठाया गया।

बुधवार को होटल चाणक्या बीएनआर में नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सिनी की ओर से वैश्विक सहयोगियों जैसे आरएनएलआई के तकनीकी सहयोग से स्टेट लेवल कंसल्टेशन ऑन ड्राउनिंग प्रिवेंशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस उच्चस्तरीय परामर्श सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्य में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए तैयारी, जोखिम प्रबंधन और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, वन एवं पर्यावरण, शिक्षा और पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधियों के साथ-साथ यूनिसेफ, जेएसएलपीएस, पिरामल फाउंडेशन और सीआईएनआई सहित दर्जनों गैर-सरकारी और विकास संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई।

बैठक के दौरान राज्य में जल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एक विस्तृत रणनीति और 90-दिवसीय कार्य योजना (90-डे प्लान) तैयार करने पर सहमति जताई गई।

समीक्षा के दौरान पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार मई से जुलाई 2025 के बीच राज्य में डूबने से 161 लोगों की जान गई है, जो प्रतिदिन औसतन दो मौतों को दशार्ता है। इस गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए विशेषज्ञों और अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के बाद राहत कार्य चलाने से बेहतर है कि दुर्घटना होने ही न दी जाए। इसके लिए जोखिम वाले हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करने, जल स्त्रोतों को बैरियर लगाकर सुरक्षित बनाने, प्राथमिक बचाव उपकरण तैनात करने और समुदाय को जागरूक करने की जरूरत है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि डूबने से होने वाली मौतें पूरी तरह से रोकी जा सकती है। इसके लिए खास कर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने उच्च जोखिम वाले स्नान घाटों और झरनों पर स्थायी सुरक्षा रस्सियां और बैरियर नेट लगाने का सुझाव दिया, ताकि डूबते व्यक्ति को सहारा मिल सके।

वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीकी ने पर्यावरणीय और नीतिगत दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि झारखंड में ईको-टूरिज्म बढ़ रहा है, ऐसे में पर्यटन से जुड़ी पंचायतों को विशेष ट्रेनिंग देने की सख्त जरूरत है। वन, पर्यावरण और जल निकायों के संरक्षण के साथ-साथ आपदा प्रबंधन की भूमिका तय करना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि हर जगह पुलिस की तैनाती संभव नहीं है, इसलिए सामुदायिक भागीदारी और प्रत्येक विभाग की जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ प्रभात कुमार ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था 'ग्राउंड जीरो' से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि दुर्घटना के बाद केवल अस्पताल पर निर्भर रहना बहुत देर हो जाने जैसा है। सम्मेलन में भारत सरकार, डब्ल्यूएचओ और ब्रिटेन की संस्था आरएनएलआई के विशेषज्ञों ने ऑनलाइन जुड़कर अपने तकनीकी अनुभव साझा किए।

इस अवसर पर एनएचएम की राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अनिमा किस्कू सहित स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन और एनएचएम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

सिल्ली-मुरी में धूमधाम से मनाई गई मनसा पूजा, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु

बिभा संवाददाता

सिल्ली: सिल्ली-मुरी एवं आसपास के क्षेत्र में मंगलवार को मनसा पूजा बड़े उल्लास और आस्था के साथ मनाई गई। नाग पंचमी के बाद मनाई जाने वाली इस पूजा को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। सुबह से ही व्रती महिलाओं और पुरुषों ने उपवास रखकर माँ मनसा की पूजा-अर्चना शुरू की। शाम होते ही गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु निकटतम जलाशयों में जाकर स्नान कर बारी लेकर पहुंचे घरों और मंदिरों में विधि-विधान से माँ मनसा की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना किया गया। कई जगहों पर घरों में ही पारंपरिक तरीके से पूजा की गई, तो वहीं संध्या होते ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मनसा पूजा के अवसर पर बाजारों में भी विशेष रौनक दिखी। पूजा सामग्री के साथ-साथ बत्तख की बिक्री भी खूब रही। मान्यता है कि कुछ स्थानों पर माँ मनसा को प्रसन्न करने के लिए बत्तख की बलि दी जाती है। इसी परंपरा के चलते लोग सुबह से ही बत्तख खरीदते नजर आए। रात तक मंदिरों में विशेष पूजा किया गया। पूजा संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया। महिलाओं ने माँ से सुख-समृद्धि और परिवार की रक्षा की कामना की।

नीमडीह-सोनाहातु के ग्रामीणों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

बिभा संवाददाता

सिल्ली : वन विभाग द्वारा पेशा का उलंघन के खिलाफ नीमडीह,सोनाहातु के ग्रामीणो द्वारा राज्यपाल के समक्ष दिया धरना एवं राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर वन विभाग बुंडू रैंज द्वारा निमडीह ग्रामीणो का रास्ता रोकने पर रोक लगाने, किसानों के खेत एवं पशुओं के चारागाह तक जाने का रास्ता देने तथा पेशा कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन, ग्रामसभा के बिना पेड़ लगाने पर रोक लगाने का मांग किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में किसान नेता उमेश महतो,सोनाहातु मुखिया विकास मुंडा, बसंत मुंडा, चतुर महतो, देवेन्द्र नाथ महतो, परिक्षित महतो,मुकेश महतो,सुखलाल मुंडा, रबिंद्रनाथ मुंडा,लालू लोहरा,राजनाथ महतो, विनोद महतो, विश्व देव महतो ,शोशोधर महतो,दुखी महतो, कुलदीप महतो,अशोक महतो ,अघनु महतो,मखर महतो, प्रदीप महतो,बिसम मुंडा आदि ने संबोधित करते हुए कहा पेशा के उलंघन पर रोक नहीं लगा तो नागरिक आन्दोलन के लिए विवश होंगे। पेशा का उलंघन कर रास्ता एवं चारागाह पर रोक नहीं चलेगा,वन विभाग के मनमानी के खिलाफ संघर्ष तेज करो, ग्रामसभा का उलंघन नहीं चलेगा,लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा आदि नारे लग रहे थे।

संक्षिप्त खबरें

मानसिक रूप से बीमार दो व्यक्तियों को लाया गया अपना घर आश्रम

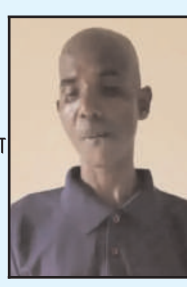

रांची(बिभा)। प्रणामी ट्रस्ट के अंतर्गत पुंदाग में संचालित श्री कृष्ण प्रणामी मंगल राधिका सदानंद सेवा धाम में मंगलवार को दो असहाय और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को रेस्क्यू कर लाया गया। दोनों को सद्गुरु कृपा अपना घर आश्रम में आश्रय दिया गया। इसके साथ ही आश्रम में निराश्रितों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। दोनों व्यक्तियों की आश्रम लाने से पहले अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। उनकी पहचान और पते की जानकारी नहीं मिल सकी। बताया गया कि दोनों अपनी याददाश्त भी खो चुके हैं। आश्रम प्रबंधन ने उनकी पहचान के लिए एक का नाम सुदामा और दूसरे का नाम गोविंद रखा है। रेस्क्यू टीम में सेवा साथी मुकुंद यादव, परमेश्वर प्रमाणिक और सूरज प्रमाणिक शामिल थे। आश्रम के मीडिया प्रभारीसंजय सर्राफ ने बताया कि आश्रम की टीम सूचना मिलने पर समय-समय पर जरूरतमंद और निराश्रित लोगों को रेस्क्यू करती है। यहां उन्हें भोजन, रहने और आवश्यक देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि आश्रम में निराश्रितों को घर जैसा वातावरण देने का प्रयास किया जाता है। पिछले सप्ताह भी एक निराश्रित को आश्रम लाया गया था। आश्रम के उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि आश्रम की टीम को सूचना मिली थी कि रातू के समीप एक असहाय व्यक्ति लावारिस हालत में घूम रहा है। वह काफी अस्वच्छ अवस्था में था। टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रेस्क्यू किया। वहीं दूसरा व्यक्ति एचईसी के शालीमार बाग इलाके में घूम रहा था। उसे भी टीम ने सुरक्षित आश्रम पहुंचाया।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से, परीक्षा केंद्र के पास रहेगी निषेधाज्ञा

रांची(बिभा)। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) नई दिल्ली की ओर से आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2026 को कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची कुमार रजत ने बीएनएस की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। निषेधाज्ञा निर्मला कॉलेज, डोरंडा, रांची स्थित परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में लागू रहेगी। यह आदेश 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त 2026 को सुबह 6 बजे से शाम 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन के अनुसार परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों, उनके अभिभावकों अथवा असामाजिक तत्वों के परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ जुटाकर विधि-व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्र होने पर रोक रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र और लाठी-डंडा, बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम सहित अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पांबदी रहेगी। इसके अलावा किसी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने पर रोक रहेगी। हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा के संबंध में भी आदेश में अपवाद रखा गया है। जिला प्रशासन ने परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों और आम लोगों से प्रशासनिक निदेर्शों का पालन करने की अपील की है।

छात्रों के आंदोलन की समाप्ति पर कांग्रेस ने राहुल गांधी और हेमंत को दी बधाई

रांची(बिभा)। झारखंड में छात्रों के आंदोलन की समाप्ति की घोषणा का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि छात्रों की मांगों और उनकी भावनाओं को गंभीरता से लेते हुए संवाद एवं समाधान का रास्ता अपनाना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को समाप्त कराने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लगातार समर्थन और मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन सरकार की सकारात्मक पहल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके लिए झारखंड के सभी छात्रों की ओर से राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बधाई के पात्र हैं। राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा युवाओं और छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वहीं, राज्य सरकार ने छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी चिंताओं का समाधान निकालने की दिशा में गंभीर पहल की है।

सरला बिरला यूनिवर्सिटी में विश्व फोटोग्राफी दिवस पर 'पिक्सेल स्पंदन 2026' का शानदार आगाज

फोटोग्राफी कला, विज्ञान एवं दर्शन का अद्भुत संगम: डॉ. प्रदीप वर्मा

बिभा संवाददाता

रांची : सरला बिरला विश्वविद्यालय (एसबीयू) में विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर दो दिवसीय फोटोग्राफी कार्यक्रम पिक्सेल स्पंदन 2026 की भव्य शुरूआत हुई। पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय और शटरबग्स क्लब के संयुक्त तत्वावधान में 19 और 20 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में फोटोग्राफी, दृश्य संचार और रचनात्मक अभिव्यक्ति के प्रति रुचि जगाना है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना, शिव शक्ति व जनजातीय नृत्य जैसी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ।

उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने फोटोग्राफी को कला, विज्ञान और दर्शन का अद्भुत संगम बताया। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम करार देते हुए स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का दृष्टांत भी दिया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड के सूचना आयुक्त अनुज कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में एसबीयू के कुलपति प्रो. सी. जगनाथन, महानिदेशक प्रो. गोपाल पाठक, कुलसचिव प्रो. एस. बी. दंडिन और पत्रकारिता डीन प्रो. अजय कुमार ने छात्रों को निरंतर सीखने और अभ्यास के लिए प्रेरित किया। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति बिजय कुमार दलान ने भी आयोजन की सफलता के लिए अपना शुभकामना संदेश प्रेषित किया।

कार्यक्रम के तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को फोटोग्राफी की तकनीकी और व्यावहारिक बारीकियों से अवगत कराया। प्रख्यात फोटोग्राफर कुलदीप सिंह ह्लदीपकह्व ने रील वाले पारंपरिक कैमरों से लेकर आज के स्मार्टफोन और डिजिटल संस्कृति तक के तकनीकी विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं, दिवाकर प्रसाद ने विजुअल स्टोरीटेलिंग के महत्व को समझाते हुए कहा कि एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होती है और उन्होंने सीमित संसाधनों में मोबाइल से बेहतरीन फोटोग्राफी करने की तकनीकें भी सिखाईं। तीसरे तकनीकी सत्र में संजय बोस ने बेहतरीन तस्वीर के लिए फोटोग्राफर की कल्पनाशीलता, विषय के सटीक अवलोकन और सही दृष्टिकोण के महत्व को समझाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अच्छी तस्वीर केवल महंगे उपकरणों की मोहताज नहीं होती, बल्कि इसके लिए रचनात्मक सोच का होना सबसे ज्यादा जरूरी है।

एमआरएचआरयू का शिलान्यास, गंभीर बीमारियों के कारणों की खोज में मिलेगी मदद

बिभा संवाददाता

रांची। राज्य में गंभीर और जटिल बीमारियों के कारणों की पहचान, अनुसंधान एवं बेहतर निदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में डीपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च (डीएचआर) की ओर से मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट (एमआरएचआरयू) का शिलान्यास अनगड़ा, रांची में बुधवार को किया गया।

इस अवसर पर विधायक राजेश कच्छप और केंद्रीय स्वास्थ्य उप सचिव धरकत आर लुईकांग ने यूनिट का शिलान्यास किया।

यह मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गंभीर एवं जटिल बीमारियों के कारणों की वैज्ञानिक खोज, रोगों की पहचान तथा निदान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह यूनिट मल्टीगडिसिप्लीननरी रिसर्च यूनिट, रिम्सी, रांची के साथ मिलकर विभिन्न रोगों से संबंधित अनुसंधान एवं वैज्ञानिक अध्ययन को आगे बढ़ाएगा। इस सहयोग के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान कर उनके कारणों और संभावित जोखिम कारकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकेगा। इससे रोगों के समय पर निदान, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और भविष्य में प्रभावी रोकथाम एवं उपचार की रणनीति विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से झारखंड की ग्रामीण एवं जनजातीय आबादी को इस पहल का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है।

कार्यक्रम में डॉ अनुप अन्विकर, निदेशक, एनआईएमआर, नई दिल्ली, डॉ प्रवीण कुमार भारती, निदेशक, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीदच्यूहट, जबलपुर, डॉ प्रवीण कुमार त्रिपाठी, नोडल ऑफिसर, एमआरएचआरयू, नामकुम, डॉ लखन माझी, डॉ शिशिर कुमार महतो तथा डॉ अंजनी कुमार, रिम्सं, डॉ दिनेश सहित अन्य गणमान्य एवं स्वास्थ्य तथा अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ उपस्थित थे।

करमचंद भगत कॉलेज में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का हुआ स्वागत

बिभा संवाददाता

बेड़ो। करमचंद भगत कॉलेज, बेड़ो में सत्र 2026-30 के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के अभिनंदन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नए छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी ने की। प्राचार्य ने नवागंतुक विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा, आप कॉलेज के साथ दो कदम चलें, हम आपके साथ चार कदम चलेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व, बेहतर भविष्य की तैयारी और अनुशासन के प्रति जागरूक किया। साथ ही नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. नेहा टोप्पो ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. रितेश सिंह ने किया। समारोह में डॉ. ब्रह्मानंद साहू, अभिनीत तिर्की, डॉ. संतोष कुमार भगत, अरविंद राणा बिलुंग, डॉ. मीना पूर्ति, धीरज उरांव, प्रवीण दास, डॉ. साधना कुमारी, डॉ. सवार्णी चक्रवर्ती, डॉ. स्मिता गुप्ता, उम्मे कुलसुम, डॉ. सुजाता बाला, डॉ. प्रमिला उरांव, डॉ. अल्पना मेहता, निरु कुमारी, सुनीता उरांव, डॉ. जे.डी. राम, डॉ. बदीउज्जमाँ, साईनाथ एवं अजय कुमार सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवप्रवेशी विद्यार्थियों का कॉलेज परिवार में आत्मीय स्वागत करना तथा उन्हें शिक्षा, अनुशासन और उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित करना रहा। समारोह के दौरान कॉलेज परिसर में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला।

छात्रवृत्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

बेड़ो: करमचंद भगत महाविद्यालय में बुधवार को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से छात्रवृत्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. प्रसनजीत मुखर्जी ने की। इस दौरान फाउंडेशन के प्रतिनिधि राहुल और गोबिंद ने छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों और सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया। छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और अपने सवाल पूछकर छात्रवृत्ति से जुड़ी शंकाओं का समाधान किया। प्राचार्य डॉ. मुखर्जी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति सशक्त बनाते हैं। इस मौके पर डॉ. ब्रह्मानंद साहू, अभिनीत तिर्की समेत कॉलेज के कई शिक्षक-शिक्षिकाएं और सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल और रद्द परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच कराएं मुख्यमंत्री : बाबूलाल

बिभा संवाददाता

रांची। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को पत्र लिखकर जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल एवं रद्द की गई परीक्षाओं में अनियमिताओं की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आज जो अविश्वास, आक्रोश और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके लिए काफी हद तक जेएसएससी सीजीएल प्रकरण में सीआईडी द्वारा की गई दोषपूर्ण एवं संदिग्ध जांच जिम्मेदार है। आखिर सरकार किसे संरक्षण देना चाहती है, जो सीबीआई जांच से भाग रही है। इसलिए युवाओं के भविष्य और राज्यहित को प्राथमिकता देते हुए सभी मामलों की सीबीआई से जांच आवश्यक है।

नेता प्रतिपक्ष ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए 8 मांग मुख्यमंत्री से किया है। इनमें जेएसएससी सीजीएल परीक्षा घोटाले की जांच अविलंब सीबीआई से कराने, जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित सभी अनियमितताओं की जाँच भी सीबीआई से कराने, सरकार की ओर से रद्द की गई सभी 22 परीक्षाओं एवं संदेह के घेरे में सभी 17 परीक्षाओं, परिणामओं और नियुक्तियों की जांच सीआईडी के स्थान पर सीबीआई अथवा किसी अन्य स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराने, साक्षात्कार बोर्ड में शामिल रहे सभी सदस्यों एवं अधिकारियों के बयान दर्ज कर उनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने, साक्षात्कार बोर्ड के गठन, अभ्यर्थियों के आवंटन तथा कथित कोडिंग-डिकोडिंग से संबंधित समस्त अभिलेख, डिजिटल डेटा और अन्य साक्ष्य तत्काल सुरक्षित करने, सीजीएल जांच के दौरान अभ्यर्थियों से कथित अवैध वसूली और दोषियों को बचाने में शामिल सीआईडी पदाधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने, जिन अधिकारियों की भूमिका स्वयं संदेह के दायरे में है, उन्हें इन प्रकरणों की जांच से हटाने और सीजीएल प्रकरण में दोषपूर्ण जाँच करने, साक्ष्य दबाने तथा वास्तविक दोषियों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग शामिल है।

बंधू तिर्की ने नौ लाभुकों के बीच किया 510 चूजों का वितरण

बिभा संवाददाता

रांची। कृषि और पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के प्रयास से बुधवार को चान्हो प्रखंड में योजना के तहत 09 लाभुकों के बीच 510 चूजों का वितरण किया।

इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने लाभुकों के बीच चूजों का वितरण किया। उन्होंने चूजे सौंपते हुए पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। उन्होंने लाभुकों से योजना का बेहतर लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार और आय का अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने में ऐसी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर अधिकारियों ने लाभुकों को योजना के तहत उपलब्ध कराई गई सुविधा का उचित उपयोग करने की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण कुमार, अंचल अधिकारी संजीव कुमार, उत्क्रमित पशुपालन पदाधिकारी डॉ सुसवी, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ हरविंदर पाल भगत, इरशाद खान, इश्तियाक अंसारी सहित अन्य अधिकारी सहित अन्य मौजूद थे।

साल के अंत तक रिम्स के सभी टीचिंग पद भरने का लक्ष्य : अजय सिंह

बिभा संवाददाता

रांची। रिम्स में चिकित्सकों और कर्मियों की कमी दूर करने के लिए साल 2026 के अंत तक सभी आवश्यक टीचिंग पदों को भरने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई रिम्स सेलेक्शन कमेटी की बैठक में मानव संसाधन की स्थिति और रिक्त पदों की विस्तृत समीक्षा के बाद अजय सिंह ने यह निर्देश दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा, ताकि वर्ष के अंत तक आवश्यक टीचिंग पद भरे जा सकें। मौके पर रिम्स में एचएमआईएस को 100 प्रतिशत लागू करने पर भी जोर दिया गया। सभी विभागों में इसका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों को दी गई। बैठक में रिम्स में कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मियों की संख्या, सृजित पदों और विभिन्न विभागों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने पर जोर दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने विभागवार आवश्यकता के आधार पर पदों का रेशनलाइजेशन करते हुए मानव संसाधन ढांचे को रिस्ट्रक्चर करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी पदों की आवश्यकता का आकलन कर संबंधित प्रस्ताव संचिका के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य टीचिंग पदों के अलावा एएनएम, जीएनएम एवं अन्य कर्मियों के पदों पर भी चर्चा हुई। पदोन्नति के लिए स्पष्ट और पारदर्शी मानदंड निर्धारित कर उसका ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अपर सचिव शशि प्रकाश, रिम्स निदेशक डॉ. डीके सिंह सहित विभाग और रिम्स के कई अधिकारी मौजूद थे।

भाजपा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह से की मुलाकात, मिला मार्गदर्शन

बिभा संवाददाता

रांची। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड भाजपा का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से बुधवार को मुलाकात की।

इस दौरान झारखंड के कई सम-सामयिक विषयों पर गृह मंत्री से सार्थक चर्चा हुई। गृह मंत्री की ओर से भाजपा नेताओं को कई आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपाई सोरेन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय, दीपक प्रकाश और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल थे।

संक्षिप्त खबरें

बकरी बाजार में शिव परिवार व हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न, 5000 लोगों ने ग्रहण किया महाप्रसाद

रांची(बिभा) : राजधानी रांची के बकरी बाजार स्थित मंदिर में भारतीय युवक संघ द्वारा आयोजित छह दिवसीय 'दुर्गेश्वर महादेव' और 'दक्षिणमुखी बालाजी' का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह बुधवार (19 अगस्त) को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मंदिर के नवनिर्मित स्वरूप का अनावरण किया गया, जहाँ अब मां भगवती के साथ संपूर्ण शिव परिवार और महाबली हनुमान जी भी विराजमान हो गए हैं। संघ के प्रवक्ता अमित बजाज ने बताया कि अनुष्ठान के सकुशल संपन्न होने के उपलक्ष्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5000 श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इस पूरे कार्यक्रम और भंडारे की व्यवस्था को सफल बनाने में अध्यक्ष राहुल अग्रवाल, सचिव रवि रोहतगी, संयोजक अमित सोनी, दीपक गोयंका, सचिन मोतीका सहित संघ के अन्य सभी सदस्यों की अहम भूमिका रही।

अबुआ अधिकार मंच ने बी.एड. का रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग की

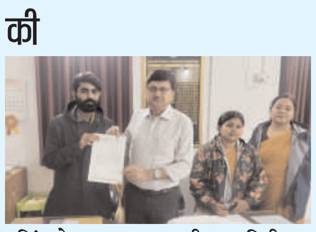

रांची(बिभा): अबुआ अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने संयोजक विपिन कुमार यादव के नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर बी.एड. द्वितीय वर्ष (सत्र 2024-26) का रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग की है। छात्रों ने चिंता जताते हुए कहा कि रिजल्ट में देरी के कारण वे 31 अगस्त 2026 तक चलने वाले बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा और अन्य आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन से वंचित रह जाएंगे, जिससे उनका पूरा एक साल बर्बाद हो सकता है। छात्रों की इस गंभीर समस्या पर परीक्षा नियंत्रक ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए जल्द ही रिजल्ट जारी करने की बात कही है।

छात्र आंदोलन खत्म होने पर कांग्रेस का भाजपा पर निशाना: 'राजनीतिक दुकानदारी' हुई बंद

रांची(बिभा) : झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति ने छात्र आंदोलन की समाप्ति का स्वागत करते हुए कहा कि इसके साथ ही भाजपा की 'राजनीतिक दुकानदारी' भी बंद हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजनीतिक स्वार्थ और राज्य सरकार को अस्थिर करने की नीयत से छात्रों को भड़काने व आंदोलन को हाईजैक करने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि, छात्रों के शांतिपूर्ण रवैये और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा परीक्षा रद्द करने तथा सीआईडी व रिटायर्ड जज से जांच कराने जैसे त्वरित छात्र-हितैषी फैसलों के कारण भाजपा अपने मंसूबों में पूरी तरह नाकाम रही। कांग्रेस ने पूर्व सीएम रघुवर दास के दावों को भी 'चोर की दाढ़ी में तिनका' करार देते हुए कहा कि उनके शासनकाल में भी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई होंगी, जिसे अब छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

रांची(बिभा)। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में 15 वर्षीया नाबालिग से दुष्कर्म का मामला बुधवार को प्रकाश में आया है। घटना के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने पर पीड़िता को रिम्स में भर्ती कराया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 35 वर्षीय गुरुदयाल मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पीड़िता के घर अक्सर आता-जाता था। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

एचईसी की स्थिति सुधारने रांची पहुंची केंद्रीय संसदीय कमेटी की टीम, 20 को करेगी प्लांट का निरीक्षण

रांची(बिभा)। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से केंद्रीय संसदीय कमेटी की छह सदस्यीय टीम बुधवार को रांची पहुंची। टीम का नेतृत्व सांसद तिरुचि शिवा कर रहे हैं।। इसमें चार सांसदों के अलावा एचईसी के निदेशक-अध्यक्ष और भेल के ज्वाइंट सेक्रेटरी शामिल हैं। टीम फिलहाल रांची के एक होटल में ठहरी हुई है। एचईसी के मान्यता प्राप्त यूनियन के महामंत्री लीलाधर सिंह ने बताया कि गुरुवार को संसदीय टीम के सदस्य सबसे पहले एचईसी परिसर में सलामी लेंगे। इसके बाद पौधरोपण कार्यक्रम होगा। टीम एचईसी के विभिन्न प्लांटों का निरीक्षण कर उत्पादन क्षमता, वर्तमान स्थिति और अन्य गतिविधियों की जानकारी लेगी। उन्होंने बताया कि संसदीय टीम एचईसी से जुड़े विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों पर विचार-विमर्श करेगी। इसके बाद लंच के बाद एचईसी प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। बैठक में कंपनी की आर्थिक स्थिति, उत्पादन, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों और पुनरुत्थान की संभावनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। लीलाधर सिंह ने कहा कि एचईसी के कर्मचारी और यूनियन लंबे समय से ऐसी पहल का इंतजार कर रहे थे।

जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों ने निकाला आभार यात्रा, मनाई खुशी

बिभा संवाददाता

रांची। जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच की ओर से छात्रों ने जेपीएससी-जेएसएससी सीजीएल सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चलाए गए आंदोलन के बाद बुधवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा निकाली गई।

इस यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए। सबों ने एक दूसरे पर अबीर-गुलाल लगाकर और आतिशबाजी कर खुशी मनाई। आभार यात्रा के दौरान देवेंद्रनाथ महतो सहित अन्य छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा और शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया।

अभियान के दौरान छात्रों ने एक पोस्टर निकाली जिसमें 45 आयोजित परीक्षाओं में 22 परीक्षाएं रद्द, 17 परीक्षाओं की जांच और छह परीक्षाओं को स्थगित करने से संबंधित बातें लिखी हुई थी।

इस पोस्टर को लहराते हुए मंच ने इसे झारखंड के छात्र आंदोलन की महत्वपूर्ण सफलता बताते हुए कहा कि भविष्य में पेपर लीक और नौकरियों की खरीद-फरोख्त जैसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की मांग की। मंच ने कहा कि इस सफलता के पीछे दो जुलाई 2026 से 47 दिनों का संघर्ष, पांच जुलाई से 44 दिनों का आंदोलन, 25 जुलाई 2026 से 24 दिनों का सत्याग्रह और दो अगस्त 2026 से 16 दिनों की भूख हड़ताल शामिल रही।

जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से उम्मे हबीबा, रूपेश कुमार, राहुल कुमार क्रांति, सबिता कुमारी, छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो, महेन्द्र मंडल प्रसाद सहित अन्य छात्र भूख हड़ताल में शामिल हुए थे। मंच ने कहा कि छात्रों की एकजुटता और लोकतांत्रिक तरीके से किए गए लंबे संघर्ष से यह सफलता मिली है। छात्रों ने भविष्य में भी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग दोहराई।

आरटीई के तहत ऑनलाइन लॉटरी में 35 स्कूलों में 89 बच्चों का चयन

बिभा संवाददाता

रांची। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए रांची जिले में दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी बुधवार को संपन्न हुई। उप विकास आयुक्त संजय कुमार भगत की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में आयोजित लॉटरी प्रक्रिया में 35 निजी स्कूलों के लिए 89 बच्चों का चयन किया गया।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई गई। वर्ष 2026-27 के दूसरे चरण में नामांकन के लिए कुल 224 आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच और सत्यापन के बाद सभी 224 आवेदनों को ऑनलाइन लॉटरी के लिए योग्य पाया गया।

जिले के 39 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध 183 सीटों पर चयन प्रक्रिया की गई। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 35 विद्यालयों में 89 बच्चों का चयन हुआ। चयनित बच्चों को संबंधित स्कूलों में बिना किसी शुल्क के नामांकन मिलेगा और कक्षा आठवीं तक की शिक्षा निःशुल्क होगी।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित स्कूलों को चयनित बच्चों का नामांकन एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।

पहले और दूसरे चरण को मिलाकर अब तक आरटीई के तहत कुल 722 सीटों पर नामांकन सुनिश्चित किया गया है। प्रशासन ने कहा कि आरटीई के प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रहेगा।

लॉटरी के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, सहायक जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रीमा कुजूर, एडीपीओ सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मी मौजूद थे।

नौकरी जाने से नाराज सीजीएल अभ्यर्थी जबरन घुसे प्रोजेक्ट भवन में, किया प्रदर्शन

बिभा संवाददाता

रांची। राज्य सरकार की ओर से सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले से नाराज सफल अभ्यर्थियों का आक्रोश बुधवार को उस समय बढ़ गया, जब उन्हें प्रोजेक्ट भवन के अंदर जाने से रोक दिया गया। भारी बारिश के बीच आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने जबरन प्रोजेक्ट भवन परिसर में प्रवेश कर नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने और समझाने का प्रयास किया, लेकिन बड़ी संख्या में आंदोलनकारी सचिवालय परिसर के अंदर पहुंच गए।

प्रदर्शन के दौरान कई आंदोलनकारी भावुक होकर एक-दूसरे से लिपटकर रोते नजर आए। उनका कहना था कि जिस कार्यालय में वे कल तक काम कर रहे थे, उसी कार्यालय से उन्हें बाहर होना पड़ा है।

इस अवसर पर अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा रद्द होने के फैसले से उनकी नौकरी चली गई और वे अचानक बेरोजगार हो गए।

मौके पर पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों को सचिवालय परिसर खाली करने की चेतावनी दी। डीएसपी नीरज कुमार ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यहां प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। उन्होंने चेतावनी दी कि परिसर खाली नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मौके पर झारखंड मंत्रालय में कार्यरत रहीं प्रिया ने कहा कि सरकार ने बिना उचित प्रक्रिया के सीजीएल परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया, जिससे दो हजार से अधिक कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी न्यायिक रास्ता अपनाएंगे और सरकार से फैसला वापस लेने की मांग करते हैं। पूजा लकड़ा ने कहा कि परीक्षा रद्द करने की भी निर्धारित प्रक्रिया होती है। उन्होंने सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की।

दीनबंधु दुबे ने कहा कि अभ्यर्थी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। मंत्रालय के बाहर टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण बारिश में खुले में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि फैसला वापस नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस दौरान सचिवालय प्रशासन आंदोलनकारियों को समझाने में जुटा रहा।

विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में उभरते आयाम विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन 21 अगस्त से

बिभा संवाददाता

रांची: रांची विश्वविद्यालय (आरयू) के भौतिकी विभाग और झारखंड सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 21 और 22 अगस्त को एक भव्य दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आरयू के आर्यभट्ट सभागार में होने वाला यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम महान भौतिकविद् श्रोडिंगर द्वारा खोजे गए 'श्रोडिंगर समीकरण' (1926-2026) के 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित किया जा रहा है।

इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर के लगभग 300 से अधिक प्रमुख भौतिकी व अभियंत्रण प्राध्यापक और रिसर्च स्कॉलर जुटेंगे। इस दौरान 100 से ज्यादा शोध पत्र (रिसर्च पेपर) प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के उभरते आयामों पर विस्तृत चर्चा के लिए प्रो. जी.पी. दास (कोलकाता), प्रो. कमल प्रसाद (भागलपुर), डॉ. रितेश कुमार केसरी (नागपुर), प्रो. विनय कुमार (दिल्ली), प्रो. विनीत कुमार राय (धनबाद) और डॉ. धर्मेंद्र सिंह (रांची) जैसे कई दिग्गज शिक्षाविद बतौर मुख्य वक्ता अपने विचार साझा करेंगे। सम्मेलन के दौरान उद्घाटन सत्र, तकनीकी सत्र, पेपर एवं पोस्टर प्रस्तुति और समापन सत्र का आयोजन किया जाएगा।

इस वृहद कार्यक्रम की सफलता को लेकर भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक अहम तैयारी बैठक भी संपन्न हुई। इस सम्मेलन के संरक्षक आरयू की कुलपति डॉ. सरोज शर्मा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार और तकनीकी विभाग के निदेशक जॉर्ज कुमार हैं। वहीं, डॉ. सुनील कुमार सिंह इसके जेनरल चेयर और डॉ. राज कुमार सिंह कन्वेनर की भूमिका निभा रहे हैं। श्रोडिंगर समीकरण का पूरे विश्व में जो ऐतिहासिक महत्व है, उसे देखते हुए यह राष्ट्रीय सम्मेलन आज के वैज्ञानिक दौर में बेहद प्रासंगिक माना जा रहा है।

राष्ट्रीय मंत्री बनने पर डॉ. प्रदीप वर्मा का रांची में जोरदार अभिनंदन, कार्यकताओं में उत्साह

बिभा संवाददाता

रांची। झारखंड से राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा को भाजपा की राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय मंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व दिए जाने के बाद बुधवार को रांची आगमन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य एवं जोरदार स्वागत किया।

भाजपा रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक वाद्ययंत्रों, ढोल-नगाड़ों एवं पुष्पमालाओं के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों के साथ अपने नेता का स्वागत किया।

स्वागत से अभिभूत नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं एवं भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना भारतीय जनता पार्टी की उस कार्यसंस्कृति का प्रमाण है, जहां कार्यकर्ता की निष्ठा, परिश्रम और समर्पण का सम्मान होता है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास उन पर जताया है, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे।

डॉ. वर्मा ने कहा कि ‌भाजपा मेरे लिए केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विचार और परिवार है। संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उसमें अपना हर पल पार्टी और संगठन को मजबूत करने में लगाऊंगा। झारखंड के कार्यकर्ताओं की आवाज और आकांक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर तक मजबूती से पहुंचाना भी मेरी प्राथमिकता होगी।

राष्ट्रीय मंत्री ने झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार और घोटालों का बोलबाला है। राज्य की जनता बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है और युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाएं युवाओं के भविष्य का आधार होती हैं। जेपीएससी , जेएसएससी- सीजीएल सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और अनियमितता सामने आना बेहद गंभीर विषय है।

डॉ. वर्मा ने कहा कि झारखंड के नौजवान वर्षों तक मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनके माता-पिता अपनी जमा-पूंजी लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जब परीक्षा में गड़बड़ी होती है, परीक्षा रद्द होती है या पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आती है, तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि हजारों युवाओं के वर्षों की मेहनत, समय और सपने बर्बाद होते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार की कार्यप्रणाली से राज्य के युवाओं में लगातार निराशा बढ़ रही है। छात्र और युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। सरकार को युवाओं की आवाज दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

पूर्व रेलवे

खुली निविदा सूचना सं.: 50-एसडीएसटीई-एएसएन-2026-27, दिनांक 18.08.2026, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता, पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, आसनसोल, पिन-713301 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: **कार्य का नाम/स्थान:** "आसनसोल मंडल - निम्नलिखित कार्य के संबंध में दूरसंचार कार्य (1) आसनसोल मंडल: एईएन/बीआरएल/आसनसोल के अंतर्गत खाना-आसनसोल खंड के बीच अप और डाउन डीएसपी लाइन पर पुल सं. 9 और 9ए के तटबंध की रिगर्डिंग व मजबूती एवं अन्य सहायक कार्य (2) डीईएन/4/आसनसोल के अंतर्गत अंडाल में पुल सं. 20 के लिए पीएससी गर्डर का प्रतिस्थापन और नवीनीकरण, सुरक्षा एवं अन्य सहायक कार्य। (3) एईएन/बीआरएल/आसनसोल खंड में एससीएन1-तापसी के बीच पुल सं. 3 के अन्य सहायक कार्यों के साथ बीजीएमएल गर्डर का प्रतिस्थापन, जैकेटिंग और सुरक्षा कार्य"। **निविदा मूल्य:** रु. 58,17,656.36, **बयाना राशि:** रु. 1,16,400/-, **कार्य की समापन अवधि:** एलओए जारी करने की तिथि से 18 माह। **निविदा बंद होने की तिथि और समय:** 10.09.2026 को 14.00 बजे। **वेबसाइट का विवरण:** http://www. ireps.gov.in/

ASN-224/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

बोकारो में दूसरे राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आगाज, राज्यपाल ने किया उद्घाटन

बिभा संवाददाता

बोकारो। बोकारो में आयोजित एनटीपीसी के दूसरे राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का बुधवार को भव्य आगाज हुआ। 18 से 27 अगस्त तक चलने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट का उद्घाटन 19 अगस्त को झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। प्रतियोगिता में देशभर से तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं, जिससे बोकारो में खेल का माहौल पूरी तरह उत्साहपूर्ण बना हुआ है।

आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में पूरे भारत से करीब 900 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें लगभग 600 खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। प्रतियोगिता में अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित खिलाड़ी भी बोकारो पहुंचे हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के नामचीन तीरंदाजों की मौजूदगी से प्रतियोगिता का स्तर और रोमांच दोनों बढ़ गया है।

यह टूर्नामेंट मोहान कुमार मंगलम स्टेडियम, सेक्टर-4, बोकारो में आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में तीरंदाजों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। तीन प्रमुख कैटेगरी में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे खिलाड़ी पदक और राष्ट्रीय रैंकिंग में बेहतर स्थान हासिल करने के लिए निशाना साध रहे हैं।

उद्घाटन समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से झारखंड में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दीं।

बोकारो में पहली बार इतने बड़े स्तर पर तीरंदाजी के राष्ट्रीय खिलाड़ियों के जुटने से खेल प्रेमियों में भी खासा उत्साह है। प्रतियोगिता के आगामी दिनों में देश के शीर्ष तीरंदाजों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।

नकली विदेशी शराब का मुख्य सरगना गिरफ्तार, 6 माह से था फरार

बिभा संवाददाता

गोमिया (बोकारो) : चतरोचट्टी थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली विदेशी शराब के निर्माण और कारोबार के मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हजारीबाग जिले के आंगो थाना क्षेत्र अंतर्गत बेडम गांव निवासी 33 वर्षीय संतोष महतो के रूप में हुई है। वह पिछले छह महीने से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। बेरमो अनुमंडल डीएसपी रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे उसके घर से दबोच कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि इसी वर्ष होली पर्व के मद्देनजर 22 फरवरी 2026 को अवैध शराब के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के नरकंडी गांव में सोना महतो के मकान में छापेमारी कर विभिन्न ब्रांड की 2688 बोतल नकली विदेशी शराब बरामद की गई थी। उस वक्त मकान मालिक सोना महतो को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अनुसंधान में यह बात सामने आई थी कि इस पूरे अवैध कारोबार का मुख्य निर्माणकर्ता संतोष महतो ही है। घटना के बाद से ही वह गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा था।

पुलिस के अनुसार, इस मुख्य सरगना का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। आरोपी संतोष महतो के खिलाफ पहले से ही विष्णुगढ़, आंगो और चतरोचट्टी थानों में कई संगीन मामले दर्ज हैं। उसे पकड़ने गई इस सफल छापेमारी टीम में चतरोचट्टी थाने के एसआई अनुप रंजन बाखला सहित कई आरक्षी और पुलिसकर्मी शामिल थे, जिनकी तत्परता से यह गिरफ्तारी संभव हो सकी।

नावाडीह डकैतीकांड का फरार आरोपी गिरफ्तार

बिभा संवाददाता

नावाडीह (बोकारो)। नावाडीह थाना क्षेत्र के बिरनी गांव में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे एक और अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र स्थित खरखरी बस्ती निवासी मुस्ताक शेख उर्फ मोहम्मद मुस्ताक (26) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे 19 अगस्त 2026 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

जानकारी के अनुसार, बिरनी गांव निवासी धनेश्वर साहू (47), पिता स्व. तेजलाल साहू, के लिखित आवेदन पर नावाडीह थाना कांड संख्या 57/2025 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में अज्ञात 8-10 अपराधियों पर 18 अगस्त 2025 की रात करीब एक बजे घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करने, हथियार का भय दिखाने तथा जेवरात और नकदी लूटने का आरोप लगाया गया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस के अनुसार, अनुसंधान के दौरान इस कांड में सात अप्राथमिकी अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। वहीं, मुस्ताक शेख उर्फ मोहम्मद मुस्ताक घटना के बाद से फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध न्यायालय से इस्तेहार भी निर्गत किया गया था। अनुसंधान के क्रम में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

छापेमारी दल में अमित कुमार सोनी, पुलिस अवर निरीक्षक सह थाना प्रभारी, नावाडीह थाना,राहुल कुमार राम, पुलिस अवर निरीक्षक,आरक्षी शेख मोहम्मद शोहराब शामिल थे। गिरफ्तार । आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

संक्षिप्त खबरें

बारिश में बह गया पुल का संपर्क पथ, बेरिकेडिंग की मांग

बोकारो(बिभा): चंदनकियारी क्षेत्र के सबड़ा से उदलबनी को जोड़ने वाली दरहा जोड़िया पुल की संपर्क सड़क के किनारे मिट्टी धंसने से दोनों ओर गहरी खाई बन गई है। दिनोंदिन खाई का दायरा बढ़ने से हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल बेरिकेडिंग कराने के साथ सड़क की मरम्मत की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार, करीब एक वर्ष पहले बनी इस सड़क के किनारे गार्डवाल का निर्माण नहीं किया गया है। बारिश के बाद मिट्टी धंसने से सड़क के किनारे गहरी खाई बन गई। समय रहते मरम्मत नहीं होने पर सड़क का और हिस्सा धंसने की आशंका है। यह सड़क सबड़ा मोड़ से उदलबनी, आसनबनी और मामरकुदर होते हुए चास-तालगड़िया मुख्य पथ के धानडाबर को जोड़ती है। साथ ही इलेक्ट्रोस्टील जाने का भी प्रमुख मार्ग है। इस रास्ते से आसनबनी, मधुनियां, उदलबनी और मोदीडीह के ग्रामीणों, छात्र-छात्राओं तथा इलेक्ट्रोस्टील के मजदूरों का प्रतिदिन आवागमन होता है। छोटे बच्चे भी साइकिल से इसी मार्ग से स्कूल आते-जाते हैं। प्रशासन को दुर्घटना का इंतजार किए बिना तत्काल बेरिकेडिंग, मरम्मत और आवश्यक स्थानों पर गार्डवाल का निर्माण कराना चाहिए।

जीएम दौरा से पूर्व डीआरएम ने बोकारो रेलवे में विकास कार्यों का किया निरीक्षण

बोकारो(बिभा) : दक्षिण पूर्व रेलवे आद्रा डिविजन के डीआरएम मुकेश कुमार गुप्ता ने बुधवार को बोकारो रेलवे क्षेत्र का निरीक्षण किया. अपनी टीम के साथ बोकारो पहुंचे मंडल प्रबंधक ने बोकारो रेलवे स्टेशन के पैनल रुम, नवनिर्मित यात्री प्रतीक्षालय आदि का जायजा लिया. इस दौरान डीआरएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को ससमय सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही डीआरएम ने आउट यार्ड, इलेक्ट्रिक शेड सहित अन्य कार्य स्थलों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली. बता दें कि 21 अगस्त को दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम का दौरा होना है, जिसकी तैयारी को लेकर डीआरएम ने बोकारो क्षेत्र का निरीक्षण किया.

बोकारो ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष बने अशोक यादव, मो. अलाउद्दीन महासचिव व मनोज सिंह कोषाध्यक्ष

बोकारो (बिभा): बोकारो रेलवे स्टेशन परिसर स्थित बोकारो ऑटो रिक्शा चालक संघ का चुनाव बुधवार को संपन्न हो गया. इस चुनाव में 159 में से 145 मतदाताओं ने मतदान किया. सुबह 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया आरंभ हुई, जो अपराह्न 3 बजे तक चली. शाम को मतगणना का काम पूरा हुआ. इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर अशोक यादव 76 वोट पाकर विजय हुए. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी मनोज कुमार वर्मा को 62 तथा जाफिर अंसारी को 5 वोट मिला. वहीं, महासचिव पद पर चालकों ने एकबार फिर मोहम्मद अलाउद्दीन विजय रहे. उन्हें 108 वोट मिला, जबकि चंद्रशेखर गुप्ता को 38 वोट मिला. जबकि मनोज कुमार सिंह कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए. नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने चालकों के हित में काम करने की बात कही. कहा कि जिस भरोसे से यहां के चालक साथियों ने जिम्मेदारी सौंपी है, उसे पूरी इमानदारी से निर्वाह करूंगा. इस दौरान निर्वाचन पदाधिकारी सहित समस्त चालक उपस्थित थे.

हजारी पंचायतआरटीआई में खुली आरओ खरीद की पोल, जांच की मांग

बिभा संवाददाता

गोमिया। हजारी पंचायत में आरओ मशीन की खरीद को लेकर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, खुदगड्डा स्कूल में मशीन लगाने के नाम पर 1 लाख 49 हजार रुपये खर्च दिखाए गए। वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि ऐसी मशीन 50-65 हजार में ही मिल जाती है। पंचायत निवासी आमोद प्रजापति ने पूरे मामले की जांच की मांग की है।

पंचायत निवासी आमोद प्रजापति ने आरटीआई के माध्यम से पंचायत में कराए गए कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त की। इसमें आरओ मशीन की खरीद का बिल भी शामिल है। आमोद के अनुसार, स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक दुकानदारों से जानकारी लेने पर मशीन की कीमत करीब 50 से 65 हजार रुपये बताई गई।

आरोप है कि मशीन की फिटिंग के लिए 15 हजार रुपये और पाइप व निपल्स के नाम पर भी 15 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। दुकानदारों के अनुसार सामान्य फिटिंग का खर्च करीब दो हजार रुपये होता है। खास बात यह है कि भुगतान के बावजूद मशीन अब तक स्कूल में स्थापित नहीं की गई है।

आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार, मशीन का बिल कटरा स्थित एक दुकान का है। स्कूल से दुकान की दूरी करीब चार किलोमीटर है। इसके बावजूद परिवहन शुल्क के रूप में 3,500 रुपये का भुगतान दशार्या गया है, जबकि स्थानीय स्तर पर 500 से 600 रुपये में सामान पहुंचाने की बात सामने आई है।

आमोद प्रजापति ने मामले की जांच की मांग करते हुए पंचायत के अन्य कार्यों में भी वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। मुखिया तारामणि देवी से पक्ष जानने के लिए फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया।

चास पुलिस को मिली बड़ी सफलताः रात में घरों की खिड़की तोड़ने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 शातिर चोर गिरफ्तार

बिभा संवाददाता

बोकारो/चासः बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने रात के अंधेरे में घरों की खिड़कियां तोड़कर जेवरात, नकदी और मोबाइल चुराने वाले गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी निशानदेही पर चोरी का काफी सामान भी बरामद किया गया है।

गौरतलब है कि चास इलाके में 22 जुलाई, 11 अगस्त और 15 अगस्त 2026 की रात को अलग-अलग घरों में चोरी की वारदातें हुई थीं। इसे लेकर चास थाने में तीन अलग-अलग मामले (कांड संख्या 94/2026, 102/2026 और 103/2026) दर्ज किए गए थे। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए बोकारो एसपी के निर्देश पर एएसपी (सदर) वेदांत शंकर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन छह आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस की पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अम्बेदकरपुरी निवासी गौतम बाउरी उर्फ मिरीण्डा व राहुल कुमार बाउरी, तारानगर निवासी रवि कुमार पाण्डेय, प्रिंस कुमार उर्फ कृष व अमन राज और शिवशक्ति नगर निवासी कृष्णा कुमार पॉल शामिल हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर सोने जैसे 7 कंगन, 3.50 ग्राम गला हुआ धातु का टुकड़ा, ताला/खिड़की तोड़ने में इस्तेमाल होने वाला लोहे का एक चापड़, एक छोटी वजन तौलने वाली मशीन, 7 मोबाइल फोन और कुछ नकदी बरामद की है। इनमें मुख्य आरोपी गौतम बाउरी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ 2021 में भी चोरी के दो मामले दर्ज हो चुके हैं।

इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाले छापामारी दल में एएसपी वेदांत शंकर के साथ चास थाना प्रभारी दिनेश कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक संदीप कुमार, अजीत कुमार, मुकेश दयाल सिंह, रवि शंकर समेत रिजर्व गार्ड और तकनीकी शाखा की टीम शामिल थी। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और चोरी गए अन्य सामानों की भी तलाश की जा रही है।

हंसलता में बाल विवाह के खिलाफ चला जागरूकता अभियान

बिभा संवाददाता

कसमार (बोकारो): कसमार प्रखंड के दांतू पंचायत स्थित राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय हंसलता में बुधवार को सहयोगिनी संस्था के द्वारा बाल विवाह को लेकर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, शिक्षकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर मे प्रभारी प्रधानाध्यापक अध्यापक फिरोज आलम ने बाल विवाह के गंभीर दुष्परिणामों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह न केवल एक कानूनी और सामाजिक अपराध है, बल्कि यह बच्चों (विशेषकर बालिकाओं) के मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। कम उम्र में विवाह से किशोरियों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है और वे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। कार्यक्रम के दौरान संस्था द्वारा बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। संस्था के विकास कुमार में बताया कि यदि क्षेत्र में कहीं भी बाल विवाह कराने का प्रयास किया जा रहा हो, तो उसकी सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या आपातकालीन सेवा 112 पर दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाती है। उन्होंने बताया कि जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में बाल विवाह, बाल तस्करी तथा बाल यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए सघन रूप से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बोकारो जिले में सहयोगिनी इस विषय पर लगातार जागरूकता का कार्य कर रही है। इस मौके सहायक शिक्षक उमेश कुमार महतो, कामदेव चंद्रपाल, चंद्र नारायण महतो, राजेश कुमार, संतोष कुमार महतो एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष परमेश्वर महतो मुख्य रूप से मौजूद थे।

थाना दिवस से 292 मामलों का त्वरित निपटारा

बिभा संवाददाता

बोकारो। आम लोगों की जमीन, राजस्व, पारिवारिक और अन्य स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले में प्रत्येक गुरुवार थाना व ओपी स्तर पर थाना दिवस का आयोजन किया जा रहा है. नौ जुलाई से 13 अगस्त तक 42 थाना व ओपी में चार थाना दिवस आयोजित हुए. इस दौरान कुल 372 शिकायतें पहुंचीं, जिनमें 292 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया. 69 मामले लंबित हैं, जबकि 11 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी.

थाना दिवस में पहुंचने वाली शिकायतों में भूमि विवाद, जमीन बंटवारा, स्वामित्व, निर्माण कार्य रोकने, राजस्व और आपसी विवाद से जुड़े मामले सबसे अधिक रहे. गोमिया थाना में तीन भूमि विवाद पहुंचे. इनमें एक मामले का समाधान किया गया, जबकि जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण दो मामले लंबित रहे.पुलिस का प्रयास है कि छोटे विवादों को शुरूआती स्तर पर ही बातचीत और आपसी सहमति से सुलझाया जाये, ताकि विवाद आगे बढ़कर मुकदमेबाजी में न बदलें. इससे लोगों को भी राहत मिलती है और न्यायालय पर अनावश्यक मुकदमों का बोझ कम करने में मदद मिलती है.

चार थाना दिवस में 372 शिकायतें

09 जुलाई : 103 शिकायतें आयीं, जिनमें 84 मामलों का निपटारा किया गया. 10 मामले लंबित रहे और नौ मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी.

16 जुलाई : 70 शिकायतों में 54 मामलों का निपटारा हुआ. 15 मामले न्यायालय में लंबित रहने के कारण निष्पादित नहीं हो सके. एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी.

30 जुलाई : 113 शिकायतों में 84 मामलों का निपटारा किया गया. 29 मामले लंबित रहे और एक मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई.

13 अगस्त : 86 शिकायतों में 70 मामलों का निपटारा हुआ. 15 मामले लंबित रहे और एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी.

एसपी नाथू सिंह मीणा ने कहा कि थाना दिवस का उद्देश्य केवल लोगों की समस्याओं का समाधान करना नहीं, बल्कि उन्हें कानूनी पहलुओं के प्रति जागरूक करना भी है. इसके माध्यम से सामाजिक समरसता बढ़ाने और छोटे-छोटे विवादों को समय रहते सुलझाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिले के 42 थाना व ओपी क्षेत्रों में लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि लोग विवादों को बढ़ाने के बजाय शुरूआती स्तर पर ही उसका समाधान कर सकें.

वास्तु विहार में देवर-भाभी पर रॉड से हमला, दोनों घायल, पुलिस ने जांच शुरू की

बिभा संवाददाता

बोकारो । शहर के वास्तु विहार में बुधवार को एक जानलेवा घटना की जानकारी मिली है, जिसमें दो व्यक्तियों देवर और भाभी पर कुछ युवकों ने रॉड से हमला कर दिया। पीड़ितों के मुताबिक घटना तब हुई जब गौतम सिंह अपने कुत्ते को लेकर टहलने निकले थे। इसी दौरान कुछ लोग पहले से घात लगाए खड़े थे और अचानक उन पर हमला कर दिया।

घायल गौतम ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें पीछे से पकड़ कर रॉड से हमला किया। चिल्लाने पर उनकी भाभी घटनास्थल पर पहुंचीं, लेकिन आरोपियों ने उन पर भी लाठियों एवं हाथापाई की। हमले के बाद घायल दोनों सीधे सेक्टर 12 थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा; अस्पताल सूत्रों के अनुसार दोनों की स्थिति स्थिर है और उन्हें खतरा से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज और पड़ोसी के बयानों की जांच की जा रही है तथा जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पड़ोसियों ने कहा कि इस इलाके में रात के समय संदिग्ध गतिविधियाँ बढ़ी हैं, और वे सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध जानकारी के लिए थाने से संपर्क करने की अपील की है।

घर-घर सत्यापन कर एक परिवार-एक मतदान केंद्र के अनुरूप मतदाता सूची को सुव्यवस्थित करना सुनिश्चित करें:के. रवि

बिभा संवाददाता

पाकुड़। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने बुधवार को पाकुड़ जिले के पाकुड़ एवं लिट्टीपाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सीमावर्ती इलाकों में स्थित विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली तथा स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर मतदाता सूची में दर्ज विवरणों एवं बीएलओ द्वारा किए जा रहे घर-घर सत्यापन के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों एवं बीएलओ को निर्देश दिया कि घर-घर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी गंभीरता एवं सावधानी से की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि यथासंभव एक परिवार के सभी मतदाता एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध हों तथा कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर सत्यापन अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्धारित प्रक्रिया एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

श्री के. रवि कुमार ने राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से तैयार मतदाता सूची को परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संरक्षित किया जाएगा। मतदाता सूची में दर्ज प्रमाणित एवं सही विवरण भविष्य में मतदाता तथा उसके परिवार के लिए महत्वपूर्ण अभिलेख के रूप में उपयोगी होगा। इसलिए प्रत्येक मतदाता अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के विवरण की जांच अवश्य करें और किसी प्रकार के सुधार, नाम जोड़ने अथवा अन्य आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के अनुरूप केवल भारतीय नागरिक ही निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए-2 तथा आम नागरिकों से अपील की कि यदि उनके संज्ञान में किसी विदेशी नागरिक द्वारा मतदाता सूची में शामिल होने का प्रयास करने अथवा ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी विदेशी नागरिक का नाम दर्ज होने का मामला आता है, तो निर्धारित फॉर्म-7 के माध्यम से अपनी आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं। प्राप्त आपत्ति पर संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों एवं तथ्यों की जांच करते हुए नियमानुसार आदेश पारित किया जाएगा।

श्री के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि किसी भी विदेशी नागरिक को मतदाता सूची में पंजीकरण कराने में किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी परिवार में विवाह अथवा किसी अन्य कारण से कोई विदेशी नागरिक निवास कर रहा है, तो मतदाता के रूप में पंजीकरण की पात्रता के लिए उसे पहले विधि के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी होगी। भारतीय नागरिकता प्राप्त किए बिना मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए गलत घोषणा अथवा मिथ्या विवरण के आधार पर आवेदन करना कानून के तहत दंडनीय हो सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मूल उद्देश्य शुद्ध, त्रुटिरहित एवं समावेशी मतदाता सूची तैयार करना है। इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से न छूटे और किसी भी अपात्र अथवा विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों, बीएलओ, राजनीतिक दलों एवं नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग की अपील की।

इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती मेघा भारद्वाज सहित लिट्टीपाड़ा एवं पाकुड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ईआरओ एईआरओ अतिरिक्त एईआरओ उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित जिला निर्वाचन कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

हजारीबाग पंचमंदिर विवाद: हाईकोर्ट की सख्ती के बाद खुला रहेगा मंदिर, आम लोगों के दर्शन पर कोई रोक नहीं

हजारीबाग : पंचमंदिर मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए अब आमलोगों के लिए मंदिर बंद नहीं होने देने का आश्वासन याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दिया।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में प्रदीप कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले की सुनवाई की।मामले के साथ Cont. Case (Civil) No. 1398 of 2025 भी जुड़ा है।अदालत ने दोनों मामलों को 'Admission' शीर्षक के तहत सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। वहीं, मामले में हस्तक्षेप के लिए दायर आवेदन की सुनवाई मुख्य याचिका के साथ किए जाने की बात आदेश में कही गई।

गौरतलब है कि इसी में सुनवाई के दौरान इंटरवेनर नीलेंदु जयपुरियार की ओर से उनके अधिवक्ता अवनीश रंजन द्वारा अदालत को बताया गया कि मंदिर को लॉक कर दिया गया, जिसपर अदालत के रुख के बाद आश्वासन देना पड़ा कि ऐसा नहीं होगा और मंदिर आमजन के लिए खुला रहेगा।

हाईकोर्ट के आदेश में इस आश्वासन को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। आदेश पर न्यायमूर्ति आनंद सेन के हस्ताक्षर हैं और आदेश की तारीख 17 अगस्त 2026 है।मामले की अगली सुनवाई मुख्य याचिका के साथ

अदालत ने हस्तक्षेप आवेदन को मुख्य मामले के साथ सुनने का निर्देश दिया है। ऐसे में मंदिर से संबंधित विवाद पर आगे की सुनवाई मुख्य याचिका के क्रम में होगी। मामले में याचिकाकताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार के साथ अधिवक्ता राहुल लांबा, कनु प्रिया और अनिश कमल उपस्थित थे। राज्य की ओर से अभिजीत आनंद तथा प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता भारत कुमार उपस्थित हुए। इंटरवेनर की ओर से अधिवक्ता अवनीश रंजन मिश्रा ने पक्ष रखा।

संक्षिप्त खबरें

रोटरी क्लब रामगढ़ सिटी ने धूमधाम से मनाया सावन सिंधारा उत्सव

रामगढ़(बिभा): रोटरी क्लब रामगढ़ सिटी के तत्वावधान में स्थानीय ओय पंजाब होटल में 'सावन सिंधारा उत्सव' अत्यंत हर्षोल्लास, उमंग और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। सावन की फुहारों के बीच आयोजित इस मिलन समारोह में रोटरी परिवार के सदस्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और सावन के पारंपरिक उल्लास का भरपूर आनंद उठाया।लहरिया और हरियाली की दिखी धूम उत्सव का मुख्य आकर्षण महिलाओं की विशेष ड्रेस थीम रही। सभी महिला सदस्य सावन के पारंपरिक परिधान लहरिया एवं हरे रंग की खूबसूरत साड़ियों में सज-धज कर पहुंची थीं, जिससे पूरा हॉल सावन के सतरंगी रंगों और हरियाली की आभा से सराबोर नजर आया।मजेदार गेम्स और तंबोला का सबने लिया आनंद कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए कई मनोरंजक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बच्चों के लिए भी जहां मजेदार खेल आयोजित हुए, वहीं बड़ों के लिए भी कई सरप्राइज गेम्स रखे गए। इसके बाद आयोजित हुए रोमांचक तंबोला (हाउजी) गेम में सभी ने पूरे उत्साह के साथ भाग्य आजमाया और विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए गए। सावन के गीतों पर सभी सदस्य जमकर झूमे और उत्सव का लुत्फ उठाया। इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष राजु अग्रवाल, प्रोजेक्ट चेयरमैन सुरज अग्रवाल एवं प्रकाश अग्रवाल की सराहनीय भूमिका रही। उनके कुशल नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ।

12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर अहम बैठक संपन्न

रामगढ़(बिभा): आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 26 को किया जाना है। इसके सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रामगढ़ के चैंबर कक्ष में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह-समझौते एवं सहमति के आधार पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपने-अपने विभाग से संबंधित अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन हेतु प्रस्तुत करने तथा पक्षकारों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), रामगढ़, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़, कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग, रामगढ़, सहायक आयुक्त, उत्पाद विभाग, रामगढ़ तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रामगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार रामगढ़ सचिव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रामगढ़ द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई कि वे आपसी सुलह-समझौते योग्य मामलों के शीघ्र एवं सरल समाधान के लिए आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।

सिमडेगा में सर्पदंश से दो लोगों की मौत

सिमडेगा(बिभा)। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच जहरीले सांपों का खतरा बढ़ गया है। अलग-अलग सर्पदंश की घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। पहली घटना पाकरटांड़ थाना क्षेत्र के चमरूटोली की है, जहां जमीन पर सो रहे श्याम मांझी को जहरीले सांप ने डस लिया। गंभीर हालत में उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना जलडेगा थाना क्षेत्र के खरवागाढ़ा की है। यहां सुरेश सिंह को सांप ने डस लिया। गंभीर हालत में अस्पताल लाए जाने के बाद इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार बारिश को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश की घटनाओं को लेकर सावधानी बरतने की अपील की गई है।

उपायुक्त ने नगर निगम की समीक्षा बैठक में नगरीय व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया निर्देश

बिभा संवाददाता

हजारीबाग: उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में नगर निगम क्षेत्र की वर्तमान नगरीय व्यवस्था एवं संचालित कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, जल निकासी, भवन निर्माण, अतिक्रमण, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, वेंडिंग जोन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने बरसात के दिनों में शहर के विभिन्न इलाकों में होने वाले जलजमाव की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित कर प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही जहां बिना समुचित जल निकासी व्यवस्था के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, वहां नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।

उपायुक्त ने नगर निगम अधिकारियों एवं टाउन प्लानर से बहुमंजिला एवं अन्य भवनों के निर्माण की स्थिति की जानकारी लेते हुए बिना विधिवत नक्शा स्वीकृत कराए तथा नियमों का उल्लंघन कर निर्मित भवनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ऐसे भवनों के स्वामियों को नोटिस निर्गत करने को कहा गया।

उन्होंने निर्देश दिया कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठान, व्यावसायिक भवन, बहुमंजिला इमारत एवं अन्य प्रकार के निमार्णाधीन भवन सात दिनों के अंदर भवन चित्र, भूमि प्रतिवेदन, अग्निशमन यंत्र से संबंधित दस्तावेज, पार्किंग तथा वाहनों के आगमन-निर्गमन की व्यवस्था सहित आवश्यक दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित भू-स्वामी के पास वैध अनुमति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है तथा भवन उपविधि यथा संशोधित एवं नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने सहायक नगर आयुक्त से उनके कार्यों की जानकारी लेते हुए नगरीय व्यवस्था को ठोस कार्ययोजना के साथ दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने गलत तरीके से निर्मित भवनों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए ऐसे निमार्णों पर रोक लगाने का स्पष्ट संदेश देने को कहा। उन्होंने शहर में नालियों की नियमित एवं प्रभावी सफाई, स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था तथा अवैध एवं बड़े भवनों के विरुद्ध कार्रवाई को प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर 15 दिनों के अंदर प्रस्ताव समर्पित करने को कहा।

बैठक में शहरी क्षेत्र में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने इन केंद्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाइयों की आपूर्ति एवं मानव संसाधन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों एवं आवश्यक मानव संसाधन के अभाव में इन स्वास्थ्य केंद्रों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने एएनएम, जीएनएम, चिकित्सक, मेडिकल ऑफिसर सहित रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया, ताकि शहरी क्षेत्र के नागरिकों को इन स्वास्थ्य केंद्रों का बेहतर लाभ मिल सके।

उपायुक्त ने कहा कि शहर की नगरीय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग एवं नगर निगम के पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माण, अतिक्रमण एवं अन्य अनियमितताओं के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में नगर आयुक्त श्री ओम प्रकाश गुप्ता, उप नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर, टाउन प्लानर व अन्य उपस्थित थे।

सदर एसडीओ से मिले हजारीबाग के निशानेबाज, उत्कृष्ट प्रदर्शन पर खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला

बिभा संवाददाता

हजारीबाग। 16वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हजारीबाग के निशानेबाजों को सदर एसडीओ आदित्य पांडेय ने अपने आवास योयर बुलाकर न सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि उन्हें खूब प्रोत्साहित किया। खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन और आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारियों से एसडीओ को अवगत कराया।

इस दौरान एसडीओ ने खिलाड़ियों से बातचीत कर उनकी उपलब्धियों की जानकारी ली और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को निरंतर मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे आगे भी बेहतर प्रदर्शन कर हजारीबाग और झारखंड का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों को अपनी तरफ से सहयोग का भरोसा भी दिया।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल राइफल क्लब में 29 से 31 जुलाई तक आयोजित 16वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में हजारीबाग के निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। जिले के खिलाड़ियों ने पदक हासिल करने के साथ भारतीय टीम के ट्रायल के लिए अपनी जगह बनाई है। वहीं, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के कई अन्य निशानेबाजों ने 25 से 30 अगस्त तक आसनसोल में होने वाली 10वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए भी क्वालीफाई किया है।

इस अवसर पर हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश रंजन, सचिव निलेंदु जयपुरियार, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्ष अजमेरा, सदस्य तेजबल देव प्रताप सिंह, मनीष सिंह समेत अन्य मौजूद थे।

वामदल राज्य भर में एमएमडीआर विधेयक की 25 से जलाएंगे प्रतियां

बिभा संवाददाता

रांची। राज्य के सभी छह वामदलों भाकपा, माकपा, भाकपा (माले), एसयूसीआई (सी), फारवर्ड ब्लाक और आरएसपी खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक (एमएमडीआर)-2026 के खिलाफ पूरे राज्य में संडकों पर उतरेंगे। यह निर्णय बुधवार को माकपा राज्य कार्यालय में आयोजित वामदलों की संयुक्त बैठक में लिया गया।

बैठक में तय किया है कि 25 से 31 अगस्त के बीच राज्य के सभी जिलों के प्रखंडों, पंचायतों और नगर निकायों में संयुक्त रूप से इस विधेयक की प्रतियां जलायी जायेंगी। सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ सभा होगी और राजधानी रांची के लोकभवन पर प्रदर्शन आयोजित कर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। आंदोलन के अगले चरण में केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों का घेराव और झारखंड बंद की घोषणा की जाएगी।

बैठक की अध्यक्षता भाकपा (माले) के राज्य सचिव मनोज भक्त ने की।

बैठक में भाकपा के राज्य सचिव महेंद्र पाठक, अशोक यादव, माकपा के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव, प्रफुल्ल लिंडा, समीर दास, सुखनाथ लोहरा, अमल आजाद बीना, भाकपा (माले) के शुभेंदु सेन, सुदामा खलको, एसयूसीआई (सी) के मिंटू पासवान और दिलीप कुमार सहित अन्य मौजूद थे।

जेपीएससी मुद्दे पर अनशनकारी छात्रों ने सरकार को दो माह में बेहतर तरीके से जांच करने की शर्त पर तोड़ा अनशन

बिभा संवाददाता

रांची। जेपीएससी-जेएसएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 25 जुलाई 2026 से चल रहे छात्र आंदोलन बुधवार को 26 वें दिन फिलहाल 60 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया।

कोतवाली थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने स्टेडियम में मौजूद अनशनकारी छात्रा सबिता कुमारी, रूपेश कुमार, राहुल क्रांति को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। हालांकि, सबिता कुमारी सहित अन्य अनशनकारियों ने दो टूक कहा कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ने जेपीएससी-जेएसएससी सीजीएल सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की बेहतर जांच का आश्वासन दिया है। सरकार के इस आश्वासन और आगे की कार्रवाई को दो माह तक देखा जाएगा।

छात्रों ने कहा कि इस अवधि में सरकार की ओर से उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर वे दोबारा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए सरकार को 60 दिनों का समय दिया गया है।

इस अवसर पर पीयूष सिंह ने आंदोलन में शामिल होनेवाले मीडिया, सामाजिक संगठन सहित अन्य लोगो के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि मांगों छात्रों की हर समस्या पर रिफॉर्म मंच आगे भी बढ-चढकर कार्य करता रहेगा।

मौके पर कुणाल प्रताप सिंह ने कहा कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग कथित परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच है। लेकिन सरकार जो कर रही है। उसे दो माह देखना होगा। सबकुछ छात्रहित और भ्रष्टाचार के खिलाफ होना चाहिए नहीं तो छात्रों को एकजुटता दिखाने में देर नहीं लगेगी। छात्रों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी है। उनका कहना है कि सिर्फ विभागीय या सीमित जांच से अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे सवालों का समाधान नहीं होगा।

छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि दो माह की मोहलत संघर्ष से पीछे हटना नहीं, बल्कि सरकार को अपनी मांगों पर कार्रवाई का अवसर देना है। निर्धारित अवधि में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा।

मौके पर पीयूष कुमार, कुणाल प्रताप सिंह, उमेश प्रसाद, देवाशीष सहित बड़ी संख्या में छात्र और अभ्यर्थी सहित मौजूद थे।

दुलाल भुईयां ने प्रधानमंत्री से दशरथ मांझी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की

बिभा संवाददाता

जमशेदपुर। अखिल भारतीय भुईयां समाज कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुईयां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दशरथ मांझी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है।

इस संबंध में उन्होंने 18 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री के नाम पत्र भेजकर दशरथ मांझी के अदम्य साहस, दृढ़ इच्छाशक्ति, संघर्ष, श्रम और समाज के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठाई है।

दुलाल भुईयां ने कहा कि बिहार के गया जिले के निवासी रहे पर्वत पुरुष दशरथ मांझी ने बेहद कठिन परिस्थितियों और अभावों के बीच अकेले पहाड़ काटकर रास्ता बनाने जैसा असाधारण कार्य किया था। उनका जीवन संघर्ष, संकल्प और दृढ़ इच्छाशक्ति का ऐसा उदाहरण है, जो आज भी देश के करोड़ों गरीब, वंचित और मेहनतकश लोगों को प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी ने अपने कार्य से यह साबित किया कि मजबूत इच्छाशक्ति और निरंतर मेहनत के बल पर असंभव दिखाई देने वाले कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि भुईयां मुशहर समाज से आने वाले दशरथ मांझी का योगदान किसी एक समाज या क्षेत्र तक सीमित नहीं था। उनका संघर्ष और मानव सेवा की भावना पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना उनके योगदान के प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

दुलाल भुईयां ने केंद्र सरकार से भुईयां समाज की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का समुचित अध्ययन कराने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले भुईयां समाज के लोगों की परिस्थितियों को देखते हुए उनके विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता है। साथ ही समाज को उसके उचित संवैधानिक और सामाजिक अधिकार दिलाने की दिशा में भी केंद्र सरकार आवश्यक पहल करे। उन्होंने प्रधानमंत्री से दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है।

डोनाल्ड ट्रंप को क्यों भा गया भारतीय निर्वाचन आयोग?

सौरभ वार्ष्णेय

भारत में चुनाव कराना अपने आप में दुनिया का एक असाधारण प्रशासनिक अभियान है। करोड़ों मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाना, मतदाता सूची तैयार करना, पहचान सुनिश्चित करना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर बनाए रखना तथा परिणामों को घोषित करना–यह पूरा तंत्र विशाल स्तर पर काम करता है। ट्रंप ने भारत के हालिया आम चुनाव में लगभग 646 मिलियन मतदाताओं का उल्लेख करते हुए भारतीय फोटो पहचान व्यवस्था को अमेरिका के संदर्भ में उपयोगी बताया। यहीं से भारत और अमेरिका के चुनावी मॉडल में एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के साथ टैरिफ पर टैरिफ खेल रहे थे अचानक युद्व छोड़कर भारत की चुनाव व्यवस्था और मतदाता पहचान प्रणाली यानी भारतीय निर्वाचन आयोग को पंसद कर रहे हैं। ज्ञात रहे कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव व्यवस्था की तुलना भारतीय चुनाव मतदाता पहचान प्रणाली से की है। ट्रंप ने भारत के विशाल चुनावी तंत्र, फोटो पहचान-पत्र की व्यवस्था और सीमित डाक मतपत्र व्यवस्था को अमेरिका के लिए उदाहरण के रूप में पेश किया। उन्होंने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कथित बातचीत का भी उल्लेख किया, हालांकि इस बातचीत का स्वतंत्र सार्वजनिक रिकॉर्ड अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान केवल भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा भर नहीं है। इसके पीछे अमेरिकी राजनीति, मतदाता पहचान, चुनावी पारदर्शिता और आगामी अमेरिकी मध्यावधि चुनावों की राजनीति भी दिखाई देती है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आखिर भारत की चुनाव व्यवस्था में ऐसा क्या है जो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति को आकर्षित कर रहा है? भारत का निर्वाचन आयोग कोई सामान्य प्रशासनिक संस्था नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसे संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का संवैधानिक दायित्व प्राप्त है। निर्वाचन आयोग स्वयं भी इसे स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में वर्णित करता है।

भारत में चुनाव कराना अपने आप में दुनिया का एक असाधारण प्रशासनिक अभियान है। करोड़ों मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाना, मतदाता सूची तैयार करना, पहचान सुनिश्चित करना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर बनाए रखना तथा परिणामों को घोषित करना–यह पूरा तंत्र विशाल स्तर पर काम करता है। ट्रंप ने भारत के हालिया आम चुनाव में लगभग 646 मिलियन मतदाताओं का उल्लेख करते हुए भारतीय फोटो पहचान व्यवस्था को अमेरिका के संदर्भ में उपयोगी बताया। यहीं से भारत और अमेरिका के चुनावी मॉडल में एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। अमेरिका में चुनावों का संचालन काफी हद तक राज्यों के स्तर पर होता है और नियमों में राज्यवार अंतर दिखाई देता है। इसके विपरीत भारत में निर्वाचन आयोग एक केंद्रीय संवैधानिक संस्था के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए व्यापक अधिकार रखता है। ट्रंप की नजर में यही केंद्रीकृत चुनाव प्रबंधन एक आकर्षक मॉडल हो सकता है। ट्रंप की टिप्पणी को समझने के लिए अमेरिकी राजनीति को समझना आवश्यक है। अमेरिका में मतदाता पहचान और नागरिकता सत्यापन लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रहे हैं। ट्रंप लगातार यह तर्क देते रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में पहचान और नागरिकता की पर्याप्त जांच होनी चाहिए।इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने भारत का उदाहरण दिया। उनका उद्देश्य केवल भारत की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि अमेरिकी मतदाता पहचान कानूनों के पक्ष में राजनीतिक समर्थन जुटाना भी है। ट्रंप प्रशासन के माध्यम से मतदाता पंजीकरण में नागरिकता प्रमाण और देशव्यापी फोटो पहचान जैसे प्रावधानों पर जोर दे रहा है।इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि ट्रंप को भारत इसलिए भा रहा है क्योंकि भारतीय चुनाव प्रणाली का एक हिस्सा उनके घरेलू राजनीतिक एजेंडे के अनुकूल दिखाई देता है।यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है–क्या ट्रंप वास्तव में भारतीय चुनाव प्रणाली को अमेरिकी चुनाव व्यवस्था का आदर्श मानते हैं या वे भारत का उदाहरण अपनी घरेलू राजनीति में एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं?

भारत की चुनाव व्यवस्था की अपनी खूबियां हैं। लेकिन भारत भी पूर्ण व्यवस्था होने का दावा नहीं कर सकता। मतदाता सूची में नाम जुड़? या हटने, पहचान संबंधी समस्याओं, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर समय-समय पर राजनीतिक विवाद उठते रहे हैं। हाल के वर्षों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर भी तीखी राजनीतिक बहस हुई है। 2026 में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष और नागरिक समूहों ने सवाल उठाए हैं, जबकि निर्वाचन आयोग ने अपने संवैधानिक अधिकारों के भीतर काम करने का पक्ष रखा है। इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में भी निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची तैयार करने की शक्तियों को लेकर प्रश्नों पर विचार हुआ है।इसलिए ट्रंप की प्रशंसा को भारत की चुनाव प्रणाली के लिए अंतिम प्रमाणपत्र मान लेना उचित नहीं होगा।किसी भी चुनाव की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोगों ने मतदान किया। असली सफलता तब होती है जब हारने वाला उम्मीदवार और उसके समर्थक भी परिणाम को स्वीकार करें।

भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान ने उसे चुनावी प्रक्रिया की देखरेख का व्यापक अधिकार दिया है ताकि सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से हो सके। निर्वाचन आयोग स्वयं अपने संवैधानिक दायित्व को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने से जोड़ता है।लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं बनती। वह जनता के विश्वास से बनती है। इसलिए निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज यही है कि उसकी प्रत्येक कार्रवाई ऐसी हो जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समान रूप से भरोसा हो।

ट्रंप के बयान के बाद भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाने संबंधी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। यह प्रतिक्रिया बताती है कि भारत में निर्वाचन आयोग को लेकर राजनीतिक विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है।यदि सरकार निर्वाचन आयोग की प्रशंसा करे तो विपक्ष को संदेह हो सकता है। यदि विपक्ष आयोग पर सवाल उठाए तो सरकार इसे राजनीतिक हमला बता सकती है। लेकिन इन दोनों के बीच संस्थागत निष्पक्षता का प्रश्न कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।निर्वाचन आयोग को न तो सरकार के पक्ष में दिखाई देना चाहिए और न विपक्ष के। उसे केवल संविधान के पक्ष में दिखाई देना चाहिए।

यदि अमेरिका भारत से कुछ सीखना चाहता है तो केवल मतदाता पहचान-पत्र की व्यवस्था को देखकर बात पूरी नहीं हो सकती। भारत की चुनाव प्रणाली एक पूरे संस्थागत ढांचे पर आधारित है। मतदाता सूची, निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्रों का प्रबंधन, चुनावी आचार संहिता, राजनीतिक दलों के साथ संवाद, चुनाव अधिकारियों की तैनाती और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से लेकर मतगणना तक एक विस्तृत व्यवस्था काम करती है।

भारत में चुनाव आयोग को चुनावों के दौरान समान अवसर उपलब्ध कराने और आदर्श आचार संहिता लागू करने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। संविधान का अनुच्छेद 324 इस पूरे ढांचे की आधारशिला है।

अमेरिका यदि भारतीय अनुभव से कुछ ग्रहण करता है तो उसे केवल पहचान-पत्र नहीं, बल्कि चुनाव प्रबंधन की संस्थागत संरचना पर भी विचार करना होगा। यहां बात केवल अमेरिका को भारत से सीखने की नहीं है। भारत को भी अपने चुनावी तंत्र में लगातार सुधार करते रहना होगा। आज मतदाता पहले से अधिक जागरूक है। सोशल मीडिया के दौर में चुनावी जानकारी कुछ सेकंड में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। गलत सूचना, डीपफेक, फर्जी वीडियो और डिजिटल प्रचार चुनावी वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं।ऐसे में निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता और संवाद की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।मतदाता सूची में किसी नागरिक का नाम क्यों जोड़ा गया या क्यों हटाया गया, चुनावी निर्णय किस आधार पर लिया गया, राजनीतिक दलों की शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई–इन सभी सवालों के जवाब समय पर और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना लोकतंत्र के हित में है।डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की ओर ध्यान जाना निश्चित रूप से भारत के लिए गर्व का विषय हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी व्यवस्था को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा उदाहरण के तौर पर पेश करना भारत की संस्थागत क्षमता को अंतरराष्ट्रीय पहचान देता है।लेकिन लोकतंत्र में बाहरी प्रशंसा से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक विश्वास है।यदि भारत के नागरिक अपने निर्वाचन आयोग पर भरोसा करते हैं, यदि राजनीतिक दल चुनावी परिणामों को स्वीकार करते हैं और यदि हर मतदाता को यह विश्वास रहता है कि उसका वोट सुरक्षित है तथा उसकी आवाज सुनी जाएगी, तभी चुनाव प्रणाली वास्तव में मजबूत कही जाएगी।आज आवश्यकता इस बात की है कि निर्वाचन आयोग अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट होकर न रुके। उसे लगातार खुद को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना होगा।ट्रंप को भारत इसलिए भाया क्योंकि उन्हें अपनी घरेलू राजनीतिक बहस के लिए भारतीय मॉडल में कुछ उपयोगी तत्व दिखाई दिए। लेकिन भारत के लिए इससे बड़ा संदेश यह है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं दुनिया के लिए उदाहरण बन सकती हैं–बशर्ते हम उनके प्रति जनता का विश्वास बनाए रखें। चुनाव केवल सत्ता चुनने की प्रक्रिया नहीं है। चुनाव लोकतंत्र में नागरिक और राज्य के बीच विश्वास का सबसे बड़ा सेतु है। निर्वाचन आयोग उस सेतु का प्रहरी है।

इसलिए ट्रंप की प्रशंसा अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन असली परीक्षा यह है कि भारत का आम मतदाता अपने निर्वाचन आयोग के बारे में क्या सोचता है। लोकतंत्र की अंतिम कसौटी वाशिंगटन की प्रशंसा नहीं, बल्कि भारत के मतदान केंद्र पर खड़ा वह सामान्य नागरिक है जो अपने हाथ में मतदाता पहचान-पत्र लेकर यह विश्वास करता है कि उसकी एक-एक वोट की कीमत है। और यही विश्वास भारत के निर्वाचन आयोग की सबसे बड़ी पूंजी है।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

एक खत्म, दूसरा शुरू

झारखंड में करीब 25 दिन तक चले छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विवादित कंपनी टीडीपीएल के संचालन में हुई जेपीएससी-14, जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही घोषणा कर दी कि जेपीएससी 11 व 13 की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा परीक्षाओं के घोषित परिणाम भी रद्द करने का ऐलान कर दिया गया। यानी टीडीपीएल के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी चुने गए, उनका चयन भी रद्द कर दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सचिवालय में ग्यारह मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर व्यापक विमर्श किया। छात्र आंदोलन के दबाव में काम कर रही राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक करीब साढ़े चार घंटे तक चली। दरअसल, छात्रों के कई खेमे अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया,उनमें चौदहवीं जेपीएससी सिविल सेवा रेगुलर, जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, फॉरेस्ट रेंज अफसर, सहायक वन संरक्षक और सिविल जूनियर आदि की नियुक्तियां शामिल हैं। दरअसल, इन परीक्षाओं का संचालन जेपीएससी के माध्यम से किया गया। वहीं दूसरी ओर सीजीएल परीक्षा से चयनित 1975 लोगों की नौकरियां भी अब समाप्त मानी जाएंगी। सरकार ने वायदा किया है कि वर्ष 2014 के बाद हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं की जांच भी की जाएगी। यह जांच कार्य एक न्यायिक आयोग करेगा। बाकायदा एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में सुधारों के लिये एक कमेटी भी बनायी गई है। हालांकि, कुछ आंदोलनकारी छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। हालांकि, सरकार की घोषणा के बाद छात्रों का आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन इस घोषणा के बाद सचिवालय परिसर में उन नियुक्त प्रतिभागियों की भीड़ जुट गई, जो जेएसएससी के माध्यम से परीक्षा उतीर्ण करके नौकरी हासिल कर चुके थे। सरकार की घोषणा के तुरंत बाद विभिन्न चयनित प्रतिभागियों का हुजूम सचिवालय में जमा होना शुरू हुआ। उनके लिये यह खबर स्तब्ध करने वाली थी। उनका दुख और गुस्सा स्वाभाविक ही है।

बहरहाल, अब राज्य सरकार के खिलाफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में चयनित होने के बाद हटाये गए लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री एक बयान देकर दो हजार लोगों को सरकारी नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? वे इसे सरकारी अन्याय बता रहे हैं। उनकी दलील है कि हम सुबह नौकरी पर थे,लेकिन शाम होते ही हमें नौकरी से हटा दिया गया। उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश के बाद ही हमें नौकरी मिली है। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षा दिसंबर 2023 में आयोजित हुई थी। लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा सितंबर 2024 में फिर से हुई। फिर पेपर लीक की आशंका के बीच मामला अदालत पहुंचा। कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। साथ ही तीस दिसंबर को सफल प्रत्याशियों को बाकायदा नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दे दिए गए। अब सरकार द्वारा ये नियुक्तियां रद्द करने से प्रतिभागी बदहवास हैं क्योंकि कई लोगों ने लोन लेकर अपना जीवन स्तर सुधारा, उनकी बैंक की किश्तें जा रही हैं। अब उनकी आंखों के सामने अंधेरा है। उनकी मांग है कि सरकार कायदे से जांच कर ले, लेकिन उन्हें नौकरी से न हटाए। सभी लोग धांधली से भर्ती नहीं हुए हैं। उनका तर्क है कि भीड़ के दबाव में निर्दोष लोगों को सजा नहीं दी जा सकती। हटाये गए कर्मचारियों की आंखें नम हैं। उनमें कई लोग ऐसे हैं जो अपनी दूसरी नौकरियां छोड़कर सरकारी नौकरी के प्रलोभन में आए। दुखी व हताश हटाये गए कर्मचारी बारिश में धरने पर बैठे रहे क्योंकि उन्हें अधिकारियों ने सचिवालय से बाहर कर दिया था। वहीं दूसरी ओर हटाए गए कर्मियों के घर वाले भी सदमे में हैं। राज्य सरकार भी मुश्किल में है क्योंकि सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों की दलील है कि उनका आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। वहीं सरकार के सामने हटाये गए अधिकारियों व कर्मचारियों का नया मोर्चा खुल गया है। हटाये गए कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। वे सरकार के लिखित आदेश की प्रतीक्षा में हैं।

मच्छर जानलेवा है, जागरूकता और स्वच्छता ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार

कांतिलाल मांडोत

मच्छर आकार में भले ही बहुत छोटा जीव है, लेकिन मानव स्वास्थ्य के लिए इसका खतरा बेहद बड़ा है। दुनिया में अनेक गंभीर संक्रामक बीमारियों के प्रसार में मच्छरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफलाइटिस, जीका, पीला बुखार और फाइलेरियासिस जैसी बीमारियां मच्छरों के माध्यम से फैलती हैं। इन बीमारियों के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं और कई मामलों में स्थिति गंभीर भी हो जाती है। इसलिए मच्छर को केवल परेशान करने वाला कीट मानना उचित नहीं है। यह मानव जीवन के लिए गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है।

हर वर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस की ऐतिहासिक खोज की स्मृति में मनाया जाता है। 20 अगस्त 1897 को रॉस ने यह महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किया कि मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया के परजीवी को फैलाने में भूमिका निभाती है। इस खोज ने मलेरिया के संक्रमण और उसके नियंत्रण को समझने की दिशा में चिकित्सा विज्ञान को नई राह दिखाई। रॉस को बाद में वर्ष 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

विश्व मच्छर दिवस का उद्देश्य केवल इस वैज्ञानिक उपलब्धि को याद करना नहीं है, बल्कि लोगों को मच्छरजनित बीमारियों के खतरे और उनसे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना भी है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बीमारी फैलने के बाद उपचार करने से बेहतर है कि मच्छरों के प्रजनन को रोककर बीमारी की आशंका को ही कम किया जाए।

मलेरिया मच्छर से फैलने वाली सबसे पुरानी और गंभीर बीमारियों में से एक है। यह प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होता है और संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिरदर्द और कमजोरी इसके सामान्य लक्षण हो सकते हैं। समय पर जांच और उचित उपचार मिलने पर मलेरिया का इलाज संभव है, लेकिन लापरवाही की स्थिति में यह गंभीर और जानलेवा रूप ले सकता है।

डेंगू भी मच्छरजनित बीमारी है, जो मुख्य रूप से संक्रमित एडीज मच्छरों से फैलती है। तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, मतली और कमजोरी इसके सामान्य लक्षण हैं। कुछ मामलों में डेंगू गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए लगातार या तेज बुखार होने पर चिकित्सकीय सलाह लेना आवश्यक है। डेंगू की रोकथाम में मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में शामिल है।

चिकनगुनिया भी एडीज मच्छरों से फैलता है। इसमें बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जापानी इंसेफलाइटिस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी है। जीका वायरस भी एडीज मच्छरों के माध्यम से फैल सकता है और गर्भावस्था के दौरान विशेष चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा पीला बुखार और फाइलेरियासिस भी मच्छरों से फैलने वाली महत्वपूर्ण बीमारियां हैं।

मच्छरों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सामान्यतः मादा मच्छर ही मनुष्य और अन्य जीवों का रक्त चूसती हैं। मादा मच्छर को अंडों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। नर मच्छर मुख्य रूप से पौधों के रस और अन्य वनस्पति स्त्रोतों पर निर्भर रहते हैं। मच्छर मनुष्य तक पहुंचने के लिए सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर की गर्मी और गंध जैसे संकेतों का उपयोग करते हैं। इसी कारण वे मनुष्यों को आसानी से खोज लेते हैं। मच्छरों की अलग-अलग प्रजातियों का व्यवहार और बीमारी फैलाने की क्षमता भी अलग होती है। इसलिए मच्छर नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक निगरानी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपाय करना आवश्यक है।

वंदे मातरम प्रेमः हकीकत या फसाना

निर्मल रानी

राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर 2026 के नये सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजाना और सभी के लिए सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही औपचारिक अवसरों पर इसके सभी छह छंदों को गाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विपक्ष सहित कुछ अन्य संगठन इस अनिवार्य प्रोटोकॉल को संविधान के अनुच्छेद 25 अर्थात व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बताते हैं। बहरहाल, इन सब के बावजूद वंदेमातरम को संसद में और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में लाल किले पर गाया गया क बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा1875 में मूल रूप से बांग्ला और संस्कृत भाषा में लिखे इस गीत के शब्द काफी कठिन हैं। 6 छंदों पर आधारित यह गीत काफी लंबा भी है। चूँकि आम तौर पर केवल इसके पहले दो छंदों को ही आधिकारिक तौर पर गाया जाता रहा है, इसलिए देश के अधिकांश राजनेताओं और आम नागरिकों को भी इसके बाद के 4 छंद कंठस्थ याद नहीं होते हैं। लेकिन भाजपा के मामले में यह विवाद इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि वह अन्य दलों पर राष्ट्रगीत के अपमान का तो आरोप लगाती है, जबकि खुद उसके अपने नेता इसे सही ढंग से प्रस्तुत करने में चूक जाते हैं।

समय-समय पर भाजपा के नेताओं की इस गीत को लेकर अज्ञानता कैमरे पर भी उजागर हुई है। एक टेलीविजन लाइव डिबेट के दौरान, जब भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार सिंह दूसरों को वंदे मातरम् गाने की चुनौती दे रहे थे, तो एंकर ने उनसे स्वयं इसे गाने को कह दिया। वे अपने मोबाइल फोन में देखने के बावजूद गीत की गलत पंक्तियाँ गाने लगे और धुन भी पूरी तरह भूल गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री बलदेव सिंह औलख से जब पत्रकारों ने वंदे मातरम् की कुछ पंक्तियाँ सुनाने को कहा, तो वे बेहद असहज हो गए। उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें इस समय पूरा याद नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर में भाजपा के मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, मंच पर राष्ट्रगीत गाते समय गलत धुन और गलत वर्जन बज गया। कांग्रेस द्वारा इस बड़ी चूक पर हमला किए जाने के बाद राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। कोटा, मेरठ और ग्वालियर जैसे कई शहरों में भाजपा के स्थानीय विधायकों और सांसदों के ऐसे अनेक वीडियो सामने आ चुके हैं, जहाँ वे वंदे मातरम् और राष्ट्रगान (जन गण मन) के बीच अंतर करने में भ्रमित हो जाते हैं या गीत की पंक्तियों को आपस में मिला देते हैं। हाल ही में गुजरे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जब वंदे मातरम् को लेकर नया कानून और राष्ट्रगीत विवाद गरमाया, तो विपक्ष ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि जिन्होंने वंदे मातरम् को लेकर कड़े कानून बनाये हैं, हक ीकत यह है कि उनके अपने नेताओं और मंत्रियों को भी यह गीत पूरा याद नहीं है।

उधर मुस्लिम समुदाय के भीतर इस गीत को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण और विचार हैं। हालाँकि समग्र मुस्लिम समाज वंदे मातरम् गायन का विरोध नहीं करता है परन्तु समाज के कुछ लोग या कुछ धार्मिक संगठन इसके पूरे पाठ या कुछ विशिष्ट छंदों का विरोध करते हैं। जबकि अनेक अन्य मुस्लिम नागरिक,प्रतिष्ठित लोग और कलाकार इसे देशभक्ति के प्रतीक के रूप में सहजता से गाते भी हैं। दरअसल मुसलमानों के एक वर्ग के वंदे मातरम् का विरोध करने के पीछे मुख्य रूप से धार्मिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक कारण हैं। एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित इस्लाम धर्म में केवल एक अल्लाह की इबादत की अनुमति है। जबकि वंदे मातरम् का शाब्दिक अर्थ माँ, मैं आपकी वंदना/पूजा करता हूँ होता है जहाँ देश को एक देवी दुर्गा के रूप में चित्रित किया गया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे धार्मिक संगठनों का मानना है कि अल्लाह के अलावा किसी भी अन्य सत्ता, भूमि या मूर्ति के सामने झुकना या उसकी पूजा करना उनके धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। कुछ इतिहासकारों और मुस्लिम विचारकों का मानना है कि इस उपन्यास की पृष्ठभूमि और कुछ अंशों में मुस्लिम विरोधी भावनाएं निहित थीं, जिससे इस गीत को लेकर ऐतिहासिक रूप से एक संशय पैदा हुआ। कई मुस्लिम नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों का यह तर्क भी है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 19 और 25 नागरिकों को अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उनका कहना है कि देशभक्ति साबित करने के लिए किसी को भी ऐसा गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जो उनकी धार्मिक आस्था से टकराता हो। हालांकि इस विषय पर मुस्लिम समाज भी एकमत नहीं है। कुछ उलेमाओं का मानना है कि इसके छंदों में मूर्तिपूजा और देवी स्वरूप की स्तुति शामिल है, इसलिए वे इसे गाने से परहेज करते हैं। यही वजह थी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए ही इस गीत के केवल शुरूआती दो छंदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया था। पहले दो छंदों में देश की प्राकृतिक सुंदरता (सुजलां सुफलां) का वर्णन है, जिस पर कई प्रगतिशील मुस्लिम संगठनों को कोई आपत्ति नहीं है। जबकि कई उदारवादी मुस्लिम, आम नागरिक और कलाकार इसे बिना किसी धार्मिक चश्मे के केवल अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान और प्रेम के रूप में देखते हैं। जैसे कि संगीतकार ए.आर. रहमान द्वारा गाया गया मां तुझे सलाम वंदे मातरम बेहद लोकप्रिय है। ऐतिहासिक रूप से भी, स्वतंत्रता संग्राम जैसे कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे महान मुस्लिम नेताओं ने इस गीत और नारे का खुलकर समर्थन किया था। इसलिए, वर्तमान में भी यह मुद्दा पूरे मुस्लिम समाज का नहीं, बल्कि व्यक्तिगत धार्मिक प्राथमिकताओं और आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

परन्तु आज जब देश का बड़ा वर्ग खासकर युवा शिक्षा की होती दुर्गति, पेपर लीक, भयंकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दयनीय स्वास्थ्य सेवाओं, बेतहाशा बढ़ती मंहगाई, मंदिर दान चोरी आदि से दुखी होकर सड़कों पर उतर रहा है। आज जब भारत में बाल कुपोष की यह स्थिति है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार हर दूसरा भारतीय बच्चा कुपोषित है,देश का गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है,खुद सरकारी दावों के अनुसार 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो मुफ़्त राशन पर आश्रित है। ऐसे में क्या वंदे मातरम गाने से लोगों को बेहतर जिन्दगी मिल सकेगी और उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सकेगा ? या फिर भाजपा इसे अपने राजनैतिक स्वभाव के अनुरूप मात्र हिन्दू मुस्लिम के बीच का भावनात्मक मुद्दा बनाकर उछालना चाह रही है? वह भी तब जबकि इसके अपने अधिकांश सांसद व नेता न तो वंदे मातरम गा सकते हैं न ही उन्हें कंठस्थ है। दरअसल भाजपा द्वारा वंदे मातरम के प्रति प्रेम प्रदर्शन के पीछे की हक ीकत कुछ और है और फसाना कुछ और।

भारत का मखाना सेक्टरः पारंपरिक फसल से ग्लोबल सुपरफूड तक

बिहान भारत

मखाना, जिसे फॉक्स नट भी कहा जाता है, भारत में तेजी से उभरता हुआ कृषि-खाद्य उत्पाद बन गया है। इसका कारण इसका पोषण मूल्य, स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और वैश्विक मांग में वृद्धि है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग तीन-चौथाई है और वैश्विक आपूर्ति में इसकी हिस्सेदारी लगभग 80झ85 प्रतिशत है। भारत का मखाना निर्यात 2020 में 7,260 मीट्रिक टन से बढ़कर 2024 में 25,130 मीट्रिक टन हो गया। स्वस्थ और प्रीमियम स्नैक्स की मजबूत मांग के कारण घरेलू कीमतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड और 476.03 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र योजना सहित सरकार की विभिन्न पहलें अनुसंधान, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, निर्यात और किसानों को सहायता प्रदान कर रही हैं। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग में लगातार वृद्धि के साथ मखाना किसानों की आय बढ़ाने की मजबूत क्षमता रखता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ भारत के कृषि-खाद्य निर्यात को भी मजबूत कर सकता है।

मखानाः भारत का सुपरफूड क्षेत्र तेजी से उभर रहा है

मखाना, जिसे वैज्ञानिक रूप से Euryale ferox के नाम से जाना जाता है, एक जलीय फसल है, जिसकी खेती मुख्य रूप से उथले तालाबों, झीलों और आर्द्रभूमियों में की जाती है। इस पौधे का खाने योग्य हिस्सा इसका बीज है। भूनने या प्रसंस्करण के बाद बीज फूलकर फॉक्स नट (मखाना) के रूप में खाया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश है। इस स्थिति के पीछे अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों और लंबे समय से चली आ रही खेती की परंपराओं का योगदान है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में किया जाता है।

समय के साथ मखाना बिहार के पारंपरिक खाद्य पदार्थ से पूरे देश में व्यापक रूप से खाए जाने वाले स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ के रूप में विकसित हुआ है। इस बदलाव के पीछे स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और सरकार की सहायक नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मूल्यवर्धित मखाना उत्पाद बनाने वाले स्टार्टअप्स के बढ़ते प्रसार और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की बढ़ती भूमिका ने भी इस क्षेत्र के विस्तार में योगदान दिया है। इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की थी। बोर्ड का औपचारिक शुभारंभ 15 सितंबर 2025 को बिहार में किया गया। यह पहल मखाना मूल्य श्रृंखला को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस क्षेत्र को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने मखाना विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए कुल 476.03 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। यह योजना अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता में सुधार करने और किसानों के कौशल को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कटाई और कटाई के बाद की प्रक्रियाओं को उन्नत करना, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ाना तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत करना भी है। मखाना विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 30 करोड़ और वर्ष 2026-27 के लिए 90 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।

भारत में मखाना क्षेत्र का तेजी से विस्तार

भारत मखाना उत्पादन में लगातार विश्व स्तर पर स्पष्ट रूप से अग्रणी बना हुआ है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग तीन-चौथाई है और वैश्विक आपूर्ति में इसकी हिस्सेदारी लगभग 80-85 प्रतिशत है। मखाने की खेती मुख्य रूप से उत्तर बिहार में केंद्रित है।

यह विशेष रूप से कोसी बेसिन के सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिलों के साथ-साथ मिथिला और सीमांचल क्षेत्रों के आसपास के इलाकों में प्रमुख रूप से उगाया जाता है। इससे बिहार मखाना क्षेत्र का मुख्य केंद्र बन गया है।

2024-25 में, उद्यानिकी सांख्यिकी इकाई, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतिम अनुमान के अनुसार, भारत में मखाना का कुल उत्पादन 63,910 मीट्रिक टन (MT) था। इसकी औसत उत्पादकता 2.03 MT प्रति हेक्टेयर थी। 2025-26 के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत में मखाना का कुल उत्पादन बढ़कर 80,590 MT हो गया है। इसकी औसत उत्पादकता 2.34 MT प्रति हेक्टेयर है। बिहार देश में मखाना का प्रमुख उत्पादक है। 2025-26 में बिहार का मखाना उत्पादन 60,000 MT रहा, जबकि इसकी औसत उत्पादकता 2.00 MT प्रति हेक्टेयर रही।

परंपरागत रूप से तालाबों में उगाए जाने वाले मखाने की खेती में अब फील्ड-सिस्टम खेती जैसी आधुनिक तकनीकों और स्वर्ण वैदेही तथा सबौर मखाना-1 जैसी उन्नत किस्मों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिली है। इस क्षेत्र की वृद्धि के पीछे खेती के क्षेत्रफल में विस्तार, उत्पादकता में सुधार और खेती से जुड़े जोखिमों में कमी प्रमुख कारक रहे हैं।

Text Box: मखाना-भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में उत्पादित मखाने की विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और इससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान को मान्यता देता है। GI दर्जा इसे कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, बाजार में अलग पहचान को बढ़ाता है तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ब्रांडिंग की संभावनाओं को मजबूत करता है।

मखाना बाजार में घरेलू उत्पादन और खपत की गतिशीलता

भारत हर वर्ष 0.6 लाख मीट्रिक टन से अधिक मखाने का उत्पादन करता है। इसमें से लगभग 40 प्रतिशत, यानी करीब 0.23-0.25 लाख मीट्रिक टन, का निर्यात किया जाता है, जबकि शेष मात्रा की खपत घरेलू बाजार में होती है। स्वच्छ-लेबल (Clean-label) और पौध-आधारित सुपरफूड्स की बढ़ती वैश्विक मांग के साथ, भारत का मजबूत उत्पादन आधार मखाने को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक प्रीमियम स्नैक के रूप में स्थापित करता है।

घरेलू मखाना बाजार में 2021-22 से 2024-25 के बीच 17-18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इस वृद्धि के पीछे स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता, प्रीमियम उत्पादों की ओर बढ़ता रुझान और ब्रांडेड कंपनियों के विस्तार जैसे कारक रहे हैं। मजबूत घरेलू मांग ने निर्यात बाजारों में होने वाले उतार-चढ़ाव से भी इस क्षेत्र को काफी हद तक सुरक्षित रखने में मदद की है। मखाना बाजार के 2029-30 तक 11,000-12,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022 से 2025 के दौरान उत्पादन मात्रा में केवल 4 से 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसत कीमतें 2020-2022 के दौरान लगभग 500 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 2025 में करीब 1,250 रुपये प्रति किलोग्राम हो गईं। इस वृद्धि को स्वास्थ्य-केंद्रित स्नैक्स की बढ़ती मांग, प्रीमियम ब्रांडिंग और आपूर्ति में सीमित वृद्धि से जोड़ा गया है।

अनुमानित मासिक घरेलू खपत (पॉप्ड मखाना)

भारत में पॉप्ड मखाने की मासिक घरेलू खपत का अनुमान 3,000-3,500 मीट्रिक टन है। त्योहारों के दौरान, जब स्नैक्स की मांग चरम पर होती है, खपत बढ़कर लगभग 5,000 मीट्रिक टन हो जाती है।

घरेलू खपत में ब्रांडेड फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) और संगठित स्नैक कंपनियों की हिस्सेदारी प्रति माह 1,800-2,000 मीट्रिक टन है। यह श्रेणी के तेजी से प्रीमियमाइजेशन और खुदरा बाजार में बढ़ती पहुंच के कारण संभव हुआ है। वहीं, खुला और असंगठित खुदरा बाजार प्रति माह 1,200-1,400 मीट्रिक टन की खपत करता है। टियर-2 और टियर-3 बाजारों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है, हालांकि पैकेज्ड उत्पादों की लोकप्रियता धीरे-धीरे बढ़ रही है।

स्थानीय खेतों से वैश्विक बाजार तकः निर्यात का सफर

2025 से पहले, मखाना सामान्य हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (HSN) कोड के अंतर्गत वर्गीकृत था। इसके कारण मखाना उत्पादों से संबंधित विशिष्ट निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

इस कमी को दूर करने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 2025 में पॉप्ड मखाना और अन्य मखाना उत्पादों के लिए अलग HSN कोड जारी किया। 2025-26 में भारत ने 7,264.89 मीट्रिक टन मखाना उत्पादों का निर्यात किया, जिसका निर्यात मूल्य 19,296.08 लाख रहा।

भारत के मखाना निर्यात बाजार अत्यधिक केंद्रित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका (40%), कनाडा (20%) और संयुक्त अरब अमीरात (17%) मिलकर कुल मखाना निर्यात का 77% हिस्सा रखते हैं। हालांकि, इन उच्च मात्रा वाले बाजारों में प्रति इकाई अपेक्षाकृत कम कीमतें मिलती हैं—अमेरिका में 19.5 डॉलर प्रति किलोग्राम, कनाडा में 15.8 डॉलर प्रति किलोग्राम और यूएई में 13.3 डॉलर प्रति किलोग्राम। इसके विपरीत, जर्मनी (26.0 डॉलर प्रति किलोग्राम), नेपाल (21.6 डॉलर प्रति किलोग्राम) और ऑस्ट्रेलिया (21.0 डॉलर प्रति किलोग्राम) जैसे छोटे बाजार सीमित मात्रा (1-5%) के बावजूद प्रीमियम कीमतें प्रदान करते हैं। यूनाइटेड किंगडम एक संतुलित स्थिति प्रस्तुत करता है, जहां बाजार हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है और औसत मूल्य प्राप्ति 20 डॉलर प्रति किलोग्राम है। यह दशार्ता है कि समग्र मूल्य प्राप्ति बढ़ाने के लिए अमेरिका और खाड़ी देशों के बाजारों से आगे निर्यात बाजारों में विविधता लाने तथा अधिक कीमत देने वाले क्षेत्रों को लक्षित करने का अवसर मौजूद है।

मखाना की खेती का विस्तार और किसानों के लिए सहायता को सुदृढ़ करना

योजना के तहत विभिन्न राज्यों में 1,010 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को मखाना की खेती के अंतर्गत लाया गया है। वहीं, 73 हेक्टेयर क्षेत्र को बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है। मखाना की उन्नत उत्पादन तकनीकों के प्रदर्शन के लिए कुल 89 फ्रंट लाइन प्रदर्शन (FLDs) आयोजित किए गए। किसानों की क्षमता निर्माण के लिए सेमिनार, एक्सपोजर विजिट और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs), केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों (CAUs), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के संस्थानों आदि में आयोजित किए गए। मखाना विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 2025-26 में देशभर में कुल 8,159 किसान लाभान्वित हुए।

कुरकुरेपन के पीछे का विज्ञानः मखाने की पोषण संबंधी विशेषताएं

मखाना पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें काबोर्हाइड्रेट, उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, आहार फाइबर तथा मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस और आयरन जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है और यह कोलेस्ट्रॉल-मुक्त होता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार की आहार संबंधी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है।

मखाना अपने पोषण और स्वास्थ्य संबंधी लाभों के लिए जाना जाता है और इसे तेजी से एक वैश्विक सुपरफूड के रूप में पहचान मिल रही है। इसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, जिससे यह मधुमेह को नियंत्रित करने वाले लोगों के लिए उपयुक्त है। यह हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने, पाचन में सहायता करने के साथ-साथ अपने एंटी-एजिंग गुणों के लिए भी जाना जाता है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि मखाने का पोषक तत्व प्रोफाइल कई आम तौर पर खाए जाने वाले मेवों जैसे बादाम, अखरोट और काजू की तुलना में बेहतर है।

इसमें वसा की मात्रा बहुत कम (प्रति 100 ग्राम 0.33 ग्राम) होती है, यह फाइबर से भरपूर है, इसमें विभिन्न आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं और इसकी लगभग 95 प्रतिशत प्रोटीन पाचन क्षमता है। इसका

आवश्यक
अमीनो एसिड

सूचकांक और रासायनिक स्कोर मछली के समान है।

सुपरफूड बनने की प्रक्रियाः बीज से स्नैक तक

मखाना उत्पादन में कई चरण शामिल होते हैं, जो मिलकर इसकी मूल्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कटाई और बीज संग्रह का कार्य खेत स्तर पर किया जाता है। सफाई और सुखाना प्राथमिक प्रसंस्करण का हिस्सा हैं। वहीं, भूनना या पॉपिंग, ग्रेडिंग, पॉलिशिंग और पैकेजिंग जैसी गतिविधियां द्वितीयक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के अंतर्गत आती हैं।

खेत स्तर पर उत्पादन

खेत स्तर पर उत्पादन में तालाब की तैयारी, बीजों का छिड़काव, फसल प्रबंधन और जल निकायों से मैनुअल कटाई शामिल है। यह चरण अत्यधिक श्रम-प्रधान है और कुशल मानवीय श्रम पर निर्भर करता है। बीज संग्रह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसे पानी के अंदर किया जाता है। पारंपरिक खेती की पद्धतियां अभी भी इस क्षेत्र में प्रमुख हैं और मशीनीकरण का स्तर सीमित है।

प्राथमिक प्रसंस्करण

मखाने का प्राथमिक प्रसंस्करण अधिकांशतः पारंपरिक उपकरणों और विधियों का उपयोग करके घरेलू या गांव के स्तर पर किया जाता है। इस प्रक्रिया की शुरूआत कच्चे बीजों को सुखाने और साफ करने से होती है, जिसके बाद उन्हें उच्च तापमान पर भुना जाता है। गर्म किए गए बीजों को फिर फोड़ा (पॉप किया) जाता है, जिससे वे फैलकर हल्के और कुरकुरे रूप में बदल जाते हैं, जिसे आमतौर पर स्नैक के रूप में खाया जाता है। पॉपिंग के बाद मखाने की पॉलिशिंग, छंटाई और आकार तथा गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाती है। बड़े आकार और बेहतर गुणवत्ता वाले मखाने को बाजार में अधिक कीमत मिलती है।

द्वितीयक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन

अंतिम उत्पाद, यानी पॉप्ड मखाना, को पॉलिश करके पैक किया जाता है। हाल के वर्षों में द्वितीयक प्रसंस्करण का विस्तार पारंपरिक रूपों से आगे बढ़ा है। अब इसमें फ्लेवर्ड मखाना, रेडी-टू-ईट स्नैक्स, मखाना आटा और अन्य उत्पाद भी शामिल हैं। यह क्षेत्र मूल्य संवर्धन और रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं प्रदान करता है।

राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र (NRCM)

राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र (NRCM) अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत के मखाना क्षेत्र के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह पूरे क्षेत्र में उन्नत खेती और प्रसंस्करण पद्धतियों को भी बढ़ावा देता है। NRCM ने अधिक उपज देने वाली मखाना और कांटारहित सिंघाड़े की किस्में विकसित की हैं, जल-कुशल और एकीकृत कृषि प्रणालियों की शुरूआत की है तथा मखाना-सह-मछली पालन को बढ़ावा दिया है।

पिछले कुछ वर्षों में NRCM ने किसानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और विभिन्न संगठनों को अधिक उपज देने वाले मखाना बीजों के 15,824.1 किलोग्राम वितरित किए हैं। इसके प्रमुख लाभार्थियों में नाबार्ड (NABARD), राज्य मत्स्य विभाग, बिहार बागवानी विकास सोसाइटी और अन्य संस्थान शामिल हैं।

2012 से 2023 के बीच, 3,000 से अधिक किसानों को उन्नत खेती, प्रसंस्करण और विपणन पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जल के कुशल उपयोग, उपयुक्त फसल प्रणालियों और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। केंद्र ने 24 उद्यमों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की है, जिससे ग्रामीण आजीविका को समर्थन मिला है और मखाना आधारित कृषि-उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है।

क्षमता निर्माण के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, NRCM ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार के साथ मिलकर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने की पहल का प्रस्ताव रखा है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य मखाना मूल्य श्रृंखला में विस्तार सेवाओं को मजबूत करना है। इसमें खेती, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, सुखाने, पॉपिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, NRCM ने मखाना पॉपिंग और मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए कई प्रकार के उपकरण और मशीनरी विकसित की है। इन तकनीकों को व्यावसायिक स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए निमार्ताओं को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। इनमें मखाना बीज वॉशर, बीज ग्रेडर, प्राथमिक रोस्टिंग मशीन, पॉपिंग मशीन और पॉप्ड मखाना ग्रेडर प्रमुख हैं। विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन से संबंधित तकनीकों को भी व्यावसायिक उपयोग के लिए हस्तांतरित किया गया है।

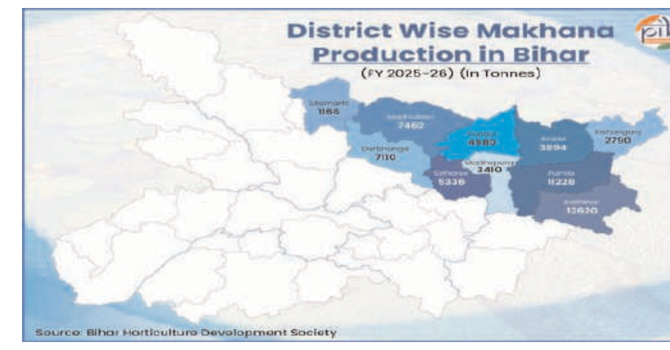

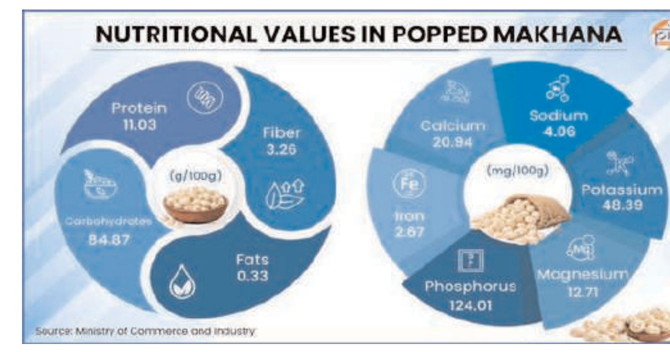

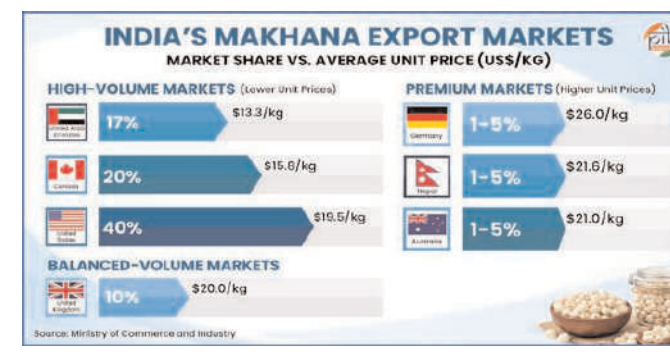

पोषण, किसानों और वैश्विक बाजारों को जोड़ने वाली फसल

मखाना भारत के सबसे तेजी से बढ़ते कृषि-खाद्य क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। इसके पीछे स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता, घरेलू मांग का विस्तार और निर्यात की मजबूत संभावनाएं प्रमुख कारण हैं।

अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों, पारंपरिक विशेषज्ञता और निरंतर तकनीकी प्रगति के बल पर भारत वैश्विक मखाना उत्पादन में अग्रणी बना हुआ है।

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना पूरे मूल्य श्रृंखला में इस क्षेत्र को मजबूत करने की सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दशार्ती है। इसी के साथ, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र (NRCM) जैसे संस्थान अनुसंधान को आगे बढ़ाने, किसानों के कौशल को बेहतर बनाने और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

स्वास्थ्यवर्धक, पौध-आधारित और प्रीमियम खाद्य उत्पादों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मखाना किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार सृजित करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देने की मजबूत स्थिति में है।

इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी की माला चढ़ी हुई तस्वीर, बीजेपी ने की थाने में शिकायत

रांची (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट के विरुद्ध बीजेपी ने रांची के साइबर थाने में लिखित शिकायत की है और आरोपितों के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर अमर्यादित सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम पर ऋषिकेश चौहान नाम के अकाउंट से पीएम मोदी के चित्र पर माला चढ़ी हुई तस्वीर व इससे जुड़ी सामग्री पोस्ट की गई है। उसमें अंतिम संस्कार से संबंधित शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है।एक जीवित प्रधानमंत्री को मृत दर्शाना अत्यंत गंभीर व आपत्तिजनक है। मीडिया रिपोर्ट अजय साह ने पुलिस से मांग की है कि संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट की आइपी लाग, लागिन हिस्ट्री, डिवाइस डिटेल, लिंक्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, मेटा डाटा व अन्य डिजिटल साक्ष्य को विधि के मुताबिक सुरक्षित रखा जाए और सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाए। इधर, साइबर थाना रांची का कहना है कि शिकायत मिली है, उसका सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद उस आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, पूरे मामले को संवेदनशील होकर देखा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में दो दिन में दो होटलों में लगी आग से 18 की मौत, मचा हड़कंप

-कई मृतक बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज कराने भारत आए थे, जांच शुरू

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में लगातार दो बड़े होटलों में अग्निकांड से हड़कंप मच गया है। कोलकाता और बीरभूम जिले के धार्मिक स्थल तारापीठ में हुई अलग-अलग आग की दुर्घटनाओं में कुल 18 लोगों की जान चली गई। पुलिस और अग्निशमन विभाग दोनों मामलों में होटल प्रबंधनों द्वारा फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की गहन जांच कर रहे हैं। होटल में ठहरे कई मेहमान बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज के लिए कोलकाता आए थे। बचाव दल मौके पर पहुंचे और इमारत से कई लोगों को बाहर निकाला। रात 3 बजे के बाद, 9 लोगों को बचाया गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फायर विभाग ने बताया कि सभी मृतक बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज के लिए शहर में आए थे। अधिकारी इन आरोपों की जांच कर रहे हैं कि होटल में आग से सुरक्षा के पर्याप्त उपाय और उचित इंतज़ाम नहीं थे।अधिकारियों ने अभी तक आग लगने के सही कारण का पता नहीं लगाया है। जांच जारी है। कोलकाता में आग की यह घटना बंगाल के बीरभूम ज़िले के एक होटल में लगी आग के ठीक एक दिन बाद हुई है। सोमवार को तड़के करीब 4 बजे तारापीठ में चार मंज़िला होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई, जब ज़्यादातर मेहमान सो रहे थे।आग की लपटें दूसरी मंज़िल तक फैल गईं, जबकि घने धुएं ने इमारत के ऊपरी हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई मेहमान अपने कमरों में फंस गए।इस घटना में नौ लोगों की मौत हो गई, जिनमें मेघालय के एक परिवार के 5 सदस्य भी शामिल थे। पुलिस ने होटल के मालिक कल्याण पाल समेत दो लोगों को हिरासत में लिया है।यह कार्रवाई होटल में आग से सुरक्षा नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच के तहत की गई है।

जम्मू-कश्मीर की समस्याओं का समाधान नई दिल्ली करेगी, न कि वॉशिंगटन

-सर्जियो के साथ बैठक से पहले सीएम उमर बोले- दूसरे से शिकायत करना गलत

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ बैठक से पहले एक साफ कूटनीतिक दायरा तय किया और अटकलों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर की समस्याओं का समाधान नई दिल्ली करेगी, न कि वॉशिंगटन। बुधवार सुबह श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि हालांकि वह स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन वह इस बैठक का इस्तेमाल किसी विदेशी राजनयिक के सामने भारत की शिकायत करने के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे।

अब्दुल्ला ने साफ कहा कि वॉशिंगटन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। हमारी केंद्र सरकार को ही हमारी समस्याओं का समाधान करना होगा।किसी दूसरे देश के राजदूत से शिकायत करना गलत होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि श्रीनगर में अमेरिकी राजदूत के साथ बुधवार को प्रस्तावित बैठक में अंतरराष्ट्रीय मुलाकातों के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।उमर ने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर और वहां के हालात के बारे में बात करूंगा, लेकिन शिकायत नहीं करूंगा। मैं उनसे अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश भी नहीं करूंगा। यह देखते हुए कि 15 से ज्यादा सालों में यह पहली बार है जब जम्मू-कश्मीर का कोई मौजूदा सीएम किसी मौजूदा अमेरिकी राजदूत से मिल रहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि ज़्यादातर, मैं उनकी बात सुनना पसंद करूंगा।हालांकि वह भी सुनने ही आ रहे हैं।

यह हाई-प्रोफाइल मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां राज्य का दर्जा पूरी तरह बहाल करने और संवैधानिक गारंटी की सक्रिय रूप से मांग कर रही हैं, जहां विश्लेषक इस बैठक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अहम संदेश के तौर पर देख रहे हैं क्योंकि गोर दक्षिण और मध्य एशिया के लिए वॉशिंगटन के विशेष दूत की दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं सीएम अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में विदेशी मध्यस्थता या आंतरिक मतभेदों से जुड़ी किसी भी अटकल को पहले ही शांत करने की कोशिश की।

राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा को हटा दें, तब कांग्रेस में शामिल होऊंगा

पूर्व भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने फैसले की वजह खुलकर आर्थिक और व्यक्तिगत कारणों को बताया है, जिसका जिक्र उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू में किया था। हालांकि, भाजपा ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है।

पूनावाला ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को कोई वेतन नहीं देते, जबकि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे मकान किराया आदि का भुगतान करना होता है। उन्होंने कहा, मेरा मकान मालिक घर इसलिए मुफ्त में नहीं दे देगा, क्योंकि मैं भाजपा से हूं। वहां हर महीने की 1 तारीख को किराया मांगता है। उन्होंने जोड़ा कि किसी राजनीतिक आंदोलन से जुड़ना नौकरी नहीं है, बल्कि यह विचारधारा, व्यक्ति या संगठन के प्रति प्रेम

का परिणाम होता है। उन्होंने बताया कि वह 2024 से ही इस्तीफे पर विचार कर रहे थे और इस दौरान कई नेताओं ने उनसे संपर्क भी साधा था।

कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर पूनावाला ने भले ही सीधे इंकार किया हो, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें रखीं जो अवास्तविक लगती हैं। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस में तभी शामिल हो सकते हैं, जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हटा दिया जाए और नेहरू के कार्यों के लिए माफी मांगी जाए। खास बात यह है कि पूनावाला स्वयं 2021 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी वैचारिक निष्ठा दिखाकर कहा कि पीएम मोदी से बड़ा नेता इस देश में न कोई हुआ है और न ही कोई होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा इस समय भारत की सबसे अच्छी पार्टी है और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काम करने के बाद वह किसी अन्य पार्टी से जुड़ने के बारे में नहीं सोचते। उनके त्याग पत्र में भी आर्थिक मजबूरियों का हवाला देकर मोदी जी के विजन के समर्थन की बात कही गई है।

हरियाणा में अग्निवीरों को तोहफा : 6 सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण

गुरुग्राम (एजेंसी)। हरियाणा की नायाब सैनी सरकार ने सेना से लौटे अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया है, इसके तहत उन्हें विभिन्न सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलेगी। यह नई व्यवस्था आगामी 1 सितंबर से लागू होगी, जिसका उद्देश्य सैन्य सेवा और प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल को सम्मान देना और उनके लिए नई राहें खोलना है। सबसे बड़ा लाभ पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वन्य जीव गार्ड और फायर ऑपरेटर सह चालक सहित छह महत्वपूर्ण पदों पर मिलेगा, जहाँ अग्निवीरों को 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस आरक्षण के अंतर्गत वंचित अनुसूचित जाति (2 प्रतिशत), अन्य अनुसूचित जाति (2 प्रतिशत), बीसी-ए (3 प्रतिशत), बीसी-बी (2 प्रतिशत), ईडब्ल्यूएस (2प्रतिशत) और अनारक्षित श्रेणियों (9 प्रतिशत) के लिए कोटा निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, अन्य ग्रुप-सी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत और कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी पदों पर 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं पुलिस कांस्टेबल और अन्य संबंधित पदों के लिए आवश्यक फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) से उन्हें छूट दी जाएगी। ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) से भी छूट का मौजूदा प्रावधान जारी रहेगा। साथ ही, सैन्य प्रशिक्षण से संबंधित कौशल विशेषज्ञता वाले पदों पर कौशल परीक्षा से भी उन्हें छूट प्राप्त होगी। हालांकि, इन सभी छूटों के बावजूद, विज्ञापित पद के लिए भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा देना पूर्व अग्निवीरों के लिए अनिवार्य रहेगा। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों ने सरकार के पुराने आदेशों को रद्द किया है, इससे अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में एक सुव्यवस्थित और प्राथमिकता आधारित प्रवेश मिल सकेगा।

डीजेबी टेंडर घोटाले में एसीबी ने आप नेता सत्येंद्र जैन को किया गिरफ्तार

-वित्तीय जांच में रिश्वत और कमीशन के पैसे के लेनदेन की श्रृंखला उजागर

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के आधुनिकीकरण में अनियमितताओं और आपराधिक साजिश के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ व पूर्व आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव और तीन निजी संस्थाओं और कंपनियों के मालिकों नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुरर एवं पंकज वर्मा को भी गिरफ्तार किया है। एसीबी प्रमुख एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त विक्रमजीत सिंह के बयान के मुताबिक ये गिरफ्तारियां एफआईआर के बाद की गईं थीं, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पीएस भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जीएनसीटीडी में पंजीकृत है। जांच में सामने आया कि एसटीपी टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी शर्तों और नियमों में जानबूझकर फेरबदल किया गया था। टेंडर की शर्तें इस तरह तैयार की गईं, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाए और एक खास निजी टेक्नोलॉजी प्रदाता कंपनी 'मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। जांच अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित पायलट स्टडी को पूरा न करना, तकनीकी मापदंडों में बदलाव और उपचारित पानी के जरुरी मानकों को हटाना जैसी अनियमितताएं पाई गईं, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चला है कि टेंडर की शर्तें तय करने और संशोधन जारी करने में निजी व्यक्तियों, बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों के बीच नियमित साठगांठ थी, ताकि टेंडर केवल पसंदीदा कंपनी को ही मिले। वित्तीय जांच में रिश्वत और कमीशन के पैसे के लेनदेन की पूरी श्रृंखला उजागर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोटेक कंपनी से जुड़ी संस्थाओं से फंड नागेंद्र यादव की प्रोप्राइटरशिप फर्म 'ए एन एंटरप्राइजेस और 'सृजनहार के जरिये हस्तांतरित किया गया। इस माध्यम से तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में करीब 1.52 करोड़ रुपए की रिश्वत भेजी गई, जिसका इस्तेमाल अचल संपत्ति खरीदने में किया गया। इन सभी दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के बाद एसीबी ने 18 अगस्त 2026 को छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जांच एजेंसियां अपराध की पूरी कमाई और इस साजिश में शामिल अन्य पहलुओं की जांच कर रही हैं।

अखिलेश चुनाव में हार से बचने कांग्रेस को 300 सीटें देने का बना रहे प्लान

-बीजेपी और एनडीए सहयोगियों ने सपा प्रमुख पर किया जोरदार हमला

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। अखिलेश यादव बीजेपी और एनडीए सहयोगियों- आरएलडी, अपना दल और सुभासपा और निषाद पार्टी पर हमलावर हैं। इस बीच अब बीजेपी ने सपा प्रमुख पर उन्हीं के अंदाज में पलटवार किया है। बीजेपी का दावा है कि अखिलेश चुनाव में हार की जिम्मेदारी से बचने के लिए कांग्रेस को करीब 300 सीटें देने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा अपना दल नेता आशीष पटेल ने भी सपा पर निशाना साधा है।

बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि अखिलेश के पारिवारिक विवाद ने समाजवादी पार्टी की गुप्त योजनाओं को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा अपने ऊपर न फूटे, इसलिए सपा कांग्रेस को करीब 300 सीटें सौंपने जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए

किया जा रहा है, ताकि हार का मेडल राहुल गांधी के सिर बंधे और अखिलेश जिम्मेदारी से बच जाएं।

इससे पहले अखिलेश ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए सूत्रों के हवाले से एनडीए का सीट बंटवारा फॉर्मूला साझा किया था। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी पीडीए के दबाव में रालोद को 73, सुभासपा को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीटें देने की योजना बना रही है। अखिलेश ने कहा था कि यह योजना पीडीए की जनसंख्या अनुपात से बहुत कम है और पूरी तरह विफल साबित होगी।

अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा-परीक्षा घपलों, फर्जी मुकदमों, बुलडोजर कार्रवाई और 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित करने जैसी नीतियों से जनता त्रस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना लाने, स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाल करने और संविधान बदलने की साजिश करने वालों को जनता नकार चुकी है। उन्होंने नारा दिया कि आज हर जन कह रहा है कि उन्हें बीजेपी नहीं चाहिए।

वहीं, अखिलेश के एनडीए के सीट बंटवारा फॉर्मूले पर अपना दल ने भी पलटवार किया। अपना दल नेता आशीष पटेल ने सपा प्रमुख के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ट्वीट और रीट्वीट का खेल नहीं खेलती है। वह जमीन पर जनता के बीच काम करने और गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास करते हैं। पटेल ने कहा कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है और इसी हकीकत से परेशान होकर सपा नेता दूसरों के शब्दों को अफवाह बताते-बताते खुद अफवाहों के वाहक बन रहे हैं।

सारे मंदिर अभी इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि चोरी की जा सके : रेणुका

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी, वंदे मातरम विवाद और राजनीति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे सवाल किए। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी द्वारा चंपत राय को क्लीन चिट देने पर कहा कि ये पहले ही अपेक्षित था कि बड़े लोगों को बचाने के लिए निचले स्तर पर काम कर रहे लोगों को कुर्बान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। हमें पहले से पता था कि यही होने वाला है। छोटे-मोटों को कुर्बान कर देंगे और चंपत राय को बचा लेंगे। उन्होंने कहा कि सारे मंदिर अभी इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि चोरी की जा सके। ये भूल गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा से खिलवाड़ करेंगे तो ये बच जाएंगे। उनका श्राप इनको ही लगा है। बता दें मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है। मंदिर में दान के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने 27 जून को अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मंदिर में दान प्रबंधन और संग्रह से संबंधित जांच के लिए एसआईटी ने दोनों से पूछताछ की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वंदे मातरम के पूरे गीत को राजनीतिक और हिंदू-मुस्लिम से जोड़कर देखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस समय जो माहौल था, उस कारण से फैसला हुआ था। आज ये लोग किस कारण से कर रहे हैं, वही जानें और भगवान जाने। वैसे तो भगवान राम भी इनसे हटकर बैठे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर रेणुका चौधरी ने कहा कि एक लोकतंत्र में हम कोई हाथ-ज्योतिषी बनकर नहीं कह सकते हैं।

सीएम विजय का ऐलान: हर विधायक को मिलेगी नई कार

विधायकों की मांग पर टीवीके सरकार का फैसला, क्षेत्र में दौरे और विकास कार्यों की निगरानी में मिलेगी मदद

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख थलपति विजय ने राज्य के सभी विधायकों को यात्रा के लिए नई कार उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लगातार दौरे करने पड़ते हैं और जनता की समस्याओं तथा जरूरतों का जायजा लेने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र में रहना जरूरी है। ऐसे में उन्हें पर्याप्त लॉजिस्टिक्स और वाहन सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है।

सरकार का यह फैसला विधानसभा में विधायकों के लिए वाहनों और जरूरी लॉजिस्टिक्स की सुविधा का मुद्दा उठाए जाने के बाद आया है। वीसीके विधायक जोतिमणि ने विधानसभा में कहा था कि यदि विधायकों को जरूरी संसाधन और वाहन उपलब्ध नहीं होंगे तो वे अपने क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सरकार से विधायकों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करने का

अनुरोध किया था।

मुख्यमंत्री विजय ने विधायक के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए सभी विधायकों के लिए नई कार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि वाहन सुविधा मिलने से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक आसानी से पहुंच सकेंगे और जनता से सीधे संवाद के साथ-साथ विकास कार्यों की निगरानी भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे।

जनता से संपर्क में आसानी होगी

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकार की ओर से सभी विधायकों के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में आने-जाने वाले विधायकों को विशेष सुविधा मिलने की उम्मीद है। विधायक नियमित रूप से अपने क्षेत्र का दौरा कर सकेंगे और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल तथा अन्य स्थानीय समस्याओं की जानकारी लेकर संबंधित विभागों के साथ उनका समाधान कराने में तेजी ला सकेंगे। विधायक जोतिमणि ने विधानसभा में अपने क्षेत्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए वाहनों को जरूरी सुविधा बताया था। उनके अनुरोध पर मुख्यमंत्री विजय द्वारा लिया गया यह फैसला सरकार और विधायकों के बीच बुनियादी संसाधनों को लेकर उठाए गए मुद्दे के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

आँख की रोशनी गायब, शरीर में छर्रों का दद... लेंकिन दीपके ने नहीं ली कोई खबर

-संसद मार्च के दौरान घायल हुए छात्रों का दर्द

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन घटना में पैलेट गन के छर्रे लगने से घायल हुए छात्रों के जख्म अभी भी ताजा हैं। पीड़ितों को इस बात की टीस ज्यादा है कि जिस कॉकराच जनता पार्टी (सीजेपी) ने उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया था, वह अब उनका हाल भी नहीं पूछ रही है।

नजफगढ़ के छात्र साहिल लोचव की दूसरी सर्जरी के बावजूद दाईं आंख की रोशनी वापस नहीं लौट सकी है। 19 वर्षीय साहिल की आंख में पैलेट के छर्रे लगने से कॉर्निया में छेद हुआ था। उसकी मां ज्योति बताती हैं कि 20 जुलाई की घटना में साहिल की आंख और हाथ में छर्रे लगे थे, जिसमें से सभी अब तक नहीं निकाले जा सके हैं। इससे उसका एक हाथ भी ठीक से काम नहीं कर रहा। एम्स ट्रॉमा सेंटर में आंख की सर्जरी और बाद में लेंस डालने के बावजूद रोशनी नहीं लौटी है। स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और वह अभी भी अस्पताल में भर्ती है।

वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी इरशाद मंसूरी के चेहरे, आंख के पास, छाती और शरीर के कई हिस्सों में पैलेट गन के करीब 40 छर्रे लगे थे। 21 जुलाई को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में सर्जरी कर कुछ छर्रे निकाले गए, लेकिन कई अभी भी शरीर में मौजूद हैं। गुरुग्राम की कॉरपोरेट कंपनी में कार्यरत इरशाद पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं और घाव नहीं भरने के कारण ड्यूटी जॉइन नहीं कर सके हैं। बिहार के 25 वर्षीय छात्र प्रशांत के हाथ, छाती और कमर में पैलेट के छर्रे लगे थे, जिससे उनका दायां हाथ कुछ समय के लिए सुन्न पड़ गया था। डॉक्टरों ने कुछ छर्रे निकाले, लेकिन कई छोटे छर्रे मांसपेशियों में गहराई तक धंसे हैं, जिन्हें निकालने से और अधिक घाव होने का डर है। प्रशांत अब नौकरी की तैयारी करते हुए भी पहले जैसा सामान्य महसूस नहीं कर रहे हैं। साहिल की मां और प्रशांत दोनों ने बताया कि घटना के बाद से सीजेपी की तरफ से किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। जख्मी प्रदर्शनकारियों में अब यह कड़वाहट साफ दिखती है कि राजनीतिक दल ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है।

शहबाज शरीफ की परमाणु धमकी और ट्रंप की चुप्पी पर भड़के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार की जा रही प्रशंसा और दक्षिण एशिया में परमाणु तबाही टलने का श्रेय देने के मामले पर भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। पूर्व विदेश सचिव सिब्बल ने शहबाज शरीफ पर निशाना साधकर कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज ट्रंप के बढ़े हुए अहंकार को खुश करने और राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए चापलूसी में लगे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शहबाज इस मामले में अति कर रहे हैं और ट्रंप को वहीं बातें बता रहे हैं जो वे सुनना पसंद करते हैं।

शरीफ ने पोस्ट कर ट्रंप के नेतृत्व की सराहना कर दावा किया था कि उनके साहसी कदमों से दक्षिण एशिया में परमाणु तबाही टली और लाखों लोगों की जान बच गई। हालांकि, पूर्व विदेश सचिव सिब्बल ने बयान के गंभीर निहितार्थों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उनका कहना है कि शहबाज के इन बयानों में भारत के विरुद्ध परमाणु हथियारों के संभावित पहले इस्तेमाल का छिपा हुआ संकेत और आक्रामक धमकी शामिल है। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया न आना चिंता का विषय है।

पूर्व विदेश सचिव ने अमेरिका के रवैये को पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जिस प्रकार परमाणु हथियारों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर अमेरिकी नेतृत्व की चुप्पी या अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसतरह के बयानों को नजरअंदाज करना अंतरराष्ट्रीय शांति के हित में नहीं है।

इसके अतिरिक्त, शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और तुर्किये के साथ हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का भी उल्लेख कर इसके लिए अमेरिकी समर्थन का आभार जताया। ट्रंप ने इस त्रिपक्षीय समझौते को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। बहरहाल, पाकिस्तान की परमाणु बयानबाजी और उस पर अमेरिकी प्रशासन की चुप्पी को लेकर सिब्बल के इन तीखे बयानों ने कूटनीतिक हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

एसआईआर कार्य के सुचारू संचालन को लेकर बैठक, दावा-आपत्ति की जांच के लिए 9 टीमें गठित

बिभा संवाददाता

उधवा । उधवा प्रखंड सभागार कक्ष में बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के सुचारू संचालन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ सदानंद महतो ने किया। बैठक में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ जयंत कुमार तिवारी एवं अंचलाधिकारी आशीष कुमार मंडल भी उपस्थित रहें। इस दौरान निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह एसडीओ सदानंद महतो ने कहा कि एसआईआर के कार्य को पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए प्रपत्रों की जांच हेतु टीम गठित की गई है। उन्होंने बताया कि दावा-आपत्ति एवं नोटिस की जांच के लिए कुल 9 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये टीमें प्रतिदिन प्राप्त होने वाले नोटिसों का सत्यापन करेगी और निष्पादन में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को सहयोग करेगी। कहा कि एसआईआर एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर प्रभारी जीपीएस सह पर्यवेक्षक संतोष कुमार सुमन, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक हारून रशीद, अब्दुस सलाम, बाबूधन हेंब्रम, सत्यनारायण रजवार, प्रेमचंद रजक, नुकुल कुमार, मोनिका मुर्मू, ओमप्रकाश साहा, बिसंभर दास, शशि कपूर दुबे, सिकंदर अली, मो. सेराजुल हक, श्मामसुन मालतो, संतोष टुडू, मो. वसीम अख्तर, कम्प्यूटर ऑपरेटर फैयाज अहमद, रमीज राजा, देवाशीष साहा, हीरा साहा, चौकीदार सौरभ घोष, मम्पी कुमारी, सुमन कुमारी, पूजा कुमारी सहित अन्य मौजूद थे।

जल निकासी का रास्ता अवरूद्ध होने से घरों में घुसा बारिश का पानी

बिभा संवाददाता

उधवा । लगातार हो रही झमाझम बारिश से उधवा प्रखंड के मिर्जानगर गांव के ग्रामीणों की परेशानी काफी बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार उधवा मोड़ से पाकीजा मोड़ के बीच मुख्य सड़क के किनारे जल निकासी का रास्ता अवरुद्ध हो जाने के कारण घरों में जलजमाव हो गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों,आंगनों और बाड़ियों में भर गया है। जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर मिर्जानगर के दर्जनों ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा है। इस संदर्भ में ग्रामीण मुनीलाल मंडल,सुरेश मंडल,गुद्धू मंडल,प्रकाश मंडल,आरिफ रजा,पिंकू मंडल,अखिलेश मंडल,अर्जुन सिंह,संतोष मंडल,सिउली कुमारी,राजकुमार मंडल,राकेश मंडल,कंचन मंडल सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 60-70 वर्षों से मिर्जानगर गांव का सारा बारिश का पानी सरकारी पीडब्ल्यूडी की पुलिया से होकर उधवा मोड़ के समीप स्थित बड़े नाले में जाकर गिरता था। इसी निकासी के सहारे पूरा गांव सुरक्षित था। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा सरकारी पुलिया से होने वाली निकासी को बंद कर दिया गया है। जिससे पानी का निकासी पूरी तरह से बंद हो गया है। जलजमाव के कारण ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी से जल्द-जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है।

संक्षिप्त खबरें

सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मनाई गई गोस्वामी तुलसीदास जयंती

साहेबगंज (बिभा)। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर लालमाटी में बुधवार को संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई। विद्यालय के विशाल वंदना कक्ष में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ साहेबगंज के विभाग प्रमुख रमेश कुमार एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार उपाध्याय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर किया। साथ ही सामूहिक वंदना के बाद विद्यालय के आचार्य एवं दीदी जी ने भैया-बहनों को गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन एवं उनके साहित्यिक योगदान के बारे में जानकारी दी। वक्ताओं ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने तथा उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान प्रांत की योजना के अनुसार कक्षा द्वितीय एवं तृतीय के विद्यार्थियों के बीच सुलेख प्रतियोगिता तथा कक्षा चतुर्थ एवं पंचम के विद्यार्थियों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मौके पर विभाग प्रमुख रमेश कुमार, प्रधानाचार्य संतोष कुमार उपाध्याय सहित विद्यालय के सभी आचार्य एवं दीदी उपस्थित थे।

प्रबंधन समिति के निर्विरोध अध्यक्ष बने सूरज मंडल

उधवा(बिभा) । उधवा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेगमगंज में बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में बच्चों के अभिभावकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पर्यवेक्षक के रूप में संकुल साधन सेवी द्विजेंद्र नाथ मंडल एवं विजय मंडल उपस्थित रहें। इस दौरान सर्वसम्मति से सूरज मंडल को निर्विरोध प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जबकि पंचमी देवी को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सदस्य के रूप में उत्तम कुमार मंडल,अर्चना देवी,निमाय मंडल,विक्रम कुमार मंडल,लक्खी मंडल,पिंटू स्वर्णकार एवं रतन कर्मकार सहित अन्य को सदस्य चयन किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं नवनियुक्त प्रबंधन समिति अध्यक्ष सूरज मंडल ने कहा कि विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है,उसे निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक कार्य का निर्वहन करेंगे। मौके पर जिला परिषद सदस्य सहनारा बीबी,मुखिया प्रियंका कुमारी सहित अन्य मौजूद थे।

पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश

साहेबगंज(बिभा) । साहेबगंज महाविद्यालय साहेबगंज परिसर में बुधवार को पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 77 वां वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रमदान एवं पौधारोपण कर ह्यक्लीन साहेबगंज, ग्रीन साहेबगंज एवं हेल्दी साहेबगंजह्व का संदेश दिया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में साहेबगंज नगर परिषद के अध्यक्ष रामनाथ पासवान उपस्थित रहे। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया। वहीं मुख्य अतिथि रामनाथ पासवान ने वन महोत्सव के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव प्रयास करने की अपील की। वहीं प्राचार्य डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना और स्वच्छ एवं हरा-भरा वातावरण बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पौधारोपण के साथ-साथ लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने पर भी जोर दिया। मौके पर मैथिली विभागाध्यक्ष डॉ. ध्रुव ज्योति कुमार सिंह, लाइफ साइंस विभागाध्यक्ष डॉ. मीरा चौधरी, डॉ. संतोष कुमार चौधरी, डॉ. जीसू हसदा, डॉ. अनिल कुमार, डॉ. प्रिया सिंह, डॉ. अक्षय कुमार वर्मा, डॉ. रूपा दास, प्रो. कुमार प्रशांत भारती समेत अन्य प्राध्यापक, कर्मचारी एवं छात्र- छात्राएं उपस्थित रहे।

गुल्लीभट्ठा में चोरी का पदार्फाश, मुख्य आरोपी रायगंज जेल में, जेवरात बरामद

बिभा संवाददाता

साहेबगंज । नगर थाना क्षेत्र के गुल्लीभट्ठा में घर का ताला तोड़कर हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए चोरी गए जेवरात समेत अन्य सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग को निरुद्ध किया है, जबकि मुख्य आरोपी विशाल पासवान फिलहाल पश्चिम बंगाल के रायगंज करेक्शनल होम में न्यायिक हिरासत में है। वहीं पुलिस के अनुसार 14-15 अगस्त की रात गुल्लीभट्ठा निवासी ज्योति कुमारी के आवास का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर में चोरी की थी। मामले में ज्योति कुमारी के लिखित आवेदन पर नगर थाना कांड संख्या 150/26, दिनांक 16 अगस्त 2026 को बीएनएस की धारा 331(4)/305 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। टीम ने गुप्त सूचना, तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की। जांच में वादिनी के घर के सामने रहने वाले मंटू पासवान के दामाद विशाल पासवान और एक नाबालिग की संलिप्तता सामने आई। वहीं पुलिस टीम ने विशाल पासवान के ग्राम कंचनपॉली, थाना रायगंज, जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल स्थित आवास पर छापामारी की। जांच के दौरान पता चला कि विशाल पासवान पहले से रायगंज थाना कांड संख्या 943/26, दिनांक 16 अगस्त 2026, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(ए)/27 के मामले में रायगंज करेक्शनल होम में न्यायिक हिरासत में है। वहीं पुलिस ने बताया कि विशाल पासवान के घर में जमीन के अंदर छिपाकर रखे चोरी के सामान बरामद किए गए। वहीं, मामले में संलिप्त एक अन्य नाबालिग को सत्यापन के बाद निरुद्ध कर किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने चोरी गए सामान में एक सोने का मंगलसूत्र, सोने का गले का हार, सोने की चेन, कान के टॉप्स व बालियां, सोने का सिक्का, सोने का टॉप्स, पांच जोड़ी चांदी की पायल, चांदी की छोटी कटोरी, चांदी का सिक्का, चांदी की सिंदूरदानी, अंगूठी के दो सफेद व एक हरे रंग के स्टोन, सोने जैसा नाक का बेसर तथा एक नीले रंग का पिट्ठू बैग बरामद किया है।

पुलिस की कार्रवाई से चोरी की घटना का खुलासा होने के साथ ही चोरी गए अधिकांश सामान की बरामदगी भी हो गई है। मौके पर नगर थाना पुअनि गुलाम सरवर, पुअनि मो. आफताब अंसारी सहित पुलिस बल शामिल थे।

पीसी और पीएनडीटी समिति की बैठक में अल्ट्रासाउंड केंद्रों की निगरानी पर जोर

बिभा संवाददाता

साहेबगंज । समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में बुधवार को पीसी और पीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न पंजीकरण, नवीनीकरण और अल्ट्रासाउंड केंद्रों से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में प्रेम ज्योति कम्युनिटी हॉस्पिटल, बरमसिया द्वारा पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के तहत अवधि विस्तार और डॉ. बेथनी ग्रेस न्यूमैन के पंजीकरण संबंधी आवेदन पर जांच समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय अल्ट्रासाउंड और क्लिनिक उधवा बाजार के पंजीकरण आवेदन सूर्या सुपर स्पेशलिटी साहेबगंज में आईवीएफ के लिए पंजीकृत अल्ट्रासाउंड मशीन बदलने के प्रस्ताव,शिफा अल्ट्रासाउंड, बरहेट के पंजीकरण आवेदन तथा रूबी स्वास्थ्य केंद्र, राजमहल में चिकित्सक परिवर्तन से संबंधित आवेदन पर भी विचार किया गया। वहीं समिति ने नाहिद अल्ट्रासाउंड के औचक निरीक्षण से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब पर भी चर्चा की। जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों में कार्यरत चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित मानकों के अनुरूप अल्ट्रासाउंड करने की अनुमति से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने पीसी और पीएनडीटी अधिनियम और निर्धारित नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंजीकृत संस्थानों की नियमित निगरानी और निरीक्षण करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। मौके पर सिविल सर्जन डॉ. रामदेव पासवान, डॉ. मोहन मुर्मू, सहायक नोडल पदाधिकारी पीसी और पीएनडीटी डॉ. आशुतोष कुमार, सुरेश निर्मल समेत समिति के अन्य सदस्य और संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

जलापूर्ति योजनाओं की गुणवत्ता और प्रगति की हुई गहन समीक्षा

साहेबगंज । जिले में आमजनों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुचारू पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा की अध्यक्षता में बरहेट, पतना, बरहरवा व राजमहल प्रखंड की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया। कहा उपायुक्त द्वारा गठित तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के संयुक्त दल ने संबंधित योजनाओं का निरीक्षण कर भौतिक प्रगति, निर्माण कार्य की गुणवत्ता, जलापूर्ति की स्थिति, तकनीकी मानकों के अनुपालन तथा योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव की विस्तृत समीक्षा की। वहीं निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने योजनाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा ने निर्देश दिया कि जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। आम लोगों को नियमित एवं सुचारू पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं के संचालन और रख-रखाव में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जहां तकनीकी अथवा अन्य किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, वहां तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं निरीक्षण के दौरान संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, तकनीकी पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता मौजूद रहे। अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण दल को योजनाओं की वर्तमान प्रगति और कार्यों से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई।

देवघर श्रावणी मेला 2026: 21वें दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 2.38 लाख से अधिक कांवरियों ने किया जलार्पण

देवघर(बिभा): राजकीय श्रावणी मेला 2026 के 21वें दिन बाबा नगरी देवघर में शिवभक्तों का भारी उत्साह और जनसैलाब देखने को मिला। अहले सुबह 4:14 बजे कपाट खुलने के साथ ही बाबा बैद्यनाथ का जलार्पण शुरू हो गया, जो दिनभर अनवरत चलता रहा। इस 21वें दिन कुल 2,38,963 श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर मंगल कामना की। इनमें आंतरिक अर्घा के माध्यम से 1,15,857, बाह्य अर्घा से 1,08,695 और शीघ्र दर्शनम कूपन के जरिए 14,416 श्रद्धालुओं ने बाबा का जलार्पण किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मेला क्षेत्र में कतार प्रबंधन के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम (दफ्ळ), पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की 24 घंटे तैनाती सुनिश्चित की गई है। प्रशासन द्वारा पूरे रूट लाइन पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि देवघर आने वाले हर एक कांवरिये को बिना किसी परेशानी के सुगम, सुरक्षित और सुखद आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सके।

पहाड़गांव और उधवा चौक में आज रहेगी बिजली आपूर्ति बाधित

उधवा (बिभा)। 33 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र उधवा से निर्गत 11 केवी उधवा फीडर के अंतर्गत पहाड़गांव एवं उधवा चौक में गुरुवार को जर्जर विद्युत तार बदलने का कार्य किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए विद्युत कनीय अभियंता चंदन कुमार ने बताया कि गुरुवार को 11 केवी उधवा फीडर के अंतर्गत पहाड़गांव एवं उधवा चौक में जर्जर विद्युत तार बदलने का कार्य किया जाना है। उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्र में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि निर्धारित समय से पहले आवश्यक विद्युत संबंधी कार्य निपटा लें। कहा कि कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: 30.5 किलो पेड़ा सहित 72.5 किलो मिलावटी खाद्य सामग्री नष्ट

बिभा संवाददाता

देवघर : खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक सघन निरीक्षण अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत सत्संग, शिक्षा सभा चौक, चाँदनी चौक, भोला पंडा पथ, बैद्यनाथ लेन और सिंह द्वार क्षेत्र में स्थित 47 पेड़ा व मिठाई दुकानों और भोजनालयों में छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

निरीक्षण के दौरान सुभाष पेड़ा भंडार, अन्नपूर्णा स्वीट्स, द फूड क्वेस्ट रेस्टोरेंट, बाबा बैद्यनाथ पेड़ा भंडार, शिव पेड़ा भंडार सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई। जांच के क्रम में गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने के कारण कुल 30.5 किलोग्राम पेड़ा नष्ट कराया गया। वहीं, ऑन-स्पॉट जांच में अखाद्य रंग (हानिकारक रंग) की मिलावट पाए जाने पर चार भोजनालयों से 9 किलो दाल, 18 किलो सब्जी और 10 किलो चना-घुघनी नष्ट कराई गई। इसके अलावा 1 किलो मिलावटी हल्दी और 4 लीटर बार-बार इस्तेमाल किया हुआ खराब खाद्य तेल भी मौके पर ही फिंकवा दिया गया। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रथम दृष्टया मानक के अनुरूप पाए गए पेड़े के दो वैधानिक नमूने (सैंपल) भी लिए हैं, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने सभी संबंधित खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने की कड़ी चेतावनी दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ यह सघन जांच अभियान लगातार जारी रहेगा और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व रेलवे

खुली निविदा सूचना सं.: 48-एसडीएसटीई-एएसएन-2026-27, दिनांक 14.08.2026, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता, पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, आसनसोल, पिन-713301 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: **कार्य का नाम/स्थान:** "आसनसोल मंडल-आसनसोल में डीआरएम कार्यालय और रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी में सीसीटीवी की व्यवस्था और आसनसोल मंडल: विभिन्न स्टेशन/यार्ड में सीसीटीवी कैमरों की ज़रूरत"। **निविदा मूल्य:** रु. 1,19,45,872.65, **बयाना राशि:** रु. 2,38,900/-, **कार्य की समापन अवधि:** एलओए जारी करने की तिथि से 18 माह। **निविदा बंद होने की तिथि और समय:** 08.09.2026 को 14.00 बजे। **वेबसाइट का विवरण:** http://www. ireps.gov.in/

ASN-219/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

पूर्व रेलवे

खुली निविदा सूचना सं.: 49-एसडीएसटीई-एएसएन-2026-27, दिनांक 14.08.2026, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता, पूर्व रेलवे, आसनसोल मंडल, स्टेशन रोड, आसनसोल, पिन-713301 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: **कार्य का नाम/स्थान:** "आसनसोल मंडल - सीतारामपुर-झाझा मेन लाइन, मधुपुर-गिरिडीह और जसीडीह-बैद्यनाथधाम शाखा लाइन में लेवल क्रॉसिंग रोड की सतह को बेहतर बनाने के साथ पुराने, टूटे-फूटे गेट लॉज को बदलने सहित एसओडी उल्लंघन से बचने के लिए नए गेट लॉज का निर्माण करके गेट लॉज का स्थानांतरण"। **निविदा मूल्य:** रु. 1,29,85,681.59, **बयाना राशि:** रु. 2,59,700/-, **कार्य की समापन अवधि:** एलओए जारी करने की तिथि से 18 माह। **निविदा बंद होने की तिथि और समय:** 08.09.2026 को 14.00 बजे। **वेबसाइट का विवरण:** http://www. ireps.gov.in/

ASN-221/2026-27

निविदा सूचना वेबसाइट: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

संक्षिप्त डायरी

लोकभवन मार्च के चलते पटना में ट्रैफिक बदला, पटना जंक्शन-डाकबंगला समेत कई रूट पर वाहनों की नो एंट्री

पटना (एजेंसी) पटना में राष्ट्रीय जनता दल की लोकभवन मार्च के चलते शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. बुधवार सुबह 9 बजे से विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की गई है. पटना के गांधी मैदान में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल की आयोजित होने वाली लोकभवन मार्च के मद्देनजर यातायात पुलिस ने शहर में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था लागू की है. यह नया ट्रैफिक प्लान सुबह 9:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक रहेगी. शहर में जाम की स्थिति से निपटने और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के रूट में बदलाव किया है. ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें और पुलिस के निदेशों का पालन करें. प्रमुख मार्गों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित पटना जंक्शन की ओर से डाकबंगला चौराहा जाने वाले वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और उन्हें दूसरे रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा. इनकम टैक्स चौराहा से मंदिरी नाला की ओर जाने वाले मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. व्यावसायिक वाहनों और ऑटो-ई-रिक्शा के रूट में बदलाव गांधी मैदान के चारों तरफ व्यावसायिक वाहनों, विशेषकर ऑटो और ई-रिक्शा के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. दानापुर से राजापुर पुल आने वाले ऑटो/ई-रिक्शा को पुलिस लाइन तिराहा से वापस दानापुर की ओर मोड़ दिया जाएगा. गायघाट से आने वाले ऑटो कारगिल चौक से डबल डेकर के पश्चिमी छोर से वापस लौटेंगे. इन अन्य मार्गों पर भी वाहनों का परिचालन रहेगा बंद एग्जीबिशन रोड (भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर), बुद्धमार्ग/छज्जूबाग (टी एन बनर्जी पथ), पुलिस लाइन से बैंक रोड और बुद्ध मार्ग पुलिस लाइन तिराहा से कोतवाली टी तक ऑटो/ई-रिक्शा का परिचालन बंद रहेगा. सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम राजद के लोकभवन मार्च को लेकर पटना में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं. अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की तैनाती की गई है.

तेजस्वी का राजभवन मार्च बना रणक्षेत्र: बैरिकेडिंग तोड़ी, वाटर कैनन चला और फिर हिरासत में नेता प्रतिपक्ष

पटना (एजेंसी) बिहार में पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्र आंदोलनों के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के राजभवन मार्च के दौरान पटना में हंगामा हो गया। जेपी गोलंबर से मार्च शुरू होने के बाद डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर मार्च रोकने की कोशिश की। बिहार में पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन और बेरोजगारी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकला आरजेडी का राजभवन मार्च पुलिस कार्रवाई के बाद हंगामे में बदल गया। जेपी गोलंबर से शुरू हुए मार्च में तेजस्वी यादव के साथ हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने मार्च रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन तेजस्वी अपने समर्थकों के साथ बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ गए। इसके बाद इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

कार्रवाई के बाद तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने के दौरान उन्होंने कहा कि वह जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी ने कहा, ₹हमारे भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ था।जेपी गोलंबर से शुरू हुआ मार्च राजभवन मार्च के लिए आरजेडी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेपी गोलंबर पर जुटे। तेजस्वी यादव ने मार्च शुरू करने से पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण को नमन किया। इसके बाद वह कार्यकताओं के साथ राजभवन की ओर रवाना हुए। पुलिस ने डाकबंगला चौराहे के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ बैरिकेडिंग की गई थी। यहीं से मार्च को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई।

बैरिकेडिंग के बाद वाटर कैनन, तेजस्वी हिरासत में डाकबंगला चौराहे पर पुलिस की बैरिकेडिंग के बावजूद तेजस्वी यादव और आरजेडी कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कार्रवाई के बाद तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने के दौरान तेजस्वी ने कहा कि वह जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण का जिक्र करते हुए कहा कि उनके भगवान का जन्म भी जेल में ही हुआ था। मीसा भारती ने भी सरकार पर साधा निशाना आरजेडी सांसद मीसा भारती भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकले मार्च में शामिल हुईं। उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों-युवाओं की समस्याओं को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। मीसा भारती ने कहा कि उन्होंने सुना है कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के खिलाफ एके-47 के इस्तेमाल की बात स्वीकार की है। उन्होंने सवाल किया कि प्रदर्शन के दौरान एके-47 के इस्तेमाल की अनुमति किसने दी थी। मीसा भारती ने कहा कि अगर इसकी अनुमति जिला मजिस्ट्रेट ने दी थी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर एके-47 से गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोलीबारी की गई। उनके मुताबिक, सीवान में तीन लोगों को गोली लगी थी और उनका इलाज पटना के मेदांता अस्पताल में कराया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि आरोपी जवान के पास एके-47 कैसे पहुंची, हथियार किस यूनिट या शस्त्रागार से जारी हुआ और उसे जारी करने का आदेश किस अधिकारी ने दिया। तेजस्वी ने हथियार जारी करने से लेकर फायरिंग के आदेश तक की पूरी कमांड चेन सार्वजनिक करने की मांग की। 'सिर्फ सिपाही पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा' तेजस्वी यादव ने कहा कि मामले में यह भी सामने आना चाहिए कि आरोपी सिपाही किस यूनिट में तैनात था। क्या वह जिला पुलिस, एसपी की सुरक्षा, एसटीएफ या किसी अन्य विशेष इकाई का हिस्सा था, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि भीड़ नियंत्रण के दौरान फायरिंग की अनुमति किसने दी और गोली चलाने का आदेश किस अधिकारी ने दिया। तेजस्वी ने सीवान के एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि केवल सिपाही पर कार्रवाई करके मामले को खत्म नहीं किया जा सकता।

भागलपुर से बंगाल का सफर होगा आरामदायक, कोलकाता-दुगार्पुर-सिलीगुड़ी के लिए चलेगी सरकारी AC बस

पटना (एजेंसी) भागलपुर से पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरों जैसे कोलकाता, दुगार्पुर और सिलीगुड़ी के लिए सरकारी एसी बस सेवा जल्द शुरू होने वाली है. नवंबर में 11 नई एसी बसों के आने से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में आराम मिलेगा. भागलपुर से बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब कोलकाता और दुगार्पुर जैसे शहरों के लिए सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही सरकारी एसी बस की सुविधा मिल सकेगी. पथ परिवहन निगम के भागलपुर प्रमंडल को नवंबर में 11 नई एसी बसें मिलने जा रही हैं. इनमें चार बसें भागलपुर डिपो को मिलेंगी. इन बसों का परिचालन छठ पूजा तक शुरू करने की तैयारी है. यानी इस साल छठ के आसपास यात्रियों को लंबी दूरी के सफर के लिए सरकारी एसी बस का नया

विकल्प मिल सकता है. खास बात यह है कि भागलपुर पथ परिवहन निगम को पहली बार एसी बस मिलने जा रही है. कोलकाता और दुगार्पुर के साथ सिलीगुड़ी तक मिलेगी बस नई एसी बसों के आने के बाद भागलपुर से पश्चिम बंगाल के कोलकाता और दुगार्पुर के लिए बस सेवा शुरू करने की योजना है. इसके अलावा सिलीगुड़ी के लिए भी बस चलाने की तैयारी है. अभी भागलपुर पथ परिवहन निगम की ओर से बंगाल के लिए नियमित बस सेवा नहीं है. लंबी दूरी की यात्रा के लिए एसी बस उपलब्ध नहीं होने को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है. अब सरकारी बेड़े में एसी बस शामिल होने के बाद इस कमी को दूर करने की कोशिश होगी. इससे भागलपुर के अलावा आसपास के जिलों के यात्रियों को भी लाभ मिल सकता है. यात्रियों को लंबी दूरी के सफर के लिए ट्रेन के अलावा सरकारी बस का विकल्प मिलेगा. भागलपुर को चार, मुंगेर-जमुई को तीन-तीन बसें पथ परिवहन निगम के भागलपुर प्रमंडल के लिए कुल 11 एसी बसें उपलब्ध करायी जायेंगी. इनमें चार बस भागलपुर पथ परिवहन निगम डिपो को मिलेंगी. वहीं मुंगेर और जमुई डिपो को तीन-तीन एसी बस दी जायेंगी. भागलपुर डिपो में अब तक कई नई बसें आयी हैं, लेकिन एसी बस का इंतजार बना हुआ था. पहली बार एसी बस मिलने से डिपो की लंबी दूरी की बस सेवा को विस्तार मिलने की उम्मीद है. दूर के सफर में यात्रियों को मिलेगा आराम भागलपुर से कोलकाता, दुगार्पुर और सिलीगुड़ी की दूरी काफी अधिक है. ऐसे में एसी बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को गर्मी और लंबी यात्रा के दौरान अपेक्षाकृत आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा. अभी इन मार्गों पर निजी ऑपरेटरों की एसी बसें, खासकर रात के समय, चलती हैं. पटना से आयी चार बसों को भी सावन के बाद रांची और बोकारो के लिए चलाने की तैयारी है. इसके लिए पथ परिवहन निगम भागलपुर की ओर से झारखंड का परमिट लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. परमिट मिलने के बाद इन बसों का परिचालन शुरू किया जायेगा. रांची और बोकारो के लिए बस सेवा शुरू करने की योजना लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब इसे धरातल पर उतारने की तैयारी तेज हो गयी है. रांची-बोकारो के लिए तय हुआ रूट रांची और बोकारो के लिए बस परिचालन का रूट भी तय किया जा चुका है. इससे भागलपुर के यात्रियों को झारखंड की ओर जाने के लिए सरकारी बस सेवा का विकल्प मिलेगा. फिलहाल डिक्सन मोड़ से रांची और झारखंड के अन्य जिलों के लिए निजी बसों का परिचालन होता है. सरकारी बस सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों को परिवहन का एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होगा. छठ से पहले बस सेवा शुरू करने की तैयारी भागलपुर प्रमंडल में नवंबर में 11 एसी बसें मिलने की उम्मीद है. विभाग की योजना इन बसों को छठ पूजा तक परिचालन में लाने की है. छठ के दौरान बिहार और दूसरे राज्यों के बीच यात्रियों की आवाजाही काफी बढ़ जाती है. ऐसे में यदि निर्धारित समय पर बसें उपलब्ध हो जाती हैं

BPSC TRE-4 का नोटिफिकेशन फिर भी नहीं थमा छात्रों का आंदोलन, आखिर क्यों धरने पर डटे हैं अभ्यर्थी जानिए क्या हैं मांगें

पटना (एजेंसी) सवाल है कि जब 32,388 पदों पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है, तो फिर छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? दरअसल, अभ्यर्थियों की कुछ ऐसी मांगें हैं, जिन पर अभी सहमति नहीं बनी है. नोटिफिकेशन में क्या है? मंगलवार को आंदोलन के बीच की अधिसूचना जारी की. इसके तहत 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती होगी. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी. अभ्यर्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे. नोटिफिकेशन आने के बाद भर्ती को लेकर लंबे समय से चला आ रहा इंतजार खत्म हुआ. लेकिन छात्रों का विरोध खत्म नहीं हुआ. आखिर आंदोलन क्यों जारी है? छात्रों का कहना है कि सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होना उनकी सभी मांगों का समाधान नहीं है. वे के परीक्षा पैटर्न और भर्ती प्रक्रिया में

बदलाव की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा की परीक्षाओं और संविदाकर्मियों से जुड़े मुद्दे भी उनके आंदोलन का हिस्सा हैं. की परीक्षा को लेकर है. अभ्यर्थी सिंगल एग्जाम यानी एकल परीक्षा प्रणाली चाहते हैं. उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती के लिए दो चरणों की परीक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए. वे एक ही परीक्षा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे हैं. निगेटिव मार्किंग हटाने की मांग अभ्यर्थियों की दूसरी प्रमुख मांग निगेटिव मार्किंग खत्म करने की है. छात्र चाहते हैं कि की परीक्षा में गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटे जाएं. उनका तर्क है कि परीक्षा को अभ्यर्थियों के लिए ज्यादा पारदर्शी और सहज बनाया जाना चाहिए. संविदा कर्मचारियों के वेटेज का भी विरोध छात्रों की एक और मांग संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले अतिरिक्त अंकों यानी वेटेज से जुड़ी है. अभ्यर्थी इस वेटेज को खत्म करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर होना चाहिए. तेजस्वी और दीपांकर भी पहुंचे धरनास्थल मंगलवार को आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को राजनीतिक समर्थन भी मिला. के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव धरनास्थल पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की. वहीं भाकपा-माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी छात्रों के बीच पहुंचे. दोनों नेताओं ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया. हालांकि, छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है. उनका फोकस अपनी मांगों को पूरा कराने पर है. 'मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन' छात्र नेता दिलीप ने आंदोलन को लेकर राज्यभर के अभ्यर्थियों से गर्दनीबाग पहुंचने की अपील की है. उनका कहना है कि नोटिफिकेशन जारी होना अच्छी बात है, लेकिन अभी छात्रों की सभी मांगें पूरी नहीं हुई हैं. दिलीप के मुताबिक, जब तक छात्रों की जायज मांगों पर फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा. अब सवाल, आगे क्या होगा? -4 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है. 1 सितंबर से आवेदन भी शुरू हो जाएंगे. लेकिन गर्दनीबाग में छात्रों का धरना यह साफ कर रहा है कि नोटिफिकेशन उनकी मंजिल नहीं है. वे परीक्षा के पैटर्न, निगेटिव मार्किंग, की लंबित परीक्षाओं और संविदा वेटेज जैसे मुद्दों पर फैसला चाहते हैं.

बिहार के इन 11 जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट, 21 अगस्त तक के लिए IMD की एडवाइजरी जारी

पटना (एजेंसी) बिहार का मौसम इन दिनों खुशनुमा बना हुआ है. कई जिलों में रुक-रुककर बारिश हो रही है जबकि कुछ जिलों में दिनभर बादलों की आवाजाही रह रही. ऐसे में मौसम विभाग ने आज 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. : बिहार में इन दिनों रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है. लगभग सभी जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. इस बीच आज मौसम विभाग ने 11 जिलों में अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में भारी बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है. इस दौरान बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है. इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. साथ ही औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले में बारिश की गतिविधियां ज्यादा रह सकतीं हैं. बिगड़े मौसम के दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है. खासकर किसानों को खराब मौसम में खेतों में काम नहीं करने की सलाह दी गई है. अभी भी सामान्य से कम हुई बारिश मौसम विभाग की माने तो, अब भी बिहार में सामान्य से कम ही बारिश हो पाई है. अभी तक बारिश दर्ज की गई जबकि बारिश होनी चाहिए थी. इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 41 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. लेकिन यह भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं. आगे कैसा रहेगा मौसम? मौसम पूवार्नुमान की माने तो, बिहार के जिलों में 20 और 21 अगस्त को भी कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा. 20 अगस्त की बात करें तो, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिले में ऑरेंज अलर्ट है. बिहार से जुड़ी अन्य ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें जबकि 21 अगस्त को मौसम विभाग ने कुछ जिलों जैसे कि खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई को छोड़कर बाकी के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इस दिन पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, अररिया और किशनगंज में भयंकर बारिश की चेतावनी है. साथ ही तेज हवा और बिजली गिरने का भी पूवार्नुमान जारी किया गया है. इस तरह से उमस वाली गर्मी से लोगों को अभी राहत मिलती रहेगी. राज्य में हो रही बारिश की वजह बिहार में लगातार रुक-रुककर हो रही बारिश को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर बना हुआ है.

तेजस्वी यादव करेंगे राजभवन मार्च, इन रूटों से गुजरेंगे प्रदर्शनकारी, सरकार से लालू बोले- यूथ का फ्यूचर मत खाओ

पटना (एजेंसी) नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज राजभवन मार्च करेंगे. गांधी मैदान से मार्च की शुरूआत होगी. इसकी तैयारी कर ली गई है. तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ स्टूडेंट्स यूनियन से भी जुटने की अपील की है. बिहार के सीवान जिले में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अङ-47 से फायरिंग करने और छात्रों के मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष आज सड़क पर उतरेंगे. राजधानी के गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च किया जाएगा. इसे लेकर तैयारी कर ली गई है. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है. गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों से की थी

मुलाकात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को गर्दनीबाग जाकर अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी. उस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों को समर्थन दिया था. साथ ही सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा था, अहंकारी सरकार को जल्द ही छात्रों की मांग को गंभीरता से सुनकर पूरा करना चाहिए. पटना के धरना स्थल गर्दनीबाग में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी राजभवन मार्च को लेकर तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पार्टी के कार्यकताओं और स्टूडेंट्स यूनियन से जुटने की अपील की थी. तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने लिखा था, 'सुबह 10 बजे गांधी मैदान से शुरू होकर बिहार का यूथ करेगा राजभवन कूच. परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, नियमितता और जवाबदेही सुनिश्चित कराने हेतु छात्रों और युवाओं का विशाल मार्च.' इतना ही नहीं लालू प्रसाद ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर सरकार पर तंज कसा था. उन्होंने लिखा था, 'दाल-भात खाओ बट यूथ का फ्यूचर मत खाओ.' इससे पहले मंगलवार को भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लोगों से जुटने की अपील की थी. उन्होंने लिखा था, 'समस्त छात्र-युवा शक्ति पेपरलीक, बदहाल शिक्षा प्रणाली, पक्षपातपूर्ण बहाली प्रक्रिया और बेरोजगारी से त्रस्त है. लूट तंत्र से बनी दंभी सरकार उनकी लोकतांत्रिक मांगों को सुनने की बजाय से गोलियां बरसाती है, यह अन्यायपूर्ण है. इस तानाशाही के विरुद्ध सभी 19 अगस्त को पटना में एकजुट हो.' बिहार से जुड़ी अन्य ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें इन रूटों से गुजरेगा मार्च जानकारी के मुताबिक, पटना के जेपी गोलंबर से मार्च की शुरूआत होगी. इसके बाद डाकबंगला चौराहा, तारामंडल, इनकम टैक्स गोलंबर, पटना वीमेंस कॉलेज, बिहार म्यूजियम, विश्वसरैया भवन, पंचमुखी हनुमान मंदिर, बेली रोड से होते हुए लोकभवन तक जायेगा. इस तरह से मार्च को लेकर ट्रैफिक रूटों में भी बदलाव किया गया है. पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है. तेजस्वी यादव ने किए थे ये 15 सवाल छात्रों पर गोलीबारी करने वाले सिपाही के पासआई कैसे? निलंबित सिपाही को अङ-47 किस यूनिट या शस्त्रागार से जारी की गई? हथियार जारी करने का आदेश किसने दिया? जैसे आधुनिक हथियार के आवंटन की पूरी कमांड-चेन की भूमिका सामने आनी चाहिए. आरोपित सिपाही किस यूनिट में तैनात था? क्या वह नियमित जिला पुलिस का हिस्सा था? क्या वह रढ की सुरक्षा में तैनात था या जैसी विशेष इकाई से संबद्ध था? क्या वह आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन से जुड़ा था? यदि वह विशेष बल का जवान था तो उसकी वास्तविक तैनाती और जिम्मेदारी क्या थी? क्या इससे पूर्व कभी छात्र प्रदर्शन में अङ-47 का इस्तेमाल हुआ था? सामान्य कानून-व्यवस्था या छात्र प्रदर्शन की ड्यूटी में इतनी मारक क्षमता वाले हथियार की जरूरत क्यों पड़ी? लेकर भीड़ नियंत्रण की अनुमति थी? फायरिंग का आदेश किसने दिया? जिले के पुलिस अधीक्षक पर अभी तक कारवाई क्यों नहीं हुई? कितनी गोलियां चलीं और कितने राउंड जारी हुए थे? हथियार के साथ जारी किए गए और इस्तेमाल हुए कारतूसों का हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए. इस्तेमाल किए गए हथियार का बैलिस्टिक और फॉरेंसिक परीक्षण हुआ या नहीं? क्या बॉडी कैमरा या वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है? फायरिंग से ठीक पहले और बाद की पूरी गतिविधि सामने आनी चाहिए. यदि अङ-47 गलत ड्यूटी पर पहुंची तो केवल सिपाही को निलंबित करना पर्याप्त है या हथियार जारी करने वाले अधिकारी की भी जवाबदेही तय होगी? कमांड-चेन की जांच होगी या नहीं? जांच केवल गोली चलाने वाले जवान तक सीमित न रहकर ऊपर के अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए? अङ-47 जैसे विशेष आधुनिक हथियार के लिए विशेष जिम्मेदारी होती है. इसके इस्तेमाल में प्रशिक्षण, आदेश और जवाबदेही तीनों महत्वपूर्ण हैं

सोने-चांदी में नरमी

मुम्बई ।

घरेलू बाजार में बुधवार को सोने और चांदी में तेज गिरावट रही। ये गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के चलते आई है। सुबह सोने के वायदा भाव में 362 रुपये जबकि चांदी में 2,418 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई। इस बड़ी गिरावट का मुख्य कारण 30 साल के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड का 19 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचना रहा। हालांकि, फेडरल रिजर्व द्वारा निकट भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम होने के कारण सोना और चांदी के लिए एक सकारात्मक कारक बना हुआ है, जो भविष्य में कीमतों को सहारा दे सकता है।वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर, सोना 4,410 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रहा था जबकि चांदी 63 प्रति औंस के करीब थी। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर, सोने के वायदा भाव 1,54,200 रुपये के स्तर पर थे जबकि चांदी के भाव करीब 2,30,250 के आसपास थे। एमसीएक्स पर सोने के अक्टूबर अनुबंध की शुरुआत 362 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,900 पर हुई। इसका पिछला बंद भाव 1,54,262 रुपये था। दिन के कारोबार के दौरान, यह अनुबुंध 69 रुपये की गिरावट के साथ 1,54,193 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जिसने दिन में कीमतें 1,53,900 रुपये के निचला स्तर और 1,54,326 के उच्च स्तर पर पहुंची। इस साल सोना 1,80,779 रुपये के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा था। वहीं चांदी के सितंबर अनुबंध की भी कमजोर शुरुआत रही उसमें 2,418 रुपये की बड़ी गिरावट देखी गई और यह 2,30,001 पर खुली। इसका पिछला बंद भाव 2,32,419 रुपये था। कारोबार के समय यह अनुबंध् 2,181 की गिरावट के साथ ही 2,30,238 रुपये पर था, जिसने दिन के दौरान 2,29,666 रुपये का निचला और 2,30,528 रुपये का उच्च स्तर हासिल किया। चांदी इस साल 4,20,048 प्रति किलो के उच्चतम स्तर पर पहुंची। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर सोने के वायदा भाव 4,391.40 डॉलर प्रति औंस पर खुले, जो अपने पिछले बंद भाव 4,420.60 से कम थे। कारोबार के दौरान यह 11.20 रुपये की गिरावट के साथ 4,409.40 प्रति औंस पर थे। इस साल सोने ने 5,586.20 डॉलर का रिकॉर्ड उच्च स्तर देखा। इसी तरह, कॉमैक्स पर चांदी के वायदा भाव 63.42 डॉलर पर खुले, जो पिछले बंद भाव 64.03 डॉलर से नीचे था।

बेहारी लाल इंजीनियरिंग के शेयर को लेकर निवेशकों में काफी उत्साह

लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर को लेकर मिल रहे मजबूत संकेत

नई दिल्ली,। बेहारी लाल इंजीनियरिंग के शेयर बुधवार को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने जा रहे हैं। कंपनी के शुरुआती सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ को लेकर निवेशकों में काफी उत्साह है। 17 अगस्त को शेयर आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सभी की नजर लिस्टिंग पर है। लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर को लेकर मजबूत संकेत मिल रहे हैं। बुधवार सुबह शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 133 रुपए चल रहा था। कंपनी ने आईपीओ में शेयर का ऊपरी मूल्य बैंड 285 रुपए तय किया था। इस हिसाब से संभावित लिस्टिंग कीमत करीब 418 रुपए होती है यानी इश्यू मूल्य के मुकाबले करीब 46.67 फीसदी प्रीमियम पर शेयर सूचीबद्ध होने का अनुमान लगाया जा रहा था। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अनौपचारिक संकेत होता है और वास्तविक लिस्टिंग कीमत इससे अलग हो सकती है।बेहारी लाल इंजीनियरिंग का आईपीओ 301.62 करोड़ रुपए था। इसमें 93 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए गए, जबकि 208.62 करोड़ रुपए का हिस्सा ऑफर फॉर सेल के जरिए था। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 271 से 285 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। निवेशकों को न्यूनतम 52 शेयरों के लिए आवेदन करना था। ऊपरी मूल्य बैंड के आधार पर खुदरा निवेशकों का न्यूनतम निवेश 14,820 रुपए था। बता दें कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। यह लौह और इस्पात से जुड़े उत्पादों के अलावा विभिन्न उद्योगों के लिए इंजीनियरिंग उत्पाद बनाती है। इसके उत्पादों में मेटल रोल्स, इंजीनियरिंग कास्टिंग, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद, फोर्जिंग इंगोट्स और फोर्ज्ड शाफ्ट शामिल हैं।31 मार्च 2026 तक कंपनी के ग्राहक आधार में भारत और विदेशों के 1,825 ग्राहक शामिल थे। इसकी विनिर्माण इकाइयां पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में हैं। 31 मई 2026 तक कंपनी के पास करीब 178.57 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक था। अब निवेशकों की नजर इस बात पर है कि शेयर बाजार में लिस्टिंग के दौरान ग्रे मार्केट में दिख रहा उत्साह कितना बरकरार रहता है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 325, निफ्टी 76 अंक गिरा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भी गिरावट रही। वहीं गत दिवस भी ये गिरा था। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण कच्चे तेज की कीमतें बढ़ने से भी घरेलू बाजार पर दबाव पड़ा है। बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई।

आज कारोबार के दौरान पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, आईटीसी के शेयर गिरे हालांकि, कुछ आईटी शेयरों ने बाजार की इस गिरावट को थामा।

दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 325.78 अंक की गिरावट के साथ ही 76,909.68 अंकों पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 76.60 अंकों की गिरावट के साथ ही 24,078.30 अंकों पर बंद हुआ।

बाजार की व्यापक स्थिति कमजोर रही। सेंसेक्स में सूचीबद्ध 30 कंपनियों में से केवल 8 के शेयर ही लाभ के साथ बंद हुए। वहीं 21 अन्य में गिरावट रही। इसी तरह, निफ्टी की 50 कंपनियों में से 34 के शेयर नीये आये जबकि केवल 16 में तेजी दर्ज की गई।

सरकारी बिजली कंपनी पावर ग्रिड के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.00 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई, जो सेंसेक्स के लिए सबसे बड़ा झटका था। इसके विपरीत, आईटी क्षेत्र से एचसीएल टेक का शेयर 1.73 फीसदी की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा

गिरावट दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में बजाज फाइनेंस , एलएंडटी , आईटीसी , हिंदुस्तान यूनिलीवर आदि रहे जबकि कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा , टाइटन , टीसीएस , इन्फोसिस और ट्रेंट के शेयरों में तेजी रही। बजाज फिनसर्व के शेयर बिना किसी बदलाव के सपाट रहे।

इससे पहले आज सुबह

सेंसेक्स करीब 94.57 अंक की गिरावट के साथ 77,140.89 के स्तर पर कारोबार कर रहा था जबकि 50 शेयरों वाल एनएसई निफ्टी50 भी 38.30 अंक फिसलकर 24,116.60 पर पहुंच गया।वैश्विक बाजारों में भी कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। अमेरिकी शेयर बाजारों में मंगलवार को नैस्डैक कंपोजिट 1.33 फीसदी और एसएंडपी 500 0.69 फीसदी की गिरावट के साथ लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरे। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी लगभग 0.2 फीसदी नीचे बंद हुआ।दूसरी ओर एशियाई बाजारों में भी बिकवाली का दबाव बढ़ा हुआ था। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स लगभग 4.2 फीसदी तक गिर गया।

कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी

मुम्बई ।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड (कच्चे तेल) की बढ़ती कीमतों में तेजी आई है। ऐसे में अभी पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने की जगह बढ़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ किसी भ्री तरह से बातचीत करने से इंकार करने के बाद से ही करने के बयान के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतें 91 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई हैं। आज सुबह कच्चा तेल 38 सेंट चढ़कर 91.40 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया जबकि डब्लयूटीआई क्रूड 45 सेंट की बढ़त के साथ ही 85.30 डॉलर प्रति बैरल पर था। कच्चे तेल की कीमतों में आये इस उछाल से ईंधन की कीमतें बढ़ना तय है।

एक अनुमान के मुताबिक, एक बैरल कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर की बढ़ोतरी से कंपनियों को प्रति लीटर लगभग 6 रुपये का नुकसान होता है।

वहीं देश में आज पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है। इसके साथ ही, एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ।

बाल यौन शोषण सामग्री कानून का उल्लंघन, मेटा से बातचीत के बाद सरकार सख्त

नई दिल्ली।

अमेरिकी कंपनी मेटा के साथ सरकार की बातचीत के बाद बाल यौन शोषण सामग्री के मुद्दे पर कार्रवाई में तेजी आई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने साफ कर दिया है कि ऐसी सामग्री कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और इस तरह का उल्लंघन होने पर 'सेफ हार्बर' का संरक्षण नहीं मिलेगा। 'सेफ हार्बर' एक कानूनी प्रावधान है जो इंटरनेट मध्यस्थों और सोशल मीडिया मंचों को उपयोगकर्ताओं द्वारा 'पोस्ट' की गई सामग्री के लिए कानूनी जिम्मेदारी या मुकदमों से बचाता है।सूत्रों ने बताया कि सरकार का मकसद 'सेंसरशिप' या किसी भी तरह से 'कवरेज' को सीमित करना नहीं है, बल्कि भारतीय कानूनों और नियमों का पालन तय करना और सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान को कम करना है। उन्होंने कहा कि संदेश पहुंच गया है। आईटी मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि मेटा ने सीएसएएम पर बढ़ी हुई संवेदनशीलता और सावधानी दिखाई है और हालिया चर्चाओं के बाद सरकार को कंपनी द्वारा कुछ कार्रवाई होती दिख रही है। सूत्रों ने इस प्रतिक्रिया को 'महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय' बताया। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि बातचीत में मेटा ने बताया कि उसके 'एल्गोरिदम' और प्रणालियां कैसे काम करती हैं।

एफसीएनआर (बी) स्वैप योजना बंद- बॉन्ड बाजार पर दबाव, यील्ड में वृद्धि

नई दिल्ली,।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एफसीएनआर (बी) स्वैप योजना के समय से पहले बंद होने से बॉन्ड बाजार पर, विशेषकर अल्पावधि बॉन्ड खंड पर दबाव बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप, पांच वर्षीय बॉन्ड की यील्ड 6.44 प्रतिशत से बढ़कर 6.46 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

बीते दो कारोबारी सत्रों में पांच वर्षीय बॉन्ड की यील्ड में करीब 10 आधार अंक की वृद्धि दर्ज की गई। 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की यील्ड भी 6.81 प्रतिशत से बढ़कर 6.83 प्रतिशत पर बंद हुई। डीलरों का अनुमान है कि अगस्त के अंत तक यह 6.85 प्रतिशत के करीब पहुंच सकती है। गौरतलब है कि आरबीआई की योजना ने पहले अल्पावधि बॉन्ड को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की थी।

बाजार के जानकारों के अनुसार, कारोबारियों ने एफसीएनआर (बी) के तहत 3 से 5 साल की अवधि के लिए आने वाली जमा की उम्मीद में पांच वर्षीय बॉन्ड में बड़ी पोजीशन बनाई थीं। योजना के अचानक बंद होने से इन पोजीशन को समाप्त किया जा रहा है, जिससे कम अवधि वाले बॉन्ड खंड पर

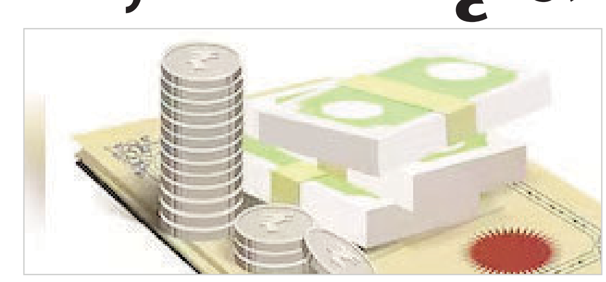

अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। प्राइमरी डीलरशिप के वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की, कारोबारियों ने 5 वर्षीय बॉन्ड में ज्यादा पोजीशन बनाई थीं और अब उन्हें खत्म किया जा रहा है। एफसीएनआर (बी) स्वैप योजना के समाप्त होने के साथ ही, बाजार का ध्यान अब फिर से वैश्विक कारकों, विशेष तौर पर अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों पर केंद्रित हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि एफसीएनआर (बी) सुविधा बॉन्ड बाजार के लिए एक सकारात्मक कारक थी और इसने बाजार को स्थिरता बनाए रखने में मदद की थी।

भारत में डीपटेक फंडिंग का बोलबाला, 11.4 अरब डॉलर का आंकड़ा पार

पिछले छह सालों में आया 85 फीसदी से ज्यादा निवेश

नई दिल्ली।

इंडियन वेंचर ऐंड ऑल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय डीपटेक सेक्टर में वर्ष 2015 से अब तक कुल 11.4 अरब डॉलर का भारी निवेश आया है। इस फंडिंग का 85 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा पिछले छह सालों में ही जुटाया गया है, जो देश के डीपटेक इकोसिस्टम के तेजी से परिपक्व होने और वाणिज्यिक सफलता की ओर बढ़ने का स्पष्ट संकेत देता है। आईवीसीए के आंकड़ों के मुताबिक डीपटेक सेक्टर में निवेश में अभूतपूर्व उछाल आया है। वर्ष 2025 फंडिंग के लिहाज से अब तक का सबसे सफल साल रहा, जब डीपटेक स्टार्टअप्स ने रिकॉर्ड 189 राउंड में 2.9 अरब डॉलर जुटाए। वर्ष 2026 में भी यह गति जारी है और कंपनियों ने 103 राउंड में लगभग 1 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई है।

2021 के बाद से फंडिंग में आई यह तेजी साफ तौर पर दर्शाती है कि डीपटेक कंपनियां अब शुरुआती चरण से निकलकर वाणिज्यिक मजबूती की ओर अग्रसर हैं।

इस तेजी का प्रमाण हाल के उदाहरणों में देखा जा सकता है, जैसे स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा पहले प्राइवेट ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट का सफल लॉन्च और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नेसा का 1.2 अरब डॉलर का फंडिंग राउंड, जिसने उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दिलाया। 2015 से 2026 के बीच ब्लूम वेंचर्स (51 सौदे), स्पेशल इन्वेस्ट (50 सौदे) और एक्सेल इंडिया (48 सौदे) सबसे सक्रिय डीपटेक निवेशक रहे। इसी अवधि में, डीपटेक कंपनियों ने 61 सौदों के माध्यम से वेंचर ऋण के रूप में कुल 54.4 करोड़ डॉलर की पूंजी भी जुटाई। हालांकि, निवेश से बाहर निकलने (एक्जिट) के लिए विलय एवं अधिग्रहण को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा सेकंडरी बिक्री (56 फीसदी) ही देखने को मिली हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 62 प्रतिशत फंडों ने एक्जिट की स्पष्टता को एक बड़ी चुनौती माना है।

आईपीओ भी एक विकल्प है, लेकिन इसके लिए ग्रोथ-स्टेज कैपिटल की अधिक आवश्यकता होती है।

पिछले साल 18 बिकवाली सौदों से 60 करोड़ डॉलर मिले, जबकि 2024 में 7 एक्जिट से 15.2 करोड़ डॉलर जुटाए गए। डीपटेक स्टार्टअप वे उद्यम हैं जो नई वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग प्रगति पर आधारित समाधान विकसित करते हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस-टेक, रक्षा और एयरोस्पेस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नॉलजी और अन्य उन्नत क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं।

भारत का डीपटेक सेक्टर भविष्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया 18 पैसे की बढ़त के साथ ही 95.57 पर बंद हुआ। वही गत दिवस रुपया 95.74 पर बंद हुआ। आज सबह रुपया 95.72 पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में गत दिवस रुपया 95.68 प्रति डॉलर पर खुला रुपया सोमवार को 19 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.61 पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 फीसद टूटकर 99.63 पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि ब्रेंट कच्चा तेल की कीमत के करीब 91 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने से तेल से संबंधित डॉलर की मांग में वृद्धि हुई है।

ओपनएआई ने किशोरों के लिए शुरु किया नया चैटजीपीटी, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत

अभिभावक अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की कर सकेंगे निगरानी

नई दिल्ली,।

ओपनएआई ने 13 से 17 साल की उम्र के किशोर उपयोगकर्ताओं के लिए चैटजीपीटी सेवा शुरू की। कंपनी के मुताबिक इसमें ज्यादा मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और अभिभावकों के नियंत्रण की सुविधा होगी यानी वे अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी कर सकेंगे। यदि चैटजीपीटी के सिस्टम को शक होता है कि उपयोगकर्ता की उम्र 18 साल से कम है, तो यह नया फीचर अपने आप सक्रिय हो जाएगा। कंपनी ने कहा कि ऐसे उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से किशोरों के लिए चैटजीपीटी अनुभव में रखा जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा तय की जा सके।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओपनएआई ने कहा कि किशोरों के लिए चैटजीपीटी फीचर सीखने और सुरक्षा सुविधाओं को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य कक्षा के बाहर सक्रिय और सहयोगात्मक सीखने में मदद करना और एआई के ज्यादा सोच-समझ कर और उम्र के अनुरूप उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में ऐसी सामग्री से सुरक्षा शामिल है, जिसमें खुद को नुकसान पहुंचाने, हिंसा, खतरनाक गतिविधियों या किसी भी तरह की यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का चित्रण हो। ओपनएआई

इंडिया में स्ट्रैटजी और वैश्विक मामलों की प्रमुख ने यह जानकारी दी।

टाटा संस एजीएम स्थगित- जल्द होगा अगली बैठक का ऐलान

मुंबई।

टाटा संस को अभूतपूर्व स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मंगलवार को उसकी सालाना आम बैठक (एजीएम) आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या (कोरम) पूरी न होने के कारण स्थगित की गई। कंपनी के 1917 में स्थापित होने के बाद से यह पहली बार है कि उसकी एजीएम न छूटी है और न ही स्थगित हुई है, जिससे समूह के नेतृत्व को लेकर पहले से बनी अनिश्चितता और बढ़ गई है।

एजीएम स्थगन का मुख्य कारण सर रतन टाटा ट्रस्ट्स (एसआरटीटी) पर महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर द्वारा इस साल की शुरुआत में लगी रोक थी, जिससे इसके नामित निदेशकों की भागीदारी प्रभावित हुई। सूत्रों के अनुसार, टाटा संस का बोर्ड अब जल्द ही, संभवतः एक सप्ताह के भीतर, बैठक बुलाएगा।

इसमें स्थगित हुई एजीएम की नई तारीख तय होगी और मौजूदा कानूनी गतिरोध के समाधान पर वरिष्ठ विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी।

इस संभावित बैठक में चेयरमैन एन.चंद्रशेखरन के 12 अगस्त के पत्र पर भी चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे 20 फरवरी 2027 को अपना दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए खुद को आगे नहीं रखने वाले है। हालांकि, एक सूत्र के मुताबिक, बोर्ड इस बैठक में अपनी पहले की राय दोहरा सकता है कि चंद्रशेखरन को एक और कार्यकाल मिलना चाहिए। मंगलवार को एजीएम के लिए चेयरमैन चंद्रशेखरन और कुछ बोर्ड सदस्य मुंबई में मौजूद थे, जबकि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा सहित कई अन्य निदेशक ऑनलाइन शामिल हुए थे।

परंतु, कोरम पूरा न होने से बैठक शुरू होने के कुछ ही समय बाद स्थगित कर दी गई।

नई स्लाविया के साथ अपनी सेडान विरासत का अगला अध्याय शुरू किया

साथ ही ऑल-न्यू सुपर्ब और ऑक्टेविया आरएस के नए बैच की भारत में घोषणा की

जमशेदपुरः स्कोडा ऑटो इंडिया ने नई स्लाविया का अनावरण किया है, जो आधुनिक तकनीक, सुरक्षा और ड्राइविंग आनंद के साथ सेडान की शाश्वत अपील की सराहना करने वाले ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। भारत के सबसे लोकप्रिय सेडान प्लेटफॉर्म्स में से एक की सफलता पर आधारित, नई स्लाविया यूरोपीय इंजीनियरिंग प्रदान करने की ब्रांड की परंपरा को जारी रखती है, जो ड्राइव करने में आकर्षक, स्वामित्व में व्यावहारिक और भारत के चुनिंदा ग्राहकों के लिए निर्मित है। यह अनावरण स्कोडा की वैश्विक सेडान विरासत के उत्सव का भी प्रतीक था, जिसमें नई स्लाविया ने दो प्रतिष्ठित नेमप्लेट्स- ऑक्टेविया आरएस और ऑल-न्यू सुपर्ब के साथ भारत में अपनी वापसी का केंद्र स्थान लिया।

क्लॉस जेलमर, सीईओ, स्कोडा ऑटो, कहते हैं, ₹भारत हमारे सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक विकास बाजारों में से एक बना हुआ है और यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि जब हम अपने ग्राहकों की बात ध्यान से सुनते हैं, तो स्कोडा ऑटो क्या हासिल कर सकता है। नई स्लाविया इसी दृष्टिकोण पर आगे बढ़ती है। यह एक ऐसे मॉडल को और मजबूत करती है, जो वास्तविक सफलता

की कहानी बन गया है, जिसने ग्राहकों का विश्वास अर्जित किया है। मार्टिन जाह्न, कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग, कहते हैं, ₹स्लाविया का यह अपडेट भारत के लिए हमारी सुस्थापित और सफल सेडान की यात्रा का अगला कदम है। हम आश्वस्त हैं कि रोजमर्रा की व्यावहारिकता, अत्याधुनिक तकनीक और उत्कृष्ट आराम का संयोजन उन नए ग्राहकों को आकर्षित करेगा जो एक आधुनिक, सम्मोहक सेडान की तलाश में हैं। पीयूष अरोड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ, स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया, ने कहा, ₹हमारा ध्यान विश्व स्तर पर मानक उत्पादों को लाने पर बना हुआ है, जो भारतीय ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए इंजीनियर और निर्मित किए गए हैं। आशीष गुप्ता, ब्रांड डायरेक्टर ने कहा, यह सेडान अनुभव को ताजा, प्रासंगिक और आकांक्षी बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, साथ ही भारत में व्यापक दर्शकों के लिए यूरोपीय इंजीनियरिंग और नवाचार को और अधिक सुलभ बना रही है।

दुबई का कमर्शियल रियल एस्टेट बाजार 8.5 फीसदी बढ़कर 65.23 अरब दिरहम हुआ

यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ऑफिस सेगमेंट के बेहतर प्रदर्शन की वजह से हुई

नई दिल्ली,।

दुबई के वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजार ने 2026 की पहली छमाही में मजबूती दिखाई है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद दुबई में वाणिज्यिक संपत्तियों के लेनदेन का मूल्य बढ़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में दुबई के वाणिज्यिक रियल एस्टेट लेनदेन का मूल्य सालाना आधार पर 8.5 फीसदी बढ़कर 65.23 अरब दिरहम हो गया। सौदों की संख्या करीब 13 फीसदी बढ़कर 6,487 हो गई। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ऑफिस सेगमेंट के बेहतर प्रदर्शन की वजह से हुई।

रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में लेनदेन का मूल्य करीब 200 फीसदी बढ़कर 15.81 अरब दिरहम हो गया। ऑफिस सेगमेंट में लेनदेन की संख्या भी सालाना आधार पर 38 फीसदी बढ़कर 2,571 हो गई। वहीं, ऑफिस की औसत कीमत 85 फीसदी बढ़कर 3,202 दिरहम प्रति वर्ग फुट पहुंच गई।

एनारॉक समूह में खुदरा और यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के मुख्य कार्य अधिकारी ने कहा कि यह प्रमुख कारोबारी जिलों और फ्री जोन में सीमित आपूर्ति के बीच ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस की बढ़ती मांग को दर्शाता है। खुदरा संपत्तियों के कारोबार में भी तेज बढ़ोतरी देखी गई। लेनदेन की संख्या सालाना आधार पर 56 फीसदी बढ़कर 853 हो गई।

कैबिनेट : राष्ट्रीय राजमार्ग-22 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को चार लेन करने को मंजूरी

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने बुधवार को बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-22 (एनएच-22) के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को चार लेन मानक में उन्नयन की मंजूरी दी है। इस परियोजना का विकास हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) के तहत किया जाएगा। इसकी कुल पूंजी लागत 3590.73 करोड़ रुपये होगी और इसकी कुल लंबाई 82.578 किलोमीटर है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सड़क परिवहन मंत्रालय की परियोजना को मंजूरी प्रदान की। केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में आज इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह एक प्रमुख फीडर कॉरिडोर के रूप में सोनबरसा स्थित भारत-नेपाल सीमा को एनएच-27 (पूर्व-पश्चिम गलियारा) पर स्थित मुजफ्फरपुर जैसे आर्थिक केंद्रों से जोड़ेगा। परियोजना से मुजफ्फरपुर, मुक्सुदपुर, रुन्नी सैदपुर, थुम्मा, दुमरा, भुतही और सोनबरसा के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को काफी कम करने में मदद मिलती है।

इस परियोजना में यातायात की सुचारू आवाजाही बनाए रखने और सुरक्षित, उच्च गति वाली यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सात प्रमुख पुलों (जिसमें बारहमासी बागमती नदी पर 340 मीटर लंबा एक प्रमुख पुल शामिल है), तीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और दो फ्लाईओवर (1170 मीटर और 270 मीटर) का प्रावधान है।

इस परियोजना से यात्रियों और माल की तेज और सुरक्षित आवाजाही, यात्रा दक्षता में सुधार होगा और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसे 100 किमी प्रति घंटे और 80 किमी प्रति घंटे की औसत गति के डिजाइन किया गया है। इसमें सड़क के मध्य विभाजक में समतल-स्तरीय कोई खुला मार्ग नहीं होगा, जिससे तेज और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी।

एनएच-22 का मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्रीय माल ढुलाई ग्रिड से निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करता है। यह एनएच-31 और एनएच-122 जैसे मौजूदा गलियारों के साथ तालमेल बिठाकर बरौनी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों और गंगा नदी के किनारे स्थित लॉजिस्टिक्स केंद्रों से बेहतर संपर्क स्थापित करता है। साथ ही, यह भिटामोर स्थित निकटवर्ती लैंड पोर्ट के माध्यम से सीमा पार यात्री और माल की आवाजाही को भी बढ़ावा देता है।

यह परियोजना बिहार के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को निर्बाध सम्पर्क प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, उन्नत कॉरिडोर से पीएम गति-शक्ति के पांच आर्थिक केंद्रों (चार औद्योगिक एस्टेट और एक मेगा फूड पार्क), चार सामाजिक केंद्रों (बाबा गरीबनाथ मंदिर, माता जानकी मंदिर, पुनौरा धाम, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी आकांक्षी जिले) और दो लॉजिस्टिक्स केंद्रों (मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन) के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इससे इस पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की तेज आवाजाही सुगम होगी।

इस परियोजना से औसत यात्रा गति में वृद्धि, यात्रा समय में कमी तथा समग्र सड़क सुरक्षा, ईंधन दक्षता और वाहनों की परिचालन लागत में सुधार होगा। इससे क्षेत्रीय आवागमन और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

सुगम्यता से आत्मनिर्भरता तक: उत्तर मध्य रेलवे ने लॉन्च की दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर खास डॉक्यूमेंट्री

बिहान भारत

प्रयागराज: उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे अपने प्रयासों को लेकर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया है। प्रयागराज स्थित एनसीआर मुख्यालय में महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने सुगम्यता से आत्मनिर्भरता तक - उत्तर मध्य रेलवे की दिव्यांगजन सशक्तिकरण यात्राश नामक इस डॉक्यूमेंट्री का अनावरण किया। उत्तर मध्य रेलवे के जनसम्पर्क विभाग द्वारा निर्मित यह डॉक्यूमेंट्री महज सुविधाओं या आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह उन दिव्यांगजनों के सपनों, संघर्षों और सफलता की कहानी बयां करती है, जिनके जीवन को रेलवे ने एक नई दिशा दी है। यह दर्शाती है कि जब व्यवस्था व्यक्ति की कमजोरियों के बजाय उसकी क्षमता को महत्व देती है, तो रोजगार केवल कमाई का साधन नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन जाता है।

आंकड़ों की बात करें तो, एनसीआर के विभिन्न विभागों में कार्यरत 8,256 संविदा कार्मिकों में से करीब 500 दिव्यांगजन हैं, जो एटीवीएम फैसिलिटेटर, स्टेशन एनाउंसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पूछताछ सहायक और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल संचालक जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं। वहीं, रेलवे के नियमित कैडर में भी 784 दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 15 की नियुक्ति हाल ही में वर्ष 2025-26 के दौरान की गई है। इसके अलावा, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 100 दिव्यांग युवा एक्ट अप्रेंटिस के रूप में कौशल प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं।

रोजगार के साथ-साथ रेलवे ने दिव्यांगजनों के लिए स्टेशनों और कार्यालयों को अधिक सुगम बनाने पर भी जोर दिया है। इसके तहत रैम्प, लिफ्ट, सुलभ पार्किंग, लो-हाइट टिकट काउंटर, ब्रेल लिपि के संकेतक, व्हीलचेयर और बैटरी चालित वाहन जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि उन्हें एक बाधारहित वातावरण मिल सके। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के मार्गदर्शन में उठाए गए ये कदम श्सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयासश की भावना को पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री 'सुगम्य भारत अभियान' के प्रति उत्तर मध्य रेलवे की मजबूत प्रतिबद्धता को भी दशार्ती है। इस अनावरण कार्यक्रम में एनसीआर के सभी प्रधान विभागाध्यक्ष , प्रयागराज, झांसी व आगरा मंडल के डीआरएम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में श्रावणी मेला के 20वें दिन 1.29 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही

कोलकाता(बिभा): श्रावणी मेला 2026 के 20वें दिन, अर्थात 18 अगस्त 2026 (मंगलवार) को पूर्व रेलवे ने महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे, सुश्री गीतिका पांडेय के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आसनसोल मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर लगभग 1,29,626 यात्रियों की आवाजाही दर्ज की। स्टेशनवार अनुमानित यात्री संख्या में जसीडीह में 81,665, देवघर में 20,851, बासुकीनाथ में 20,068 तथा बैद्यनाथधाम में 7,042 यात्री शामिल रहे। आसनसोल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री संग्रह मौर्य की प्रत्यक्ष निगरानी में भारी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए सभी मार्गों पर सुचारु ट्रेन परिचालन सुनिश्चित किया गया। जसीडीह में कुल 137 ट्रेनें (107 नियमित और 30 विशेष), देवघर में 48 ट्रेनें (26 नियमित और 22 विशेष), बासुकीनाथ में 24 ट्रेनें (12 नियमित और 12 विशेष) तथा बैद्यनाथधाम में 26 ट्रेनें (20 नियमित और 6 विशेष) संचालित की गईं। दिन की प्रमुख उपलब्धियों में टिकट बिक्री से प्राप्त ?68.15 लाख का कुल राजस्व शामिल रहा। यात्रियों की सुविधा एवं कल्याण के लिए 1,493 लोगों को चिकित्सकीय सहायता प्रदान की गई, जबकि 6 यात्रियों को व्हीलचेयर सहायता उपलब्ध कराई गई। पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री शिबराम माझि ने कहा-ह्रपूर्व रेलवे श्रद्धालुओं को सुरक्षित, आरामदायक और समर्पित रेल सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

धनबाद से कोयम्बत्तूर के बीच चलेगी नई 'अमृत भारत एक्सप्रेस', 22 अगस्त से शुरूआत

हाजीपुर(बिभा): रेलवे ने लंबी दूरी के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धनबाद और कोयम्बत्तूर के बीच एक नई 'अमृत भारत एक्सप्रेस' ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन गोमो, गया, डीडीयू , प्रयागराज छिवकी, जबलपुर और नागपुर के रास्ते चलेगी। धनबाद से इस ट्रेन का नियमित परिचालन 22 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रहा है। इस नई ट्रेन सेवा के शुरू होने से झारखंड और बिहार के यात्रियों को दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु की यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलेगी। रेलवे द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 22363 धनबाद-कोयम्बत्तूर अमृत भारत एक्सप्रेस 22 अगस्त 2026 से सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को धनबाद से शाम 16:10 बजे खुलेगी। यह ट्रेन नेसुब गोमो (16:40), पारसनाथ, हजारीबाग रोड, कोडरमा (18:02), गया (19:30), अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड और डीडीयू (22:40) सहित विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए सोमवार को शाम 18:30 बजे कोयम्बत्तूर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 22364 कोयम्बत्तूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस 25 अगस्त 2026 से सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को कोयम्बत्तूर से सुबह 07:50 बजे प्रस्थान करेगी। वापसी के दौरान यह ट्रेन गुरुवार की सुबह डीडीयू (05:05), सासाराम, गया (08:55), कोडरमा (10:25), पारसनाथ और नेसुब गोमो (11:48) होते हुए दोपहर 13:00 बजे धनबाद पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन बल्लारशाह, वरंगल, विजयवाड़ा, गुडुर, काटपाडी, जोलारपेट्टै और ईरोड स्टेशनों पर भी ठहराव करेगी। इस नई अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। ट्रेन में शयनयान (स्लीपर) श्रेणी के 08, सामान्य द्वितीय श्रेणी (जनरल) के 11, एक पेंट्रीकार और एल.एस.एल.आर.डी के 02 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में यात्री किफायती और आरामदायक सफर का आनंद ले सकेंगे।

संडीला से बरेली के मध्य चला सघन टिकट चेकिंग अभियान, अर्जित हुआ 35,485 रुपये का रेल राजस्व

मुरादाबाद(बिभा)। ।उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि बुधवार को मुख्य वाणिज्य निरीक्षक/हरदोई द्वितीय के नेतृत्व में बालामऊ में 3 चेकिंग कर्मचारियों की एक विशेष टीम द्वारा विभिन्न रेल खंडों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस विशेष चेकिंग टीम में सीआईटी मधु देवी, सीटीटीआई आशुतोष कुमार एवं टीटीआईअनिल कुमार शामिल रहे। टीम द्वारा हरदोई से बरेली के मध्य गाड़ी संख्या (15909), बरेली से शाहजहाँपुर के मध्य गाड़ी संख्या (15098), शाहजहाँपुर से संडीला के मध्य गाड़ी संख्या (13152) गहन चेकिंग की गई। अभियान में 21 बिना टिकट पाए गए यात्री मिले जिनसे 16,090 रुपये किराया वसूल किया गया। इसके अलावा 19,395 रुपये जुमार्ना वसूल किया गया। अतः कुल 35,485 रुपये का रेल राजस्व अर्जित किया गया।

कांग्रेस कार्यसमिति ने छात्र आंदोलन, राम मंदिर चंदा चोरी और चीनी घुसपैठ को लेकर सरकार पर उठाए सवाल

एजेंसी

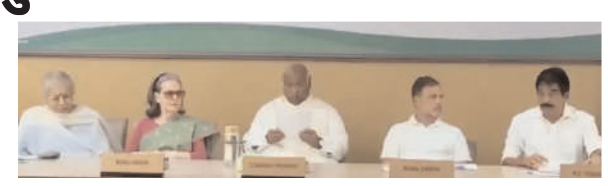

नई दिल्ली। कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) ने केंद्र सरकार से शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। पार्टी ने राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को गांव स्तर तक उठाने का भी फैसला किया। बैठक में अरुणाचल प्रदेश में चीन की कथित घुसपैठ को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया। सीडब्ल्यूसी ने लोकसभा की 543 सीटों को अगले 25 वर्षों तक स्थिर रखने और इसी संख्या के भीतर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग भी दोहराई।

बुधवार को नई दिल्ली में करीब चार घंटे चली सीडब्ल्यूसी की बैठक में छात्र आंदोलन, पेपर लीक, अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ा कथित चंदा घोटाला, चीन के साथ सीमा विवाद, परिसीमन, उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा स्थल के कथित ह्यशुद्धिकरणह्न और संगठन को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 88 सदस्य, स्थायी एवं विशेष आमंत्रित सदस्य तथा चार कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।

बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने महासचिव जयराम रमेश और मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा के साथ संवाददाताओं को बताया कि सीडब्ल्यूसी ने देशभर में छात्रों के बीच बढ़ते असंतोष और बार-बार सामने आ रही प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर चिंता जताई। कांग्रेस ने मानसून सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका की भी सराहना की।

वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी के छात्र संपर्क कार्यक्रम ह्यछात्रों की गूंजह्न को देश के 800 बड़े और छोटे शहरों में आयोजित किया जाएगा। राहुल गांधी इनमें से कई कार्यक्रमों में स्वयं शामिल होंगे। सीडब्ल्यूसी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को छात्रों समेत सभी संबंधित पक्षों से बातचीत कर एक महीने के भीतर शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार का खाका तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्रियों से शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ठोस योजना पेश करने को कहा गया है।

कुष्ठ रोग के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार की पहल, विशेष राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम(एनएलईपी) के तहत केन्द्रीय कुष्ठ डिविजन विशेष कार्याशला की शुरूआत की। इंदौर में आयोजित दो दिवसीय इस कार्यशाला का उद्देश्य कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मजबूत करना, स्वास्थ्य अधिकारियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाना तथा संक्रमण के प्रसार को रोकने की दिशा में अंतिम चरण की कार्रवाई को तेज करना है।

कार्यशाला में 70 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें स्वास्थ्य महानिदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक, उप महानिदेशक (कुष्ठ), केंद्रीय कुष्ठ प्रभाग के अधिकारी, राज्य कुष्ठ अधिकारियों, मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों के जिला कुष्ठ अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, जिला सलाहकारों तथा तकनीकी साझेदार संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल रहे।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कार्यशाला में कुष्ठ रोग की वर्तमान स्थिति और कार्यक्रम के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ-साथ जमीनी स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों और प्रभावी उपायों पर चर्चा की गई। विशेष रूप से रोग की जल्द पहचान, संपर्क में आने वाले लोगों की जांच, समय पर उपचार शुरू करना और उपचार पूरा कराना, दिव्यांगता की रोकथाम तथा निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया। डॉ. सुनील वी. गिट्टे, उप महानिदेशक (कुष्ठ) ने कार्यक्रम के आंकड़ों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि इनके माध्यम से ऐसे जिलों और क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए जहां विशेष निगरानी और लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्होंने कुष्ठ रोग की प्रसार दर को 10,000 आबादी पर 1 से कम करने तथा शुरूआती पहचान, संपर्क जांच, समय पर उपचार और दिव्यांगता रोकथाम को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कोलकाता में द्वितीय रेल सिनर्जी एवं बंगाल एमएसएमई समिट 2026 का भव्य आयोजन: रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर जोर

बिहान भारत

कोलकाता: महानगर के आईटीसी सोनार में 19 अगस्त 2026 को 'दूसरे रेल सिनर्जी एवं बंगाल माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वेंडर कनेक्ट समिट 2026' का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ पश्चिम बंगाल राज्य परिषद द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में पूर्व रेलवे ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस महासम्मेलन का मुख्य विषय आधुनिकीकरण से विस्तार तक: वैगन से ट्रैक, सुरक्षा एवं भारतीय रेलवे में टिकाऊ आपूर्ति-श्रृंखला की गहराई रखा गया था, जिसमें रेलवे के शीर्ष अधिकारियों और स्थानीय उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

सम्मेलन के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि वर्ष 2026 रेलवे के लिए बदलाव और तीव्र प्रगति का एक महत्वपूर्ण वर्ष है। कार्यक्रम में बताया गया कि देश के लगभग 98% ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। साथ ही, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल पूंजीगत परिव्यय ?2.65 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें से विशेष रूप से ?1.17 लाख करोड़ का बजट सिर्फ सुरक्षा पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित निरीक्षण ड्रोन और डिजिटल ट्विन्स जैसी भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकों का भी शानदार प्रदर्शन किया गया।

इस एक दिवसीय कार्यक्रम में स्वदेशी रोलिंग स्टॉक, सुरक्षा प्रणाली 'कवच' की तैनाती और गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पर केंद्रित तीन विशेष सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा लाइव GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) हेल्पडेस्क तथा बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) व बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकों का भी आयोजन हुआ। सम्मेलन में पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, मेट्रो रेलवे कोलकाता और डीएफसीसीआईएल (DFCCIL) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ उद्योग संगठनों और स्थानीय निमार्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक सुश्री गीतिका पांडेय ने घरेलू साझेदारी और एमएसएमई को सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य केवल आधुनिक रेलवे परिसंपत्तियों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि मजबूत घरेलू साझेदारियों के माध्यम से उनका तेजी से विस्तार करना भी है, ताकि एक सुरक्षित और विश्वस्तरीय रेल परिचालन सुनिश्चित किया जा सके। वहीं, पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक डॉ. उदय शंकर झा ने वाणिज्यिक पारदर्शिता के जरिए माल ढुलाई में वृद्धि को गति देने की प्रतिबद्धता दोहराई। पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) श्री शिबराम माझि ने इस समिट को रेलवे और उद्योग जगत की विशेषज्ञता के बीच आत्मनिर्भर नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण सेतु करार दिया।

श्रावणी मेला के दौरान जसीडीह स्टेशन पर यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता: अत्यधिक भीड़ के समय एस्केलेटर का संचालन अस्थायी रूप से बंद

बिहान भारत

आसनसोल: श्रावणी मेला के दौरान जसीडीह रेलवे स्टेशन पर कांवरियों एवं श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए आसनसोल मंडल, पूर्व रेलवे द्वारा यात्री सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए व्यापक यात्री सुविधा एवं भीड़ प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाएं की गई हैं। अत्यधिक भीड़ के समय यात्री सुरक्षा के हित में एस्केलेटर का संचालन अस्थायी रूप से बंद रखा जाता है।

यह देखा गया है कि कुछ यात्री एस्केलेटर के उपयोग के अभ्यस्त नहीं होने के कारण चलते हुए एस्केलेटर पर चढ़ते समय झिझकते हैं। श्रावणी मेला के दौरान अत्यधिक भीड़ के समय ऐसी स्थिति में एस्केलेटर के प्रवेश स्थल पर यात्रियों का जमाव हो सकता है। भीड़ का घनत्व बढ़ने पर मामूली धक्का भी किसी यात्री के चलते हुए एस्केलेटर पर गिरने का कारण बन सकता है, जिससे गंभीर चोट लगने अथवा किसी अप्रिय घटना की संभावना उत्पन्न हो सकती है।

अत्यधिक भीड़ के समय एस्केलेटर का संचालन अस्थायी रूप से बंद रखने का उद्देश्य यात्रियों को असुविधा पहुंचाना नहीं, बल्कि किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकना तथा यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

यात्रियों से अनुरोध है कि ऐसे समय में सीढ़ियों का उपयोग करें तथा सुरक्षित एवं सुगम आवागमन के लिए रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करते हुए सहयोग प्रदान करें।

व्हीलचेयर सहायता सुविधा

श्रावणी मेला के दौरान जसीडीह स्टेशन पर दिव्यांगजन एवं व्हीलचेयर सहायता की आवश्यकता वाले यात्रियों को आवश्यकतानुसार रेलवे कर्मचारियों के समन्वय से भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्वयंसेवकों द्वारा व्हीलचेयर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे सहायता की आवश्यकता वाले यात्रियों को स्टेशन परिसर में सुरक्षित एवं सुगम आवागमन में सुविधा मिल रही है।

अत्यधिक भीड़ के प्रबंधन हेतु चौबीसों घंटे टिकटिंग व्यवस्था

श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए टिकटिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। यात्रियों को सुगम टिकट सुविधा उपलब्ध कराने तथा टिकट केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख तीर्थयात्री स्टेशनों पर एटीवीएम एवं यूटीएस काउंटरों का संचालन चौबीसों घंटे किया जा रहा है।

- जसीडीह: 10 एटीवीएम एवं 20 यूटीएस काउंटर।
- देवघर: 3 एटीवीएम एवं 5 यूटीएस काउंटर।
- बासुकीनाथ: 2 एटीवीएम एवं 4 यूटीएस काउंटर।
- बैद्यनाथधाम: 1 एटीवीएम एवं 3 यूटीएस काउंटर।

इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य यात्रियों को सुविधाजनक टिकटिंग सुविधा उपलब्ध कराना तथा श्रावणी मेला के दौरान निरंतर टिकटिंग सेवाओं के माध्यम से अत्यधिक भीड़ का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। आसनसोल मंडल यात्रियों एवं श्रद्धालुओं से अपील करता है कि उपलब्ध यात्री सुविधाओं का उचित उपयोग करें, सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें तथा सुरक्षित, सुगम एवं सुव्यवस्थित रेल यात्रा सुनिश्चित करने में रेल प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करें।

बिहान भारत की ओर से स्वात्वाधिकारी प्रकाशक एवं मुद्रक **संजय कुमार** के लिए वाटिका अपार्टमेंट,भोसले गली,हरिहर सिंह रोड,बरियातू,रांची-834009(झारखंड) दूरभाष: 7761060594, 7004767601 से प्रकाशित तथा शिवा साई पब्लिकेशन प्रा.लि. (एसएच प्रिंटर प्रा.लि.), काठीटांड रातु, नियर टेंडर बगीचा, एचपी पेट्रोल पंप, रातु, रांची - 835222 झारखंड से मुद्रित। समस्त दीवानी विवाद, न्यायोचित कार्रवाई एवं दंडित परिवादो के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। **संपादक : कविता साहू**(*पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार)। **प्रबंध संपादक : बीरेन्द्र महली** ।
Email-bihanbharat@gmail.com, bihanbharatranchinews@gmail.com